प्रकाशन तिथि : 20 जुलाई, 2021 * वर्ष-30, पृष्ठ संख्या 60, अंक-7

राजस्थान सुजस

समृद्ध किसान – खुशहाल राजस्थान

कृषि विशेषांक

पशुपालन के लिए पदयात्रा

भौगोलिक व सांस्कृतिक विविधता से भरपूर राजस्थान की धरा वास्तव में अजब-अनूठी है। यहां की परंपराएं और जीवन पद्धति हर किसी को सम्मोहित करती है। पशुपालन पद्धति में भी यहां वैशिष्ट्य दिखाई देता है। मारवाड़ में चारे-पानी का संकट होने पर प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में भेड़ों व ऊंटों का समूह मेवाड़ के रास्ते मालवा क्षेत्र के प्रवास पर जाता है। मारवाड़-गोड़वाड़ से जाने वाले भेड़-ऊंटों के साथ इनके पालक भी सर्दी व गर्मी के 8 माह मालवा में प्रवास करते हैं और मानसून पूर्व वे पुनः मूल स्थानों की ओर लौट आते हैं। इनका प्रवास स्थाई और अस्थाई दो प्रकार का होता है। बड़ी संख्या में भेड़-ऊंटों के साथ इनके पालक परिवारों की भी सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा हो जाती है। रात होती है तो सड़क किनारे खेतों या खुले स्थानों पर इनका डेरा लग जाता है और सुबह होते ही फिर से ये उसी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। इस परिवार में भेड़, ऊंट, बकरियां और कुत्तों के साथ-साथ हर उम्र के लोग होते हैं। वयोवृद्ध, अधेड़, युवा, किशोरवय स्त्री-पुरुषों के साथ-साथ शिशु भी इस यात्रा के सहभागी होते हैं। इस दौरान बच्चे ऊंटों के ऊपर तो बड़े-बूढ़े पैदल चलकर ही दिन व्यतीत करते हैं।

कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए चैक पोस्ट व पुलिस चौकियां स्थापित की जाती हैं। पशुपालन विभाग द्वारा पशुओं का टीकाकरण करवाया जाता है।●

-डॉ. कमलेश शर्मा
उप निदेशक (जनसंपर्क)

प्रधान सम्पादक
पुरुषोत्तम शर्मा

सम्पादक
डॉ. लोकेश चन्द्र शर्मा

सह-सम्पादक
गणपत सिंह नारोलिया

उप सम्पादक
आशाराम खटीक

कला
विनोद कुमार शर्मा

राजस्थान सुजस में प्रकाशित सामग्री में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं एवं आंकड़े परिवर्तनशील हैं। आवश्यक नहीं कि शासन उनसे सहमत हो। सुजस में प्रकाशित सामग्री का विभाग किसी भी रूप में उपयोग कर सकेगा।

मुद्रण
पॉपुलर प्रिन्टर्स, जयपुर

सम्पर्क
सम्पादक
राजस्थान सुजस (मासिक)
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
सचिवालय परिसर
जयपुर - 302005
मो. 98292-71189
e-mail :
publication.dipr@rajasthan.gov.in
editorsujas@gmail.com
Website :
www.dipr.rajasthan.gov.in

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान का मासिक

वर्ष : 30 अंक : 07 **जुलाई, 2021**

इस अंक में

सामयिकी

05

साक्षात्कार

14

बातचीत

15

लोक जीवन	02
सम्पादकीय	04
उन्नत बीज...	16
प्रदेश में बुवाई...	17
कृषि मंडियों...	18
सरकारी सहयोग..	20
सोयाबीन बीज....	22
खेती-किसानी	23
फ्री रेंटल स्कीम	24
सहकारी ऋण	26
बूंदी में सब्जी..	29
सात समन्दर...	32
Jodhpur Handicraft	34
Folk Media	36
किचन गार्डन	37
राजस्थान की गौरवमयी...	38
एजुकेशन हब	44
विद्यालय शिक्षा	45
राज्य विश्वविद्यालय	46
चिकित्सा शिक्षा	47
लोकतंत्र	48
योजना	49
सफलता की कहानी	50
लोकरंग	54
लोक संस्कृति	56
प्रतिक्रियाएं	58
कोरोना से बचाव	59
धरोहर	60

फोटो-फीचर 30

राजस्थान सुजस के आगामी अंक के लिए मौलिक, अप्रकाशित सामग्री भिजवायें। कृपया अपने आलेख एवं फोटोग्राफ सम्पादक को e-mail : editorsujas@gmail.com पर अथवा डाक से भेजें।

अजमेर विकास

40

मकराना मार्बल

42

खेल खिलाड़ी

55

सर्ववर्ग कल्याण की प्रतिबद्धता के साथ कृषि विकास को प्राथमिकता

संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रदेश सरकार ने सभी के सहयोग से वैश्विक महामारी कोविड के बेहतर प्रबन्धन और कोरोना टीकाकरण में अग्रणी रहकर विकास में राज्य को गतिमान रखा है। राजस्थान की खुशहाली, सुख, समृद्ध व स्वस्थ जन-जीवन के लिए हर वर्ग के कल्याण को केन्द्र में रखकर राज्य सरकार विकास कार्यों व योजनाओं को धरातल पर मूर्त रूप दे रही है।

कोविड काल की दूसरी लहर का अपेक्षाकृत गांवों में अधिक फैलाव हुआ। इसी दिशा में इस आपदा से लड़ने के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में किए गए बेहतर प्रबंधन से अब स्थिति नियंत्रण में है। तीसरी लहर की संभावित आशंकाओं को देखते हुए प्रदेवासियों को चौकस रहकर कोविड प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना को जीवनशैली, आचरण व व्यवहार में शुमार रखना है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सेनिटेशन व वैक्सीनेशन को प्राथमिकता देना अपरिहार्य है।

कृषि विकास व कृषक कल्याण के लिए राजस्थान सरकार विशेष रूप से प्रयासरत है। राज्य सरकार के महत्त्वपूर्ण निर्णयों ने ही कृषि उपज के सुगम बेचान व भुगतान को सुलभ बनाया। कम ब्याज पर ऋण एवं खाद-बीज व उर्वरकों की सहज उपलब्धता भी प्रदेश में सुनिश्चित की गई है। किसान मित्र ऊर्जा योजना में राज्य सरकार ने कृषि बिजली बिलों में 1000 रुपये प्रतिमाह, अधिकतम 12000 रुपये प्रतिवर्ष का अतिरिक्त अनुदान देकर किसानों को राहत दी है। इन सबसे अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले हमारे अन्नदाता को आर्थिक संबल मिला है।

सुजस का यह अंक कृषि पर आधारित है। कृषि से सम्बन्धित जानकारियों और विकासपरक आलेखों का इसमें समावेश किया गया है। इस अंक से वैभवशाली राजस्थान की रोचक जानकारी देने के लिए राजस्थान की गौरवमयी गाथा का स्तम्भ भी प्रारम्भ किया गया है। इस स्तम्भ में प्रदेश ज्ञानवर्धक, ऐतिहासिक, समाजिक और भौगोलिक तथ्यों को प्रस्तुत करने का प्रयासनिरन्तर किया जायेगा। प्रदेशवासियों और राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप 'सुजस' का व्यापक विस्तार निरन्तर जारी है।

हनुमानगढ़ जिले से आरम्भ की गई इस विस्तृत शृंखला में इस माह से 'सुजस' का जोधपुर, अजमेर, नागौर, बूंदी, करौली, सीकर और डूंगरपुर जिलों को शामिल किया गया है। साथ ही इस बार का यह अंक प्रदेश के निजी विद्यालयों में भी भेजा जा रहा है। राज्य के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और राजकीय विद्यालयों में यह पत्रिका पूर्व से प्रेषित हो रही है। शैक्षणिक संस्थानों से विद्यार्थियों के मध्य इस पत्रिका का वाचन किये जाने का आग्रह किया गया था। अब पुनः अनुरोध है कि माह में एक बार दस से पन्द्रह मिनिट तक 'सुजस' पर चर्चा कराई जाए साथ ही आपके यहाँ हो रहे नवाचारों को हमें प्रेषित करें ताकि उनका प्रकाशन 'सुजस' में किया जा सके।

आदरपूर्वक अभिवादन व शुभकामनाओं के साथ,

(पुरुषोत्तम शर्मा)
प्रधान संपादक

राज्य सरकार के बेहतर प्रबंधन से

पटरी पर आने लगा जनजीवन

– राजीव जैन
वरिष्ठ पत्रकार

राजस्थान में अब कोरोना संक्रमण में गिरावट का दौर जारी है। इसके पीछे मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का बेहतर प्रबंधन रहा है। कोरोना की दूसरी लहर में करीब दो महीने तक कहर के बाद कोरोना की रफ्तार पर अब लगाम लगने लगी है। इसके चलते ही मुख्यमंत्री ने लोगों को छूट भी प्रदान की है। आम आदमी की सामान्य गतिविधियां शुरू हो गई हैं। प्रदेश में बाजार खुल गये हैं तो सरकारी दफ्तरों में भी कामकाज शुरू हो गया है। प्रदेश में यातायात भी चलने लगा है। इस सबमें सरकार ने जो बेहतर प्रबंधन किया उसी का नतीजा है कि प्रदेश में अब जनजीवन पटरी पर आने लगा है। मुख्यमंत्री ने टीकाकरण अभियान को भी गति देकर लोगों को इसके प्रति खासा जागरूक किया है।

प्रदेश में कोरोना महामारी पर काबू पाने के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कुशल प्रबंधन की रणनीति अपनाई। उन्होंने प्रदेश की जनता की जान बचाने के लिए हरसंभव उपाय अपनाये। कोरोना के संकट के दौरान राज्य सरकार हर जरूरतमंद के साथ खड़ी रही। सरकार की तरफ से लागू किये गये लॉकडाउन में अब लगातार छूट दी जा रही है। मुख्यमंत्री स्वयं अपने स्तर पर हालात की लगातार समीक्षा कर रहे हैं और जनता को जितनी ज्यादा राहत प्रदान की जा सके उसके लिए लगातार काम में जुटे हुए हैं। उनके निर्देश पर ही लगातार व्यावसायिक और अन्य गतिविधियों पर लगाई गई पाबंदियों में कमी की जा रही है। इस छूट का दायरा बढ़ने से अब जनजीवन सामान्य होता जा रहा है। विवाह और सामाजिक आयोजनों में भी ढील दी जा रही है। ग्रामीण इलाकों में रोजगार के लिए सबसे बड़ा साधन माने जाने वाले मनरेगा के काम भी समय पर शुरू हो गये। इससे गरीब तबके के लोगों को मजदूरी भी मिलने लग गई। सरकार ने संवेदनशीलता अपनाते हुए लॉकडाउन के दौरान भी निर्माण कामों की छूट दी थी ताकि मजदूर वर्ग के रोजगार पर कोई विपरीत असर नहीं पड़े। आम आदमी की जरूरतों को देखते हुए और अर्थव्यवस्था सुचारु हो सके, इसके लिए भी सरकार लगातार प्रयास करने में जुटी हुई है। इन सबसे ही आम आदमी राहत महसूस करने लगा है।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का साफ कहना है कि जनता कोविड प्रोटॉकोल के अनुरूप ही व्यवहार करें, क्योंकि अभी कोरोना का खतरा खत्म नहीं हुआ है। विशेषज्ञ भी तीसरी लहर की आशंका जता रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार अपील भी कर रहे हैं कि कोविड अनुकूल व्यवहार अपनाने से ही हम तीसरी लहर के घातक दौर से बच सकते हैं। विशेषज्ञों की आशंका के चलते ही सरकार ने तीसरी लहर से बचने के तमाम इंतजाम भी शुरू कर दिये हैं। इससे ही आम जनता में सरकार के प्रति भरोसा भी कायम हो रहा है। सरकार ने जरूरी दवाएं व इंजेक्शन के साथ ऑक्सीजन, आईसीयू, वेंटिलेटर, बेड आदि इंतजाम अभी से करने के निर्देश चिकित्सा महकमे को दे दिये हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद ही चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा अपने विभाग के अफसरों और डॉक्टरों के साथ तमाम इंतजाम करने में

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का साफ कहना है कि जनता कोविड प्रोटॉकोल के अनुरूप ही व्यवहार करें क्योंकि अभी कोरोना का खतरा खत्म नहीं हुआ है। विशेषज्ञ भी तीसरी लहर की आशंका जता रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार अपील भी कर रहे हैं कि कोविड अनुकूल व्यवहार अपनाने से ही हम तीसरी लहर के घातक दौर से बच सकते हैं।

जुटे हुए हैं। तीसरी लहर में बच्चों के ज्यादा प्रभावित होने के अंदेशे के चलते जिला और उपखंड स्तर तक बच्चों के अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। सरकार भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए कोई कमी नहीं छोड़ रही है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान प्रबंधन के मामले में अव्वल रहा है। कोरोना गाइडलाइन की पालना में भी राजस्थान अग्रणी प्रदेश रहा है। राजस्थान में ही सबसे पहले मास्क की अनिवार्यता लागू की गई। इसके लिए व्यापक स्तर पर जनजागरूकता अभियान भी चलाए गये। इसका काफी असर रहा और कोरोना की भयावहता को कम करने में मदद भी मिली।

राज्य सरकार के कुशल प्रबंधन का ही नतीजा रहा कि कोरोना के सबसे खतरनाक डेल्टा वेरिएंट के कारण बनी भयावह स्थिति को समय रहते संभाल लिया गया। राजस्थान कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 6 मई को देश के टॉप संक्रमित प्रदेशों में आठवें स्थान पर था। मुख्यमंत्री के बेहतर प्रबंधन की बदौलत राजस्थान अब टॉप-20 की सूची से बाहर निकल चुका है। प्रदेश में मई में हालात बहुत ही खराब हो चुके थे, उस समय प्रदेश में एक दिन में 18 हजार से ज्यादा मरीज मिलने लग गये थे। सरकार ने उस समय लॉकडाउन और कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने पर जोर दिया। इसके बाद जून में मरीजों की संख्या में कमी आती गई और जुलाई में तो अब सौ से भी कम मरीज मिल रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद परिवारों को संकट से उबारने के लिए राज्य सरकार ने संवेदनशील फैसले लेकर उन्हें राहत पहुंचाने की दिशा में कारगर कदम भी उठाये। प्रदेश के 33 लाख निराश्रित, असहाय और जरूरतमंद परिवारों को एक हजार रुपए की सहायता राशि देने के आदेश भी मुख्यमंत्री ने जारी किये। इसके तहत सरकार ने 330 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। यह सहायता राशि ऐसे परिवारों को मिली जिन्हें सामाजिक सुरक्षा योजना की किसी सहायता का लाभ नहीं मिल रहा था। सरकार ने कोरोना के विषम हालातों में आर्थिक समस्या का सामना करने वाले कलाकारों को संबल देने के लिए 5 हजार रुपए की एकमुश्त सहायता देने का भी निर्णय किया है। मुख्यमंत्री श्री गहलोत के इस संवेदनशील फैसले से प्रदेश के करीब दो हजार से ज्यादा कलाकारों को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण से अनाथ हुए बच्चों के जीवनयापन और उनकी शिक्षा-दीक्षा के लिए भी एक पैकेज बनाया है। इससे इन अनाथ बच्चों के जीवनयापन में कोई परेशानी नहीं आएगी। सरकार के निर्देश पर अब प्रदेश में सर्वे करवाकर अनाथ हुए बच्चों का पता लगाया जा रहा है।

कोरोना की पहली और दूसरी लहर में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान प्रबंधन के मामले में अव्वल रहा है। कोरोना गाइडलाइन की पालना में भी राजस्थान अग्रणी प्रदेश रहा है। राजस्थान में ही सबसे पहले मास्क की अनिवार्यता लागू की गई।

प्रदेश की जनता को भविष्य में कोरोना के खतरे से बचाव के लिए टीकाकरण की आवश्यकता को देखते हुए मुख्यमंत्री इस पर लगातार फोकस कर रहे हैं। केंद्र से टीकों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास में जुटे हुए हैं। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री से भी गुहार लगाई है और प्रदेश में उसकी जरूरत के हिसाब से पूरे टीके समय पर मुहैया कराने को कहा है। मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि केंद्र इस मामले में बगैर भेदभाव के टीके उपलब्ध कराये। चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा भी लगातार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के संपर्क में हैं और टीकों की उपलब्धता के प्रयास में जुटे हुए हैं। श्री शर्मा का कहना है कि राजस्थान में प्रतिदिन 15 लाख टीके लगाने की क्षमता सरकार ने बना रखी है। राजस्थान टीकाकरण में भी देश में अग्रणी प्रदेशों में शुमार है। मई और जून में तो देश के बड़े प्रदेशों में राजस्थान अग्रणी राज्य बना हुआ था। सरकार का मानना है कि केंद्र समय पर टीके उपलब्ध कराता रहा तो इस मामले में भी राजस्थान अव्वल रहेगा।

ऊर्जा कीमतों को कम करने के लिए कटिबद्ध

राज्य सरकार ऊर्जा खरीद की कीमतों को कम करने के लिए कटिबद्ध है। इस हेतु सस्ती कीमत वाले संयंत्रों से मेरिट ऑर्डर बनाकर बिजली की अधिकतम खरीद की जा रही है ताकि बिजली की औसत दर कम की जा सके। इसी क्रम में बिजली एक्सचेंज से सस्ती बिजली मिलने पर महंगे संयंत्रों को बन्द किया जा सकता है। राजस्थान विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा विद्युत मांग की पूर्ति हेतु दीर्घावधि के लिए विद्युत क्रय के लिए केन्द्रीय, राजकीय व निजी विद्युत उत्पादनकर्ताओं के साथ करार किए गए हैं।

राज्य सरकार के विशेष प्रयासों के कारण बिजली की औसत खरीद दर में 22 पैसे की गिरावट भी आई है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में बिजली की औसत खरीद दर 4 रुपये 77 पैसे थी जो कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में घटकर 4 रुपये 55 पैसे रह गई है।

विकास परियोजनाओं को गति

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का मानना है कि शहरी क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे के विकास, सौन्दर्यीकरण, ड्रेनेज एवं सीवरेज कार्यों से जुड़ी परियोजनाओं को समय पर पूरा होना आवश्यक है ताकि शहरवासियों को जलभराव और ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिल सके। स्थानीय लोगों की आवश्यकता और जनप्रतिनिधियों के सुझावों के अनुरूप कार्यों को योजनाबद्ध रूप से पूरा किया जाना आवश्यक है।

ग्रामीण इलाकों में रोजगार के लिए सबसे बड़ा साधन माने जाने वाले मनरेगा के काम भी समय पर शुरू हो गये। इससे गरीब तबके के लोगों को मजदूरी भी मिलने लग गई। सरकार ने संवेदनशीलता अपनाते हुए लॉकडाउन के दौरान भी निर्माण कामों की छूट दी थी ताकि मजदूर वर्ग के रोजगार पर कोई विपरीत असर नहीं पड़े। आम आदमी की जरूरतों को देखते हुए और अर्थव्यवस्था सुचारु हो सके, इसके लिए भी सरकार लगातार प्रयास करने में जुटी हुई है। इन सबसे ही आम आदमी राहत महसूस करने लगा है।

जोधपुर में करीब 309 करोड़ रुपए के सीवरेज प्रोजेक्ट के तहत विभिन्न कार्य किए जाएंगे। इसमें नगर निगम उत्तर एवं दक्षिण के करीब 60 किलोमीटर क्षेत्र में पुरानी एवं जर्जर सीवर लाइनों को सुधारने एवं बदलने का कार्य किया जाएगा। साथ ही जोधपुर विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम उत्तर एवं दक्षिण के करीब 250 किलोमीटर क्षेत्र में सीवर लाइनें डाली जाएंगी। करीब 40 हजार मकानों को सीवर कनेक्शन से जोड़ा जाएगा। प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार की जा रही है, जिसे आरयूआईडीपी को भेजा जाएगा।

करीब 37.5 करोड़ की लागत से बालसमंद-नागादड़ी ओवरफ्लो नाला निर्माण कार्य से फूलबाग, चतुरावता बेरा, सूरपुरा आदि क्षेत्रों में जलभराव की समस्या का समाधान होगा। इसकी डीपीआर नगर निगम (उत्तर) जोधपुर द्वारा तैयार की जा रही है।

अमृत योजना के पहले चरण में सूरपुरा बांध एम्यूजमेंट पार्क में करीब 2 करोड़ 7 लाख रुपए की लागत से पाथ-वे, ओपन जिम, ग्रीन स्पेस उपकरण एवं झूले इत्यादि कार्य किए गए हैं। द्वितीय चरण में फूड कोर्ट, एक्टिविटी एरिया, जॉगिंग-ट्रैक आदि के कार्य प्रस्तावित हैं। जिसकी अनुमानित लागत 20 करोड़ रुपए हैं।

गंगलाव तालाब सौन्दर्यीकरण एवं पुनरुद्धार के लिए नगर निगम जोधपुर (उत्तर)

द्वारा डीपीआर तैयार की गई है। यहां उद्यान, वॉक-वे, ओपन एयर जिम, फाउंटेन एवं पार्किंग का कार्य प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ने इस परियोजना में सघन पौधरोपण तथा पानी में जलकुंभी ना उगे, इस बात की आवश्यकता जताई है।

रजिस्टर्ड सहमति धारक भी हो सकेंगे खनन पट्टा एवं कारी लाइसेंस

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने निजी खातेदारी भूमि में खातेदार के रजिस्टर्ड सहमति धारक को भी खनन पट्टा एवं कारी लाइसेंस का आवंटन करने के लिए राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2021-22 के बजट में इस सम्बन्ध में घोषणा की थी। इस बजट घोषणा की क्रियान्विति के दृष्टिगत मुख्यमंत्री ने खातेदार को उसकी खातेदारी भूमि में एक से चार हैक्टेयर तक के खनन पट्टे अथवा कारी लाइसेंस डेडरेंट या कारी रेंट के पांच गुना निश्चित प्रीमियम पर तथा डेडरेंट अथवा कारी रेंट के दस गुना निश्चित प्रीमियम पर खातेदार के रजिस्टर्ड सहमति धारक को आवेदन पत्र के माध्यम से आवंटित करने के लिए राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली-2017 में संशोधन की अधिसूचना के प्रारूप को मंजूरी दी है।

मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए 5 करोड़

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा को प्रोक्टर एंड गैम्बर (जिलेट इंडिया लिमिटेड) की ओर से मुख्यमंत्री कोरोना रिलीफ फंड के लिए 5 करोड़ रुपए की सहायता राशि का चैक सौंपा गया है।

चिकित्सा मंत्री ने कंपनी का आभार व्यक्त करते हुए कोरोना महामारी के दौर में विभिन्न संस्थाओं को सहयोग करने की अपील की है जिससे कि मेडिकल सुविधाओं को सुचारु रखने में मदद मिल सकें। भामाशाहों व अन्य दानदाताओं को भी आगे आने की जरूरत है जिससे कि कोरोना महामारी की संभावित तीसरी लहर का सामना करने के लिए राज्य सरकार अधिक संसाधन जुटा सकें। हालांकि सरकार की ओर से तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं लेकिन भामाशाहों की मदद से अतिरिक्त सेवाओं को जुटाने का अवसर प्राप्त होता है।

ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स जिलों में भेजे जायेंगे

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा को यूएनएफपीए (यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड) की ओर से 400 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स सहित 40 हजार एन-95 व 2 लाख थ्री-लेयर सर्जिकल मास्क भेंट किए गए। इन्हें प्रदेश के पांच जिलों के चिकित्सा संस्थानों में भेजा जा रहा है।

प्राप्त कंसंट्रेटर्स को मांग व आवश्यकतानुसार सम्बन्धित जिलों के चिकित्सा संस्थानों में भेजा जा रहा है। 400 कंसंट्रेटर्स में से 80 कंसंट्रेटर्स अजमेर के जेएलएन मेडिकल कॉलेज में भेजा जाएगा जबकि करौली, नगर, तिजारा, उदयपुरवाटी, किशनगढ़बास, नदबई, सरवाड़, टांटोटी, कादेड़ा, बघेरा के चिकित्सा संस्थानों में 25-25 कंसंट्रेटर्स, सापला और जूनिया में 20-20 तथा सावर में 30 कंसंट्रेटर्स उपलब्ध कराए जाएंगे। डॉ. शर्मा को विजन स्प्रिंग संस्थान की ओर से 10 लीटर प्रति मिनिट की क्षमता वाले 150 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी भेंट किए गए।

पायनियर बनकर उभर रहा राजस्थान

राज्य सरकार के निरन्तर प्रयासों से राजस्थान स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में पायनियर बनकर उभर रहा है। देश के दूसरे राज्यों के लोग भी यहां की चिकित्सा सुविधाओं का लाभ लेने राजस्थान आ रहे हैं। यह प्रदेश के लिए गर्व की बात है। प्रदेश में चिकित्सा सुविधाएं और भी बेहतर हों, इसके लिए राजधानी से लेकर गांव-ढाणी तक मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर को लगातार सुदृढ़ किया जा रहा है।

वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रदेश के 11 जिलों के 17 चिकित्सालयों में आईसीयू, नवजात गहन चिकित्सा इकाई (एनआईसीयू), शिशु गहन चिकित्सा इकाई (पीआईसीयू) तथा मदर केयर यूनिट का शिलान्यास मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने किया। करीब 94 करोड़ 10 लाख रुपये की लागत से होने वाले कार्यों से 531 बैड की बढ़ोतरी होगी। इसमें आईसीयू के 270, एनआईसीयू के 208, पीआईसीयू के 33 बैड तथा मदर केयर यूनिट के 20 बैड शामिल हैं।

मुख्यमंत्री का मानना था कि प्रदेश ने समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर कोरोना की पहली एवं दूसरी लहर का मुकाबला किया। भीलवाड़ा और रामगंज मॉडल को देश-दुनिया में पहचान मिली और दूसरे राज्यों ने भी इसे अपनाया। दूसरी घातक लहर में

ऑक्सीजन एवं दवाओं की आपूर्ति तथा बैड्स को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ा। इससे सबक लेते हुए राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेजों से लेकर सीएचसी-पीएचसी स्तर तक चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत किया है ताकि तीसरी लहर आए तो इस महामारी के मुकाबले में किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

राजस्थान ऐसा प्रदेश है जो सभी जिलों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में अधिकाधिक मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए यूपीए सरकार के समय योजना बनी थी। राजस्थान ने इस दिशा में पूरी तैयारी के साथ आवश्यक शर्तों को पूरा किया जिसके चलते 30 जिलों में सरकारी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की ओर राज्य के कदम बढ़ सकें। शेष तीन जिलों में भी सरकारी मेडिकल कॉलेज स्वीकृत कराने के लिए राज्य सरकार प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कोरोना से जान गंवाने वाले परिवारों को सम्बल देने के लिए मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना लागू की है। इससे अनाथ बच्चों एवं विधवा महिलाओं के जीवन की राह आसान हो सकेगी। इसके साथ ही प्रदेशवासियों को इलाज के भारी-भरकम खर्च से मुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई है। सभी जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, एनजीओ आदि को हर पात्र परिवार को इस योजना से जोड़ने में भागीदारी निभानी होगी।

दूसरी लहर के कटु अनुभवों से सबक लेते हुए राज्य सरकार ऑक्सीजन उत्पादन एवं शिशु चिकित्सा इकाइयों में बढ़ोतरी की योजना पर तेजी से काम कर रही है। राज्य में एक हजार मीट्रिक टन ऑक्सीजन उत्पादन की क्षमता हासिल करने की दिशा में राज्य अग्रसर है।

प्रदेश में मार्च, 2020 में ऑक्सीजन बैड 5,448 थे। इनकी संख्या बढ़ाकर 13 हजार की जा रही है। साथ ही, आईसीयू के 1125 बैड थे जिनकी संख्या अब 2622 हो जाएगी। इसी तरह एनआईसीयू बैड की संख्या 475 से बढ़ाकर 1554, पीआईसीयू बैड की 164 से 1048 और एसएनसीयू बैड की संख्या 222 से बढ़ाकर 308 की जा रही है।

पिछले डेढ़ वर्ष में राज्य सरकार ने पूरे समर्पण भाव और मुस्तैदी के साथ कोरोना का प्रबंधन किया है। संक्रामक रोगों के बढ़ते

प्रभाव को देखते हुए भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप सुविधाएं विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

प्रदेश में प्रतिदिन 1.50 लाख कोविड टेस्ट करने की क्षमता विकसित कर ली गई है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में जीनोम सिक्वेंसिंग की सुविधा प्रारम्भ हो गई है। विभिन्न मेडिकल कॉलेजों और सीएचसी में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने का कार्य 15 अगस्त तक पूरा होना संभावित है।

सुदृढ़ चिकित्सा व्यवस्था के नये प्रयास

जोधपुर–उम्मेद अस्पताल में 460 लाख से 30 बैड एनआईसीयू, मथुरादास माथुर अस्पताल में 650 लाख से 30 बैड आईसीयू एवं 920 लाख से 60 बैड एनआईसीयूए महात्मा गांधी अस्पताल में 650 लाख से 30 बैड आईसीयू।

अजमेर–जवाहर लाल नेहरू अस्पताल में 750 लाख से 50 बैड आईसीयू।

झालावाड़–एसआरजी अस्पताल में 450 लाख से 20 बैड आईसीयू और जनाना अस्पताल में 307 लाख से 20 बैड एनआईसीयू एवं 250 लाख से 23 बैड पीआईसीयू।

कोटा– जे के लोन अस्पताल में 579 लाख से 36 बैड एनआईसीयू एवं 250 लाख से 20 बैड मदर केयर यूनिट।

चूरू–डी.बी.एच. अस्पताल में 456 लाख से 20 बैड आईसीयू और 167 लाख से 10 बैड एनआईसीयू।

बाड़मेर–जिला अस्पताल में 456 लाख से 20 बैड आईसीयू और 167 लाख से 10 बैड एनआईसीयू।

सीकर–एस.के. जिला अस्पताल में 456 लाख से 20 बैड आईसीयू एवं मातृ शिशु अस्पताल में 200 लाख से 12 बैड एनआईसीयू।

भीलवाड़ा–महात्मा गांधी जिला अस्पताल में 456 लाख से 20 बैड आईसीयू एवं मातृ-शिशु अस्पताल में 167 लाख से 10 बैड एनआईसीयू।

डूंगरपुर–हरिदेव जोशी अस्पताल में 456 लाख से 20 बैड आईसीयू और 167 लाख से 10 बैड एनआईसीयू।

पाली–राजकीय बांगड़ अस्पताल में 456 लाख से 20 बैड आईसीयू और 167 लाख से 10 बैड एनआईसीयू।

भरतपुर–राजबहादुर मेमोरियल अस्पताल में 456 लाख से 20 बैड आईसीयू और जनाना अस्पताल में 167 लाख से 10 बैड पीआईसीयू।

आकाशीय बिजली दुर्घटना में प्रत्येक घायल को 2 लाख रुपए की सहायता

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के सात जिलों में हुई आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं में प्रत्येक घायल को 2 लाख रुपए एवं मृतक आश्रितों को 5 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ मानसून की तैयारियों के संबंध में मुख्यमंत्री ने समय रहते समीक्षा बैठक की।

मुख्यमंत्री की मंशानुरूप प्रदेश में समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर कोरोना की पहली एवं दूसरी लहर का मुकाबला किया गया। भीलवाड़ा और रामगंज मॉडल को देश-दुनिया में पहचान मिली और दूसरे राज्यों ने भी इसे अपनाया। दूसरी घातक लहर में ऑक्सीजन एवं दवाओं की आपूर्ति तथा बैड्स को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ा। इससे सबक लेते हुए सरकार मेडिकल कॉलेजों से लेकर सीएचसी-पीएचसी स्तर तक चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत कर रही है ताकि तीसरी लहर आए तो इस महामारी के मुकाबले में किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

ई-व्हीकल्स की खरीद पर राज्य सरकार करेगी स्टेट जीएसटी का पुनर्भरण

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से ई-व्हीकल्स के संचालन को प्रोत्साहन देने के लिए इन वाहनों के क्रेताओं को स्टेट जीएसटी के पुनर्भरण तथा बैटरी की क्षमता अनुसार हर वाहन की बिक्री पर अनुदान देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। साथ ही इसके लिए 40 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को भी स्वीकृति दी है।

प्रस्ताव के अनुसार, ई-व्हीकल्स की बिक्री पर राज्य में वर्तमान में देय 2.5 प्रतिशत जीएसटी का पुनर्भरण किया जा सकेगा। साथ ही दुपहिया वाहनों की बिक्री पर 2 किलोवाट से 5 किलोवाट की बैटरी क्षमता के अनुरूप 5 हजार से 10 हजार रुपए तक तथा तिपहिया वाहनों की बिक्री पर 3 किलोवाट से 5 किलोवाट बैटरी क्षमता के अनुरूप 10 हजार से 20 हजार रुपए तक प्रति वाहन अनुदान दिया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2021-22 के बजट में ई-व्हीकल्स की खरीद को प्रोत्साहन देने के लिए एसजीएसटी के पुनर्भरण तथा एकमुश्त अनुदान देने की घोषणा की थी। श्री गहलोत के इस निर्णय से राज्य में ई-वाहनों की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा जिससे प्रदूषण की रोकथाम एवं पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी।

निर्माण मजदूरों के पंजीकरण के लिए चल रहा है विशेष अभियान

प्रदेश में निर्माण मजदूरों के पंजीकरण के लिए श्रम विभाग द्वारा 15 जुलाई से 15 अगस्त तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है ताकि मजदूरों को केंद्र तथा राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लाभांवित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने इसके लिए निर्देश जारी किए हैं।

श्री गहलोत मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित श्रम संहिताओं के प्रारूप पर विमर्श के लिए आयोजित विशेष बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि निर्माण मजूदरों के पंजीकरण के लिए अभियान के दौरान श्रम विभाग के अधिकारी निर्माण स्थलों तथा मजदूरों के इकट्ठा होने की जगहों (चौखटी) पर जाकर ऑन-स्पॉट रजिस्ट्रेशन करें। इससे अधिकाधिक निर्माण मजदूर भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (बीओसीडब्ल्यू) के तहत संचालित योजनाओं का लाभ ले सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने निर्माण मजदूरों के परिवारों की ओर से बीओसीडब्ल्यू के पास विभिन्न योजनाओं से संबंधित लंबित आवेदनों के जल्द निस्तारण पर जोर दिया। इन योजनाओं के संचालन के लिए प्रदेशभर में निर्माणकर्ताओं से उपकर संग्रहण (सेस कलेक्शन) के काम को गति दी जानी आवश्यक है। बीओसीडब्ल्यू के प्रावधानों के तहत बड़े भवन एवं अन्य संरचना निर्माणकर्ताओं से निर्माण कार्य की लागत के एक प्रतिशत सेस की वसूली के लिए विशेष अभियान चलाने, निर्माण कार्यों की जीआईएस मैपिंग करवाने तथा विभाग के स्तर पर एमेनेस्टी योजना तैयार करने के की आवश्यकता जताई गयी।

मुख्यमंत्री ने श्रम विभाग को प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, पटरी-रेहड़ी पर सामान बेचने वाले, खोमचे वाले, स्ट्रीट वेंडर्स, रिक्शा चालक आदि असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए बीओसीडब्ल्यू की तर्ज पर अलग बोर्ड गठित करने के प्रस्ताव का परीक्षण करने के निर्देश दिए हैं।

श्रम राज्यमंत्री श्री टीकाराम जूली के निर्देशों के अनुसार बीओसीडब्ल्यू में सेस वसूली के लिए आवश्यक है कि श्रम विभाग भवन निर्माणों की जीआईएस मैपिंग का काम शहरी विकास तथा स्वायत्त शासन विभागों के साथ समन्वय कर जल्द पूरा करें। गैर-संगठित क्षेत्र के कर्मकारों के बोर्ड के गठन के बाद राज्य सरकार इन लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं भी बना सकती है।

3000 करोड़ रुपये के कर्मचारी कल्याण कोष के गठन को मंजूरी

राज्य सरकार के कार्यरत और सेवानिवृत्त कार्मिकों के हितार्थ विभिन्न योजनाओं के संचालन के लिए 3 हजार करोड़ रुपये की राशि से कर्मचारी कल्याण कोष का गठन होगा। इस कोष से कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा, आवास, उच्च अध्ययन तथा वाहन ऋण एवं बच्चों के लिए छात्रवृत्ति सहित कर्मचारी कल्याण के लिए अन्य योजनाएं संचालित की जाएंगी।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य बजट 2021-22 की बजट घोषणा की क्रियान्विति के क्रम में कर्मचारी कल्याण कोष के गठन के लिए वित्त विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। प्रस्ताव के अनुसार इस कोष का संचालन निदेशक, बीमा विभाग द्वारा किया जाएगा। इसके लिए नया बजट मद खोला जाएगा तथा कोष के तहत योजनाओं की स्वीकृति की प्रक्रिया पृथक् से निर्धारित की जाएगी।

श्री गहलोत द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार इस कोष के माध्यम से राज्य में सेवारत तथा सेवानिवृत्त कर्मियों के कल्याण के लिए जिन नई योजनाओं को लागू किया जाएगा इनमें राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) में अंशदान, आवास ऋण, उच्च अध्ययन के लिए ऋण, व्यक्तिगत ऋण, वाहन ऋण, कामकाजी महिलाओं के लिए कार्यालयों में क्रेच तथा अल्प वेतन भोगी कार्मिकों के बच्चों के लिए प्रतिभावान छात्रवृत्ति योजना शामिल हैं। कर्मचारी कल्याण कोष का उद्देश्य कर्मचारी कल्याण और सामाजिक सहायता के साथ-साथ राजकार्य का बेहतर निष्पादन भी है। ऐसे में राज्य सरकार इस कोष के माध्यम से कर्मचारी कल्याण के लिए भविष्य में आवश्यकतानुसार अन्य अतिरिक्त सेवाएं भी सशुल्क अथवा निःशुल्क उपलब्ध करवा सकती है।

उल्लेखनीय है कि राज्य कार्मिकों एवं पेंशनरों को राजकीय अस्पतालों के साथ-साथ अनुमोदित निजी चिकित्सालयों में बेहतर एवं गुणवत्तापूर्वक विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं कैशलेस उपलब्ध करवाने के लिए आरजीएचएस योजना शुरू की गई है। इस योजना के लिए राज्य सरकार के अंशदान का वित्तपोषण निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इस कोष से किया जा सकेगा।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के

कर्मचारियों को इस कोष के माध्यम से 15 लाख रुपये की अधिकतम सीमा तक 10 वर्ष तक की अवधि के लिए आवास ऋण; पुत्र-पुत्री अथवा आश्रित के लिए देश-विदेश में उच्च अध्ययन के लिए 5 लाख रुपये की अधिकतम सीमा तक 5 वर्ष तक की अवधि के लिए उच्च अध्ययन ऋण; आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 3 लाख रुपये की अधिकतम सीमा तक 5 वर्ष तक की अवधि के लिए व्यक्तिगत ऋण और 5 लाख रुपये की अधिकतम सीमा तक 5 वर्ष तक की अवधि के लिए वाहन ऋण आदि उपलब्ध कराए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी : केंद्र के समान ही राज्य कर्मचारियों को भी दिया महंगाई भत्ता

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप ही राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। अब राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को 1 जुलाई, 2021 से 28 प्रतिशत महंगाई भत्ता देय होगा। पूर्व में राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को 17 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा था।

श्री गहलोत के इस निर्णय का लाभ लगभग 15 लाख अधिकारियों-कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को मिलेगा। बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ राज्य कर्मचारियों के अतिरिक्त कार्य प्रभारित कर्मचारियों, पंचायत समिति तथा जिला परिषद् के कर्मचारियों को भी देय होगा।

उल्लेखनीय है कि कोविड की परिस्थितियों के कारण केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 1 जनवरी, 2020 से 30 जून, 2021 तक स्थगित किया था। केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते की घोषणा किए जाने के साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की दर में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का निर्णय किया है। कोविड की कठिन परिस्थितियों के बावजूद राज्य कर्मचारियों को संबल देने के लिए राज्य सरकार इस बढ़ोतरी पर सालाना करीब 4000 करोड़ रूपए वहन करेगी।

किसी भी देश-प्रदेश की तरक्की उसकी युवा शक्ति के कौशल पर निर्भर : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के अनुसार किसी भी देश और प्रदेश की तरक्की उसकी युवा शक्ति के कौशल और दक्षता पर निर्भर करती है। हमारे युवाओं ने पूरी दुनिया में अपनी योग्यता का लोहा मनवाया है। राज्य सरकार तकनीक एवं नवाचारों के साथ युवाओं को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न विधाओं में दक्ष बनाने का हरसंभव प्रयास कर रही है। प्रदेश में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए कई संस्थानों की स्थापना के साथ ही महत्त्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं।

स्मार्ट सिटी मिशन : राजस्थान देश में प्रथम

राजस्थान ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 36 राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों की ऑनलाइन रैंकिंग में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत जनअपेक्षाओं के अनुरूप जनप्रतिनिधियों से विचार-विमर्श एवं स्मार्ट सिटी के दिशा-निर्देशों के अनुरूप जयपुर, उदयपुर, अजमेर एवं कोटा शहरों में नए जनोपयोगी कार्यों को सम्मिलित किया गया है। कार्यों के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए सीपीएम-पीईआरटी आधारित एक्शन प्लान बनाया जाकर प्रभावी मॉनिटरिंग करते हुये कार्यों का संपादन किया गया है। कोविड-19 काल के दौरान भी विकास कार्यों की गति को बनाये रखा गया जिसके फलस्वरूप नागरिकों को इच्छित लाभ मिल सका एवं राजस्थान देश में प्रथम स्थान प्राप्त कर सका है।

किसान मित्र ऊर्जा योजना कृषि क्षेत्र के लिए बड़ा संबल

राज्य सरकार हमेशा किसानों के हितों के प्रति संवेदनशील रही है। कोरोना महामारी के संकट के समय वित्तीय वर्ष 2020-21 में जहां पूरी अर्थव्यवस्था में गिरावट दर्ज की गई, तब कृषि क्षेत्र ने विपरीत परिस्थितियों में देश की अर्थव्यवस्था को संबल दिया है। इस दौर में देश के किसानों ने अपनी मेहनत से सकल घरेलू उत्पाद की दर को सहारा प्रदान किया है।

'मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना' का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 17 जुलाई को किया। राज्य सरकार की 'मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना' का मुख्य उद्देश्य किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करना ही है। इस योजना पर सालाना 1450 करोड़ रुपए

का अतिरिक्त व्यय होगा। इसमें कृषि उपभोक्ताओं को बिजली दरों पर प्रति माह 1 हजार रुपए अथवा अधिकतम 12 हजार रुपए प्रतिवर्ष अनुदान मिलेगा। इस योजना के शुरु होने पर प्रदेश में लघु एवं मध्यम वर्ग के किसानों के लिए कृषि बिजली लगभग निःशुल्क हो जाएगी।

प्रदेश में कृषि विद्युत की दर 5 रुपए 55 पैसे प्रति यूनिट होने के बावजूद किसानों को 90 पैसे प्रति यूनिट बिजली दी जा रही है। शेष 4 रुपए 65 पैसे प्रति यूनिट का अनुदान राज्य सरकार वहन कर रही है। कृषि विद्युत दरों पर अनुदान के कारण राज्य सरकार पर 16 हजार करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का आर्थिक भार आ रहा है। अब किसानों के कल्याण के लिए 1450 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार भी वहन किया जाएगा।

राज्य सरकार किसानों को अच्छी गुणवत्ता की बिजली उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्प है। बिजली के वितरण के साथ-साथ उत्पादन और प्रसारण पर भी राज्य में फोकस किया जा रहा है। पूरे राजस्थान में बिजली के नये ग्रिड, लाइनें तथा सब-स्टेशन विकसित कर इसके नेटवर्क को सुदृढ़ किया जा रहा है। कृषि क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति के लिए नई कम्पनी का गठन इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। इसके माध्यम से किसानों को उनकी मांग के अनुरूप पर्याप्त ऊर्जा उपलब्ध कराना संभव हो सकेगा। सभी जिलों में किसानों को दिन के समय बिजली देने का लक्ष्य जल्द पूरा कर लिया जाएगा।

राजस्थान में सौर ऊर्जा नीति, 2019 एवं पवन ऊर्जा नीति, 2019 के माध्यम से अक्षय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्ष 2025 तक 30 हजार मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य की दिशा में हम लगातार प्रयासरत हैं। कुसुम योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसके तहत खेतों में सोलर पैनल लगाने पर लागत का 30 प्रतिशत खर्च राज्य सरकार, 30 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा वहन करने तथा शेष 40 प्रतिशत के लिए किसान को ऋण दिलवाने का प्रावधान है। किसान उत्पादित ऊर्जा के उपयोग के बाद शेष ऊर्जा सरकार को बेचकर ऋण की किस्तें चुका सकता है। अधिक से अधिक किसानों को योजना का लाभ लेना चाहिए।

राज्य सरकार ने किसानों के हित में कई कदम उठाए हैं। किसान मित्र ऊर्जा योजना इसका सजीव उदाहरण है। इस योजना के तहत कृषि उपभोक्ताओं को 1,000 रूपए प्रतिमाह तक के बिजली बिल होने पर कोई भी राशि नहीं चुकानी पड़ेगी। किसानों के लिए द्वैमासिक बिलिंग व्यवस्था लागू होगी। किसी भी माह में बिल राशि 1,000 रुपए से कम होने पर अनुदान की शेष राशि का लाभ उसी वित्तीय वर्ष के आगामी माह में देय होगा।●

अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

#राजस्थान_सतर्क_है

बिजली बिल में देकर अतिरिक्त अनुदान
किसानों का बढ़ाया मान

मुख्यमंत्री
किसान मित्र ऊर्जा योजना

कृषि बिजली बिल में
₹1000 प्रतिमाह अधिकतम ₹12000 प्रतिवर्ष
अतिरिक्त अनुदान

लाभार्थी:- समस्त सामान्य श्रेणी ग्रामीण मीटर्ड एवं फ्लैट रेट कृषि उपभोक्ता

"किसान कल्याण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। इसी भावना के साथ हमारी सरकार ने किसानों को समृद्ध और खुशहाल बनाने के लिए कई महत्त्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इसी कड़ी में अब हम **"मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना"** शुरू करने जा रहे हैं। इसका लाभ समस्त सामान्य श्रेणी ग्रामीण मीटर्ड एवं फ्लैट रेट कृषि उपभोक्ताओं को मिलेगा। इसमें राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 1450 करोड़ रूपये का अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा।"

अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री

राजस्थान संवाद

ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार

किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध राज्य सरकार

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य सरकार का किसान की खुशहाली पर विशेष फोकस रहा है। कर्ज माफी से लेकर समय पर खाद-बीज और फसल खराबे का बीमा क्लेम मुहैया कराकर राहत पहुंचाई है। कोविड की विपरीत परिस्थितियों में आर्थिक संबल प्रदान करने के प्रयास किये गये हैं। कृषि की आधुनिक तकनीक किसानों के खेतों तक पहुंचाकर समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करने के सतत प्रयास जारी हैं।

कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग मंत्री श्री लालचंद कटारिया का कृषि विकास पर दृष्टिकोण।

जनसम्पर्क अधिकारी सोहनलाल द्वारा लिए गए साक्षात्कार के महत्त्वपूर्ण अंश

फसल बीमा योजना में कितनी राहत पहुंचाई?

हर पात्र काश्तकार को समय पर क्लेम दिलाना सुनिश्चित किया जा रहा है। खरीफ-2020 तक के लगभग सभी बीमा क्लेम किसानों को वितरित कर गत रबी फसल के क्लेम बांटने की प्रक्रिया जारी है। ढाई साल में 69 लाख फसल पॉलिसियों के विरुद्ध किसानों को 11 हजार 418 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम दिया गया।

तारबन्दी योजना का क्रियान्वयन कैसा रहा?

नीलगाय व आवारा पशुओं से फसलों को बचाने के लिए यह योजना काफी मददगार साबित हो रही है। योजना में बदलाव कर व्यावहारिक बनाने हेतु किसानों की संख्या 5 से घटाकर 3 और क्षेत्रफल को 3 हैक्टेयर किया गया है। किसानों ने वर्ष 2019-20 में 3 लाख 30 हजार 480 मीटर तथा 2020-21 में 5 लाख 19 हजार 495 मीटर तारबंदी की गयी। इस वर्ष इसके लक्ष्य को बढ़ाकर 6 लाख 90 हजार मीटर किया गया है।

कृषि आदानों के लिए क्या प्रयास किए गए?

मांग अनुसार यूरिया व डीएपी सहित समस्त उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। वर्ष 2020-21 में सहकारी एवं निजी क्षेत्र के आदान विक्रेताओं के माध्यम से 21 लाख 58 हजार मीट्रिक टन यूरिया एवं 7 लाख 39 हजार मीट्रिक टन डीएपी सहित अन्य उर्वरकों की मांग अनुसार आपूर्ति कराई गई है। इस वर्ष खरीफ सीजन में अप्रैल से जून तक 3 लाख 23 हजार मीट्रिक टन यूरिया एवं 1 लाख 47 हजार मीट्रिक टन डीएपी की आपूर्ति राज्य में कराई गई है एवं निरन्तर आपूर्ति जारी है।

बजट घोषणा के तहत गत वित्तीय वर्ष में 60 हजार 58 मीट्रिक टन यूरिया एवं 20 हजार मीट्रिक टन डीएपी भण्डारण करवाकर उपयोग किया जा चुका है। इस वर्ष दो लाख मीट्रिक टन यूरिया तथा एक लाख मीट्रिक टन डीएपी का अग्रिम भण्डारण कराया जा रहा है।

इस वर्ष वर्तमान खरीफ के लिए आकलित मांग 8 लाख 80 हजार क्विंटल के विरुद्ध 9 लाख 48 हजार क्विंटल बीजों की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। राज्य में सोयाबीन फसल के क्षेत्रफल में संभावित वृद्धि को देखते हुये कुल आकलित मांग 2 लाख 30 हजार क्विंटल के विरुद्ध 2 लाख 44 हजार क्विंटल बीजों की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। साथ ही खरीफ 2020 के दौरान ''मुख्यमंत्री बीज स्वावलम्बन योजना'' द्वारा उत्पादित 38 हजार क्विंटल बीज कृषकों को उपलब्ध करवाया गया।

टिड्डियों पर नियंत्रण किस तरह से किया?

कृषि विभाग एवं टिड्डी चेतावनी संगठन ने किसानों के साथ मिलकर दो सालों में करीब साढ़े दस लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सफलतापूर्वक टिड्डी नियंत्रण किया। सर्वे वाहनों, ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर, वाटर टैंकर एवं फायर ब्रिगेड का उपयोग कर कीटनाशी रसायन का छिड़काव कर प्रभावी नियंत्रण किया गया। गत दो वर्षों में क्रमशः 771.78 लाख व 631.91 लाख तथा कृषि विभाग द्वारा 740.31 लाख रुपए व्यय किये गये।

रिक्त पदों पर भर्ती के क्या प्रयास किए गए?

कृषि विभाग में विभिन्न संवर्गों में 2376 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा चुकी है तथा 2754 पदों पर भर्ती की कार्यवाही भर्ती एजेन्सी के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

कोविड में किसानों के लिए क्या प्रयास किए?

कोविड काल में लॉकडाउन के बीच खेती से जुड़े उपकरणों के निर्बाध आवागमन की व्यवस्था की गई ताकि किसानों को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं उठानी पड़े। साथ ही काश्तकारों को आर्थिक संबल देने के लिए टैफे कम्पनी के माध्यम से फ्री रेन्टल स्कीम शुरू की गई। यह योजना अभी जारी है।

सोलर पम्प योजना में सरकार कितने किसानों को लाभान्वित करने जा रही है?

प्रदेश सोलर पम्प स्थापना में देश में अग्रणी है। अब तक 55 हजार से अधिक सोलर पम्प अनुदान पर स्थापित किए जा चुके हैं। वर्तमान में प्रधानमंत्री कुसुम योजना के पहले चरण में वर्ष 2020-21 से 25 हजार सोलर पम्प स्थापना का कार्य किया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष के लिए 50 हजार सोलर पम्प लगाने का लक्ष्य रखा गया है।●

किसान की खुशहाली के अभिनव प्रयास

कृषि विभाग ने योजनाओं का बेहतर ढंग से क्रियान्वयन कर किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए नवाचार किए हैं। किसानों की मांग के अनुसार योजनाओं के लक्ष्य में इजाफा किया गया है। कृषि प्रसंस्करण को प्रोत्साहित कर किसान की आय में वृद्धि के साथ रोजगार सृजन का प्रयास किया जा रहा है।

कृषि, विभाग के प्रमुख सचिव श्री भास्कर ए. सावंत से बातचीत
संयुक्त निदेशक, (जनसम्पर्क) अरुण जोशी द्वारा की गई बातचीत के महत्त्वपूर्ण अंश

फसल बीमा योजना में क्या नवाचार किए हैं?

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को ज्यादा पारदर्शी बनाकर प्रभावित काश्तकार को त्वरित लाभ पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। साथ ही खरीफ-2021 से Land Record Integration कर दोहरे बीमा को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। कृषकों के खातों में डीबीटी के माध्यम से बीमा क्लेम का हस्तान्तरण किया जा रहा है। फसल उपज के आकलन के लिये फसल कटाई प्रयोग एप के माध्यम से ऑनलाइन क्या किए जा रहे हैं, जिससे मानवीय त्रुटि को कम किया जा सके।

कृषि आदानों की गुणवत्ता के लिए क्या कदम उठाए?

खरीफ एवं रबी मौसम से पहले विशेष गुणवत्ता नियंत्रण अभियान चलाकर उर्वरक एवं बीजों के नमूने आहरित किए जाते हैं। किसानों के स्तर पर उर्वरकों व बीजों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रयोगशालाओं में उनके द्वारा लाये गये नमूनों की नि:शुल्क जांच की सुविधा उपलब्ध है।

'इज ऑफ डूइंग फॉर्मिंग' की प्रगति क्या है?

इसके लिए 'राज किसान साथी' पोर्टल विकसित किया गया है जो एकल खिड़की के रूप में कृषि, उद्यानिकी, कृषि विपणन, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन, राजस्थान राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था आदि द्वारा क्रियान्वित सेवाओं के लिये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसमें आवेदन से लेकर दस्तावेजों की जांच, भौतिक सत्यापन, प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति एवं भुगतान तक की समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन की जा रही है। इसके तहत कुल 144 मॉड्यूल्स विकसित किए जाएंगे। इनमें से गत वर्ष 46 मॉड्यूल्स तैयार किये जा चुके हैं। इस साल के लिए 50 मॉड्यूल्स चिह्नित कर प्राथमिकता तय की गई है। इसमें आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।

फार्म पोण्ड का लक्ष्य क्या है?

वर्ष 2021-22 के लिए 7 हजार 111 पोण्ड निर्माण का भौतिक लक्ष्य रखते हुए 53.20 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया है। आगामी सालों में किसानों की मांग के अनुसार इनके लक्ष्यों को और बढ़ाया जायेगा।

मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

राज्य में क्षारीय भूमि सुधार कार्यक्रम के तहत किसानों को जिप्सम की आवश्यक मात्रा (जीआर वेल्यू) के आधार पर जिप्सम 50 एवं हरी खाद के लिए ढेंचा बीज 60 किग्रा. प्रति हैक्टेयर 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2020-21 में सॉयल हैल्थ कार्ड योजना के तहत 6432 किसानों को लाभान्वित किया गया।

सूक्ष्म सिंचाई योजना के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

कृषि क्षेत्र में सिंचाई जल का कुशलतम उपयोग आवश्यक है। आधुनिक सूक्ष्म सिंचाई तकनीक यथा फव्वारा व बूंद-बूंद सिंचाई से सिंचाई दक्षता को प्रभावी रूप से बढ़ाया जाना सम्भव हुआ है। उद्यान विभाग की ओर से सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों पर किसानों को 50 से 70 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। राज्य में आधुनिक सिंचाई तकनीक को वृहत रूप पर क्रियान्वित करने के लिए मुख्यमंत्री ने वर्ष 2021-22 के बजट में आगामी तीन वर्षों के दौरान 4 लाख 30 हजार किसानों को लाभान्वित करने का निर्णय लिया है। वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य में 1 लाख 51 हजार 424 हैक्टेयर में सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र स्थापित करने की वार्षिक कार्ययोजना तैयार की गई है।

कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण एवं निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

मुख्यमंत्री ने दिसम्बर, 2019 में राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति जारी की। राज्य सरकार की इस महत्त्वाकांक्षी योजना के तहत मिल रहे आकर्षक अनुदान, प्रोत्साहन, सहायता तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में भू-रूपान्तरण जैसी सहूलियतों की वजह से किसान एवं उद्यमी इसमें खासी रुचि दिखा रहे हैं। वेयर हाउस एवं कैटल फीड उद्यमों के साथ तिलहन, दलहन, मसाले, मूंगफली, कपास, दूध एवं अनाज प्रोसेसिंग की इकाइयां स्थापित की जा रही हैं। कोविड की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद प्रदेश में 617 एग्रो प्रोजेक्ट स्थापित हो रहे हैं जिन पर 1255 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इसके लिए राज्य सरकार ने 119 करोड़ रुपए की सब्सिडी मंजूर की है। राज्य में 88 किसानों को 39 करोड़ 60 लाख रुपए की सब्सिडी स्वीकृत की गई है जिन्होंने 89 करोड़ रुपए का निवेश किया है।●

उन्नत बीज-खुशहाल किसान

डॉ. ओमप्रकाश, आईएएस
अध्यक्ष, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

बीज खेती में काम आने वाला महत्त्वपूर्ण आदान है जिसकी गुणवत्ता पर खेती की सम्पूर्ण पैदावार निर्भर करती है। राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (राजसीड्स) विगत वर्षों से अपने इस मूल उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बीज उत्पादन, विधायन व सुदृढ़ विपणन तंत्र के माध्यम से बीजों के विपणन की गतिविधियों से लगातार उन्नति की ओर अग्रसर है।

राज्य बीज निगम द्वारा विभिन्न फसलों के उच्च गुणवत्ता के आधार पर प्रमाणित बीजों का उत्पादन फार्मों तथा हिस्साधारी एवं पंजीकृत उत्पादकों के खेतों पर किया जाता है। राज्य सरकार की ओर से 7 कृषि फार्म लीज पर बीज उत्पादन के लिए राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड को आवंटित हैं। फार्मों से प्रतिवर्ष लगभग 10 हजार क्विंटल बीज उत्पादन किया जा रहा है। खरीफ-2020 में कुल प्रमाणित बीज उत्पादन 82 हजार 93 क्विंटल एवं रबी 2020-21 में फसलों का प्रमाणित बीज उत्पादन 3 लाख 75 हजार 30 क्विंटल हुआ। खरीफ में बाजरा, मक्का, ज्वार, मूंगफली, मूंग, मोठ, उड़द, सोयाबीन, तिल, अरण्डी एवं ग्वार आदि तथा रबी में सरसों, तारामीरा, अलसी, गेहूं, जौ, चना एवं मैथी का बीजोत्पादन कार्यक्रम किया जाता है।

बीजों की गुणवत्ता को उच्चतम स्तर पर बनाये रखने के विशेष प्रयास किये हैं। आधार व प्रमाणित बीजों की आनुवंशिक शुद्धता जांचने के लिए निगम द्वारा स्वयं के स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं। इसके लिए उदयपुर इकाई पर बीज परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। इसके साथ ही खरीफ फसलों के प्रमाणित बीजों का वर्ष 2015 से एवं रबी फसलों के बीजों का जीओटी परीक्षण रबी 2020-21 से प्रारम्भ किया गया है जिससे किसानों को बेहतर गुणवत्ता के बीज उपलब्ध करवाना संभव हुआ है। ये प्रयास भविष्य में भी जारी रहेंगे।

भण्डारण क्षमता 10.21 लाख क्विंटल

निगम द्वारा उत्पादित विभिन्न फसलों के बीजों का विधायन राज्य में स्थापित राजसीड्स के विधायन केन्द्र पर सभी तकनीकी मापदण्डों को ध्यान में रखते हुए आधुनिक मशीनों के द्वारा किया जाता है। राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की कुल भण्डारण क्षमता 10.21 लाख क्विंटल व कुल विधायन क्षमता 20.74 लाख क्विंटल प्रतिवर्ष है।

निगम द्वारा 25-30 फीसदी बीज की आपूर्ति

राजसीड्स वैज्ञानिकों द्वारा विकसित नवीनतम किस्मों का उत्पादित उच्च गुणवत्ता युक्त प्रमाणित बीज किसानों तक विभिन्न माध्यमों से उपलब्ध करवाया जाता है। खरीफ-2020 में विभिन्न फसलों का 1,14,440 क्विंटल एवं रबी 2020-21 में विभिन्न फसलों का 2,15,055 क्विंटल बीजों का विपणन किया गया। राज्य की कुल बीज आवश्यकता की 25 से 30 प्रतिशत आपूर्ति निगम द्वारा की जा रही है।

मण्डियों में दुकानें-गोदाम आवंटित होंगे

राज्य में किसानों को उच्च गुणवत्ता का बीज सही समय पर एवं सुगमतापूर्वक उपलब्ध करवाने के लिए राज्य की समस्त कृषि उपज मण्डियों में 200 नि:शुल्क भूखण्ड, दुकानें एवं गोदाम आवंटित करवाने की कार्यवाही जारी है। कृषि क्षेत्र में राज्य के किसानों को दिये जाने वाले सभी परिलाभों को सुगम व पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से ''राज किसान साथी'' पोर्टल बनाया गया है। राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमों से कृषकों को सुगमता से जोड़ने के उद्देश्य से बीज उत्पादक कृषकों के पंजीकरण एवं बीज उत्पादन कार्यक्रम के आवंटन का कार्य इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा प्रारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम के द्वितीय चरण में लाभार्थी कृषकों को उन्नत बीजों के वितरण का कार्य भी इस पोर्टल के माध्यम सें किये जाने की योजना है।

निगम सतत रूप से राज्य के किसानों के हित में कार्य कर रहा है और बेहतर गुणवत्ता के बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सदैव किसानों की सेवा करता रहेगा।●

प्रदेश में बुवाई क्षेत्र में बढ़ोतरी, उत्पादन में भी वृद्धि

– राजेन्द्र सिंह मनोहर
कृषि अनुसंधान अधिकारी

कृषि के मानसून पर निर्भर होने के बावजूद विभागीय प्रयासों, उन्नत किस्म के बीजों, उर्वरकों के उपयोग, पौध संरक्षण उपायों एवं कृषि की नवीन तकनीक के उपयोग से राज्य में वास्तविक बोए जाने वाले क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि होने के साथ ही उत्पादन में भी निरन्तर वृद्धि हो रही है।

राज्य में कृषि मानसून पर निर्भर है। खरीफ फसलों का उत्पादन एवं उत्पादकता केवल वर्षा की मात्रा पर ही निर्भर नहीं करती अपितु यह वर्षा के उपयुक्त समयान्तराल में उचित वितरण, पर्याप्तता तथा तीव्रता पर भी निर्भर करती है।

राज्य में प्रथम योजना से अब तक की अवधि के दौरान वास्तविक बोए जाने वाले क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वास्तविक बोया जाने वाला क्षेत्रफल प्रथम योजना में 106 लाख हैक्टेयर था, जो बढ़कर वर्ष 2013-14 में 183 लाख हैक्टेयर के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया। उपज क्षेत्रफल भी प्रथम योजना में मात्र 7 लाख हैक्टेयर था वह भी बढ़कर वर्ष 2013-14 एवं 2016-17 में 79 लाख हैक्टेयर हो गया। इसी प्रकार फसलीय सघनता भी प्रथम योजना में 107 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2013-14 एवं 2016-17 में 143 प्रतिशत के स्तर पर आ गई।

देश में स्थान	फसल	उत्पादन प्रतिशत
प्रथम	बाजरा	43.78
	सरसों	47.93
	ग्वार	83.61
	मोटा अनाज	15.57
द्वितीय	तिलहन	22.57
	दलहन	11.86
	मूंगफली	15.60
तृतीय	चना	11.20
	सोयाबीन	11.63
चतुर्थ	खाद्यान्न	7.18
पंचम	ज्वार	7.80
	गेहूं	10.56

राजस्थान में फसल उत्पादन
(वर्ष 2019-20)

खरीफ	क्षेत्रफल (लाख हैक्टेयर)	उत्पादन (लाख टन)
अनाज	59.94	91.25
दलहन	38.39	17.76
खाद्यान्न	28.33	89.01
तिलहन	23.17	25.21
गन्ना	0.04	3.26
कपास	7.60	27.88
ग्वार	28.41	12.85
अन्य	4.71	
कुल बोया गया क्षेत्र	162.27	

रबी	क्षेत्रफल (लाख हैक्टेयर)	उत्पादन (लाख टन)
अनाज	37.98	149.57
दलहन	24.97	27.19
खाद्यान्न	62.95	176.75
तिलहन	34.81	47.54
अन्य	14.84	
कुल बोया गया क्षेत्र	115.60	

राज्य में खरीफ के अन्तर्गत 90 प्रतिशत क्षेत्र में बारानी फसलें बोई जाती है, जो पूर्णत: वर्षा पर निर्भर हैं। यदि राज्य में मानसून का आगमन समय पर एवं सामान्य होता है तो अच्छी पैदावार प्राप्त होती है। फिर भी विभागीय प्रयासों, उन्नत किस्म के बीजों, उर्वरकों के उपयोग, पौध संरक्षण उपायों एवं कृषि की नवीन तकनीक के उपयोग से राज्य में उत्पादन में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

राज्य में खरीफ की फसलें सामान्यतया 140 से 160 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में बोई जाती हैं। इनमें से 60 से 65 प्रतिशत खाद्यान्न, 10 से 15 प्रतिशत तिलहन, 3 प्रतिशत कपास एवं गन्ना तथा शेष 20 से 25 प्रतिशत क्षेत्र में अन्य फसलें बोई जाती हैं। खरीफ में मुख्यत: ज्वार, बाजरा, मक्का, मोठ, मूंग, उड़द, चंवला, तिल, मूंगफली, सोयाबीन, कपास एवं ग्वार की खेती की जाती है।

राज्य में रबी फसलों की बुवाई सामान्यतया 70 से 95 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में की जाती है जिसमें लगभग 60-65 लाख हैक्टेयर क्षेत्र सिंचित है। रबी मौसम में मुख्यत: गेहूं, जौ, चना, राई-सरसों, धनियां, ज़ीरा एवं मैथी की बुवाई की जाती है।

खरीफ दलहनों की भांति रबी दलहन फसलें भी मुख्य रूप से बारानी क्षेत्रों में बोई जाती हैं। चने का करीब 15-20 प्रतिशत क्षेत्र ही सिंचित है। इसलिए चने का अच्छा उत्पादन सर्दी की वर्षा (मावठ) पर निर्भर है। रबी तिलहनों में मुख्य रूप से सरसों की खेती की जाती है। राज्य में सरसों की वर्ष 2000-01 में औसत उपज 929 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर थी जो वर्ष 2010-11 में 1,560 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर हो गई है। राष्ट्रीय स्तर पर सरसों के उत्पादन में राज्य का प्रमुख स्थान है।●

कृषि मंडियों से बदली किसान की तकदीर

कृषि उपज मंडियों की स्थापना से किसान अपने उत्पाद नकद में बेचकर जीवन की राह को आसान करने लगा है।

राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का सफर

राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने अपनी स्थापना सन् 1974 से ही कृषि विपणन के लिए विकास के मानक तय करने के लिए शुरू कर दिए थे। बोर्ड की स्थापना के साथ ही संभाग, जिला और तहसील स्तर पर मंडियां खुलने लगीं जहां किसान अपने उत्पाद लाकर बेचने लगा। यदि यह कहा जाए तो अधिक उपयुक्त होगा कि कृषि मंडियों की स्थापना से किसान को अधिक मजबूती मिली। प्रदेश में अभी 247 मंडियां हैं जिनमें किसान अपने उत्पादन लाकर बेचते हैं।

उद्योगपति बना किसान

किसान अब तक अपनी फसल को मंडी तक लाकर बेचने लगा था लेकिन राज्य सरकार के प्रयासों से उसे प्रोसेसिंग करना सिखाया गया। किसान द्वारा फसल को प्रोसेसिंग कर बेचने से उसकी आमद में वृद्धि हुई। इस आमद के इजाफे से उसकी सोच में भी काफी हद तक बदलाव देखा जाने लगा है।

कृषि प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए कृषि विपणन बोर्ड की ओर से पंचायत समिति स्तर पर किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इनमें किसान प्रशिक्षण लेकर अपनी यूनिट लगाकर अपनी तकदीर को बदल सकता है। इसके लिए विभिन्न बैंकों से ऋण भी दिया जाता है।

राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना

आजादी के सात से अधिक दशक गुजरने के बाद भी किसान का नाम जेहन में आते ही पलक झपकते ही एक तस्वीर उभरती है जिसमें धोती कमीज, बनियान पहने एक संघर्षशील व्यक्ति घनघोर विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करता हुआ दिखाई पड़ता है। आमतौर पर देखा जाता है कि कई बार किसान की अकाल मौत हो जाती है। किसान की मौत होने पर 'राजीव गांधी कृषक साथी सहायता' योजना 2019 लागू की गई है। इसके तहत किसान मजदूर की खेती अथवा विपणन कार्य करते समय होने वाली दुर्घटनाओं में मृत्यु, अंग-भंग होने की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। किसान की मृत्यु होने पर दो लाख और अंग-भंग होने की स्थिति में पांच से पचास हजार रुपए तक की सहायता का प्रावधान किया गया है। इसी तरह रीढ़ की हड्डी टूटने, सिर पर चोट लगने से कोमा में जाने पर 50 हजार, एक अंगुली कटने पर 5 हजार, दो अंगुली कटने पर दस हजार और चार अंगुली कटने पर बीस हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

-डॉ. धर्मवीर चंदेल
वरिष्ठ पत्रकार

किसान कलेवा योजना

किसान अपनी उपज को अलसुबह ही खेत खलिहान से लेकर मंडी पहुंचता है। मंडी समितियों में काम करने वाले पल्लेदार भी तड़के ही घरों से मंडियों की ओर रुख करते हैं। मंडियों में पौ फटने से बहुत पहले ही काम शुरू हो जाता है।

राज्य सरकार ने 'किसान कलेवा योजना' शुरू की है। इसमें राज्य की कृषि मंडी समिति प्रांगण में कृषि जिंसों को लेकर आने वाले किसानों और मंडी समितियों में काम करने वाले पंजीकृत हम्मालों, पल्लेदारों को पांच रुपए में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है।

इससे दूर-दराज से आने वाले किसान भाइयों और मंडी में काम करने वाले मजदूरों को राहत मिलती है।

श्रमिक कल्याण योजना

यह महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम है। यदि यह कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस योजना ने राज्य सरकार के साथ ही मंडी समितियों का मानवीय और संवेदनशील चेहरा दिखाया है। यह योजना राज्य की कृषि उपज मंडी समितियों में कार्यरत अनुज्ञप्तिधारी हम्मालों, पल्लेदार और तुलाईकारों की सहायता के लिए लागू की गई है। इस योजना के तहत महिला को प्रसूति के समय 45 दिन की मजदूरी के समतुल्य सहायता राशि, पितृत्व अवकाश के रूप में 15 दिन की मजदूरी के समतुल्य सहायता राशि प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त विवाह के समय सहायता, छात्रवृत्ति, मेधावी छात्र पुरस्कार योजना, चिकित्सा सहायता राशि सहित अन्य मदद भी दी जाती है जिससे किसान की राह अधिक सुगम हो सके।

ई-भुगतान प्रोत्साहन योजना

कृषि उपज के व्यापार में अधिक से अधिक डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए यह योजना लागू की गई है। कृषि जिंसों के प्लेटफॉर्म के माध्यम से विक्रय के पश्चात् जारी वित्तीय पर्ची के आधार पर आकलित मंडी शुल्क का 25 प्रतिशत भाग किसानों को हस्तांतरित तथा व्यापारियों द्वारा भुगतान करने पर बैंक द्वारा ई-भुगतान करने पर बैंक द्वारा लगाए गए शुल्क का पुनर्भरण मंडी समितियां करती हैं।

'सावित्री बाई फूले कृषक सशक्तीकरण योजना' महिलाओं को ई-भुगतान के लिए आकर्षित करने के लिए लागू की गई है। इस योजना के तहत वर्ष 2019-20 से महिला कृषकों को सहायता राशि प्रदान करके उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जा रहा है।

विशिष्ट मंडियों के निर्माण का सुखद परिणाम

प्रदेश के जिन स्थानों पर अच्छी फसल होती है वहां पर उस फसल की विशिष्ट मंडी बनाकर राज्य सरकार ने किसानों को उपहार प्रदान किया है। मसलन-पुष्कर, अजमेर में फूल अधिक पैदा होते हैं। ऐसे में अजमेर और पुष्कर में फूल मंडी की स्थापना की गई है। इसी तरह चौमूं में आंवला, मेड़तासिटी, जोधपुर, बाड़मेर में जीरा मंडी की स्थापना की गई। टोंक में मिर्ची, अलवर में प्याज, श्रीगंगानगर में किन्नू, कपासन में अजवाइन, भवानीमंडी में संतरा, सवाईमाधोपुर में अमरूद, रामगंज मंडी में धनिया मंडी की स्थापना कर किसानों के जीवन को अधिक सुखद बनाने की सरकार की कोशिश है। बहरहाल, यह कहा जा सकता है कि मंडी समितियों के अस्तित्व में आने से किसान की अनेक परेशानियां दूर हुई हैं। किसान ने धीरे ही सही लेकिन उन्नति के नए सोपान चढ़ना शुरू कर दिया है।●

सरकारी सहयोग मिला तो किसान बने उद्यमी

प्रदेश में लग रहे हैं 617 एग्रो प्रोजेक्ट, 1255 करोड़ रुपए का होगा निवेश

खेतों में अनाज उपजाने वाले किसान अब अपने उत्पादों की मशीनों से ग्रेडिंग-शॉर्टिंग कर रहे हैं। तरह-तरह के खाने के प्रोडक्ट बनाकर देश-विदेश में बेच रहे हैं। खुद आर्थिक आत्मनिर्भर बनकर इलाके के लोगों को रोजगार देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उद्यमशीलता को सरकारी सहयोग मिला तो खेतों में वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की चेन बन गई। यह संभव हो रहा है मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की दूरदर्शी और मजबूत 'राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति-2019' से।

राज्य सरकार का पूरा प्रयास है कि प्रदेश में पैदा होने वाला हर उत्पाद प्रोसेस होकर ही बाहर बिकने जाए। इससे उत्पाद का मूल्य संवर्द्धन होगा जिसका सीधा फायदा काश्तकारों को मिलेगा। उन्हें उपज का उचित मूल्य मिलने से उनकी आय में इजाफा हो सकेगा। यह नीति रोजगार सृजन के साथ किसानों एवं युवाओं को उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

भास्कर ए. सावंत
प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग

राज्य सरकार की इस महत्त्वाकांक्षी योजना के तहत मिल रहे आकर्षक अनुदान, प्रोत्साहन, सहायता तथा भू-रूपान्तरण जैसी सहूलियतों की वजह से किसान एवं उद्यमी इसमें खासी रुचि दिखा रहे हैं। वेयर हाउस एवं कैटल फीड उद्यमों के साथ तिलहन, दलहन, मसाले, मूंगफली, कपास, दूध एवं अनाज प्रोसेसिंग की इकाइयां स्थापित कर रहे हैं। कोविड की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद प्रदेश में 617 एग्रो प्रोजेक्ट स्थापित हो रहे हैं जिन पर 1255 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इसके लिए राज्य सरकार ने 119 करोड़ रुपए की सब्सिडी मंजूर कर दी है। राज्य में 88 किसानों ने भी 39 करोड़ 60 लाख रुपए की सब्सिडी लेकर उद्यम स्थापित किए हैं। गैर कृषक उद्यमियों ने 496 करोड़ रुपए निवेश कर 250 इकाइयां स्थापित की हैं, जिन पर 79 करोड़ 69 लाख रुपए सब्सिडी दी गई है। अन्य प्रोजेक्ट्स के लिए बैंकों से लोन स्वीकृत होकर कार्य चालू हो गया है जिन्हें शीघ्र ही सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी।

-सोहन लाल
जनसम्पर्क अधिकारी

आसानी से मिल रहा है अनुदान और लोन

जोधपुर जिले के मथानिया में एग्रो इंडस्ट्रीज स्थापित करने वाले काश्तकार श्री मोहन राम चौधरी बताते हैं कि वह पीढ़ियों से कृषि कार्य करते आए हैं पर क्षेत्र में भूजल की गिरती स्थिति ने उन्हें चिंतित कर रखा था। इसी बीच साल 2019 में राज्य सरकार की कृषि प्रसंस्करण सम्बन्धी योजना की जानकारी मिली कि इसमें किसानों को उद्योग लगाने के लिए एक करोड़ रुपए तक पूंजीगत अनुदान प्राप्त हो रहा है और बैंक भी आसानी से

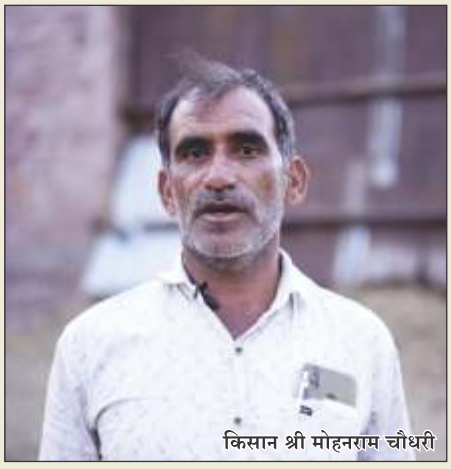

किसान श्री मोहनराम चौधरी

एग्रो इंडस्ट्री की तकदीर बदलने वाली नीति

प्रोजेक्ट एक्सपर्ट श्री विशाल बूब का कहना है कि यह नीति राज्य में एग्रो इंडस्ट्री की तकदीर बदलने वाली है। प्रशासनिक सहयोग और बैंकिंग तंत्र की रुचि इस योजना को सफल बना रही है। एग्रो उत्पादों की भरपूर संभावना वाला राजस्थान इस नीति के बल पर अग्रणी प्रदेश बनकर उभरेगा।

महिला किसान श्रीमती मुन्नी सांखला

प्रोजेक्ट फाइनेंस कर रहे हैं। उन्होंने सक्रिय होकर योजना को समझा और मूंगफली के दानों से सम्बंधित कार्य शुरू करने का निर्णय लिया। उसके बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत की तो सहजता से अनुदान राशि व लोन मंजूर हो गया। अब वह एक प्रगतिशील काश्तकार के साथ सफल उद्यमी बनने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं।

महिला किसान बनी निर्यातक

जोधपुर की ही महिला किसान श्रीमती मुन्नी सांखला आज जगदंबा डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री की मालकिन हैं। उन्होंने प्याज-लहसुन डिहाइड्रेशन सम्बन्धी प्लांट व मशीनरी लगायी है। वह अपना अनुभव साझा करते हुए बताती हैं कि प्याज और लहसुन स्थानीय स्तर पर मिल जाते हैं। हम उनका मूल्य संवर्धन कर निर्यात करते हैं। इससे किसानों को भी उनकी उपज का उचित मूल्य मिल जाता है। इसी प्रकार जोधपुर के बालरवा गांव के रहने वाले

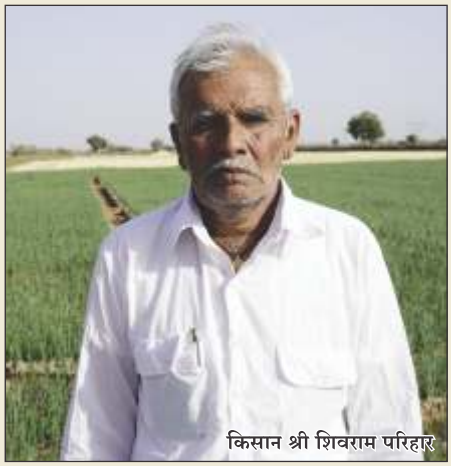
किसान श्री शिवराम परिहार

श्री शिवराम परिहार ने मसाला प्रसंस्करण का उद्यम लगाया है। परम्परागत रूप से कृषि कार्य से जुड़े श्री परिहार का कहना है कि इस योजना को लेकर प्रशासन का अच्छा सहयोग मिल रहा है। सब्सिडी रिलीज होने से लेकर सब कुछ तयशुदा वक्त पर हो गया।

डॉक्टर ने बनाया कोल्ड स्टॉरेज

ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े मथानिया के श्री सुमेर टांक ने वेयर हाउस का कारोबार शुरू किया है। वह पहले से ही कृषि उत्पादों का परिवहन करते रहे हैं। इसलिए उनके दोनों व्यवसायों में एक जुड़ाव हो गया है। इससे उन्हें न केवल अच्छा आर्थिक लाभ मिल रहा है बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा का भी बोध होता है। चिकित्सा के पेशे से जुड़े डॉ. मनोहर परिहार ने परिहार स्टोरेक्स के नाम से कोल्ड स्टॉरेज स्थापित किया है। डॉ. परिहार कहते हैं कि चिकित्सा उनका पेशा है लेकिन कृषि सम्बन्धी व्यवसाय और नवाचार हमेशा से ही उनकी रुचि रही है। ऐसे में 2019 में घोषित नीति ने उनका मनोबल बढ़ाया और वह इस नए और रुचिकर व्यवसाय की तरफ मुड़ गए। उन्हें गैर कृषक श्रेणी में 25 फीसदी सब्सिडी मंजूर हुई है। कोल्ड स्टॉरेज में बिजली के लिए पारम्परिक स्रोतों पर निर्भरता कम कर सोलर पैनल इंस्टॉल करवाया है जिस पर उन्हें अलग से 30 प्रतिशत अनुदान प्राप्त हो गया।

एक-एक करोड़ रुपए तक अनुदान

इस नीति के माध्यम से प्रदेश में एग्रो इंडस्ट्री के लिए अनुकूल माहौल बनाने और एक तंत्र स्थापित कर किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास किया गया है। इसके तहत सरकार एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाने और इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए किसानों और उद्यमियों को पूंजीगत निवेश और ब्याज पर अनुदान दे रही है। किसान एवं उनके संगठनों को परियोजना लागत का 50 फीसदी (अधिकतम एक करोड़ रुपए तक) तथा अन्य पात्र उद्यमियों को 25 प्रतिशत (अधिकतम 50 लाख रुपए) अनुदान दिया जा रहा है।

किसानों को 6 फीसदी की दर से ब्याज अनुदान

संचालन लागत कम करने के लिए सावधि ऋण लेने पर किसानों एवं उनके समूहों को 6 फीसदी की दर से 5 साल तक ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। किसानों के लिए ब्याज अनुदान की अधिकतम सीमा एक करोड़ रुपए तय की गई है। नीति के माध्यम से क्षेत्रीय, लैंगिक एवं जातीय असमानता को कम करने तथा नौजवान उद्यमियों को प्रोत्साहित करने का भी प्रयास किया गया है। सामान्य उद्यमियों को 5 फीसदी की दर से 5 साल तक ब्याज अनुदान दिया जा रहा है जबकि आदिवासी क्षेत्रों एवं पिछड़े जिलों में इकाइयां लगाने वालों तथा अनुसूचित जाति-जनजाति, महिला एवं 35 साल से कम उम्र के उद्यमियों को एक प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान मिल रहा है। यह प्रसंस्करण उद्योगों के लिए अधिकतम 50 लाख रुपए एवं आधारभूत संरचना इकाइयों के लिए एक करोड़ रुपए तक दिया जा रहा है।●

सोयाबीन बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बने किसान

देशी पद्धति में बिना लागत के स्पाइरल सीड़ ग्रेडर से तैयार किया जाता है सोयाबीन बीज

–हरि ओम सिंह गुर्जर
उप निदेशक (जनसम्पर्क)

प्रदेश में सोयाबीन उत्पादन के लिए अग्रणी कोटा संभाग के किसान अब उन्नत बीज उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। यह संभव हुआ है राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री बीज स्वावलम्बन एवं बीज ग्राम योजनान्तर्गत कृषि विभाग द्वारा स्पाइरल सीड ग्रेडर के माध्यम से सोयाबीन की ग्रेडिंग करवाकर किसानों द्वारा किसानों के लिए उन्नत बीज की उपलब्धता की बदौलत।

कोटा संभाग के बारां, बूंदी, कोटा व झालावाड़ जिलों में सोयाबीन एक प्रमुख खरीफ फसल है जिसकी लगभग 7 लाख 45 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में खेती की जाती है। सोयाबीन की बीज दर 80 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर है। इसकी बीज प्रतिस्थापन दर लगभग 34 प्रतिशत है। बीज प्रतिस्थापन दर के आधार पर लगभग 1 लाख 80 हजार क्विंटल बीज की आवश्यकता प्रतिवर्ष होती है जो कि सरकारी, सहकारी एवं निजी उत्पादकों द्वारा पूरी की जाती है। सोयाबीन की बुवाई के समय किसानों को समीप के मध्यप्रदेश राज्य से भी बीज मंगवाना पड़ता था जिससे किसानों को अधिक राशि भी व्यय करनी पड़ती थी। इसी समस्या के निराकरण के लिए कृषि विभाग द्वारा सोयाबीन उत्पादक किसानों को उन्नत बीज तैयार करने के लिए प्रेरित किया गया।

खरीफ 2021-22 में तिलहनी फसलों की आय में अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि एवं सोयाबीन के उन्नत बीज की कमी की पूर्ति करने के लिए कृषि विभाग द्वारा कृषकों को स्वयं के बीज को उपयोग में लेने एवं अधिशेष बीज को अन्य कृषकों को उपलब्ध करवाने के लिए तैयार किया गया। किसानों को उन्नत बीज की छंटनी करने तथा वर्षभर सुरक्षित भंडारण के लिए गांव-गांव में संगोष्ठियां आयोजित की गईं। सोयाबीन का उन्नत बीज तैयार करने के लिए विभागीय अनुदान योजना में नवाचार के रूप में उत्पादित बीज की स्पाइरल सीड ग्रेडर के माध्यम से ग्रेडिंग करवाकर बीजोपचार उपरांत कृषकों को बुवाई के लिए प्रेरित किया गया।

''स्पाइरल सीड ग्रेडर से संभाग में वर्ष 2020-21 में 1 लाख 62 हजार क्विंटल एवं वर्ष 2021-22 में कुल 1 लाख 50 हजार 16 क्विंटल सोयाबीन का उन्नत बीज तैयार किया गया।'' इसके लिये विभाग द्वारा संभाग की सभी ग्राम पंचायतों में कृषक गोष्ठी आयोजित की गई जिनमें 927 स्थानों पर 15 हजार 260 किसानों ने भाग लिया। संगोष्ठियों में किसानों द्वारा 1 लाख 313 क्विंटल बीज की मात्रा स्वयं के उपयोग के लिये बताई गई। 34 हजार 737 उपचारित बीज शेष रहा जिसे अन्य किसानों के लिये उपलब्ध कराया गया। इस प्रकार संभाग में 1 लाख 36 हजार 50 क्विंटल बीज किसानों द्वारा कृषि विभाग के बताये अनुसार उपचारित किया गया। कोटा के थामली गांव निवासी किसान कोमलप्रसाद मीणा बताते हैं कि ''स्पाइरल सीड ग्रेडर के माध्यम से घर में पैदा की गई सोयाबीन की ग्रेडिंग करना आसान है इसमें कृषि विभाग द्वारा बताये गये रसायन का स्पाइरल में लेप कर उसमें बीज को उपचारित किया जाता है जिससे वह वर्षभर तक सुरक्षित रह सके इसमें केवल श्रम करने की जरूरत है लागत कुछ भी नहीं है।'' वे कहते हैं कि यह पद्धति अब किसानों द्वारा किसानों के लिए उन्नत बीज उपलब्धता का आधार बनी है।

कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा कृषक गोष्ठियों में मुख्यमंत्री बीज स्वावलम्बन योजना, बीज गांव योजना, सोयाबीन प्रदर्शन की जानकारी दी गई। इसके उत्साहजनक परिणाम आने पर कृषकों के स्वयं उत्पादित बीज की सफाई एवं ग्रेडिंग करवा कर उस उपलब्ध बीज की सूचना कृषि पर्यवेक्षकों के व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कृषकों में प्रसारित करवाई गई जिससे कृषक आवश्यकता होने पर बीज का बुवाई के लिए उपयोग कर सकें। सोयाबीन के बीज को साफ कर बीजोपचार उपरांत उपयोग में लेने के लिए प्रेरित किया गया।●

फसलों की नई किस्में और तकनीक विकसित कर

खेती-किसानी को समृद्ध बनाने में जुटे कृषि विश्वविद्यालय

– डॉ. ओमप्रकाश गढ़वाल
तकनीकी सलाहकार, कृषि विभाग

खेती-किसानी को समृद्ध बनाने में कृषि विश्वविद्यालयों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। विश्वविद्यालय लगातार अनुसंधान कर नई-नई किस्में और तकनीक विकसित करते हैं। राज्य के कृषि विश्वविद्यालय इस दिशा में कार्य करने में प्रभावी ढंग से जुटे हुए हैं। यहां विभिन्न फसलों की ज्यादा पैदावार वाली कई किस्में विकसित की गई हैं। नई-नई कृषि तकनीक ईजाद की गई हैं। साथ ही प्रशिक्षण एवं प्रचार-प्रसार के माध्यम से इन्हें काश्तकार के खेत तक पहुंचाया जा रहा है ताकि किसान को वास्तव में लाभ मिल सके।

श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) में जैव विविधता पार्क की स्थापना की गई है जिसमें राजस्थान मूल की 103 से भी अधिक पादप प्रजातियों को लगाया गया है। विश्वविद्यालय की ओर से जौ की किस्में (R-2899 RD-2907), चौले की किस्म (CPD-119) व एक सौंफ की किस्म (RF-290) विकसित कर ली गई है। इसके साथ ही दो बायोफोर्टिफाइड बाजरा किस्में (RHB-233 और RHB-234) भी विकसित की गई हैं। बीज की समय पर प्रोसेसिंग करने के लिए यहां 6 नए बीज प्रसंस्करण यंत्र लगाए गए हैं। कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा Diploma in Agricultural Extension Services for Input Dealers (DAESI) प्रोग्राम के अन्तर्गत इनपुट डीलरों को एक वर्षीय कोर्स करवाया जा रहा है।

कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर में नयी फसलों जैसे कैमोमाइल (चाय) एवं चिकोरी (कॉफी) पर राज्य में पहली बार अनुसंधान कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।

महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर की ओर से मूंगफली की उच्च उत्पादन क्षमता की किस्म मूंगफली-3 (यूजी 116) राजस्थान के लिए जारी की गई। स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के अनुसंधान निदेशालय द्वारा उन्नत बीजों की चार नई किस्में विकसित की गई हैं। इनमें कपास की आरएस 2817 एवं आरएस 2827, चना की केशव, बाजरा की बीएचबी 1202 सम्मिलित हैं। कृषि विश्वविद्यालय, कोटा में चना, उड़द, मटर, मसूर एवं अलसी की उन्नत किस्मों का विकास किया गया है। अनुसंधान प्रयोगशालाएं कृषि अनुसंधान केन्द्र, उम्मेदगंज पर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत मधुमक्खी पालन एवं प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की गई।

नए कृषि महाविद्यालयों की स्थापना

युवाओं में कृषि ज्ञान का विकास करने के इसके लिए राज्य सरकार ने नए कृषि महाविद्यालयों की स्थापना की है। गत सालों में श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर के अधीन कोटपूतली (जयपुर), बसेड़ी (धौलपुर), किशनगढ़बास (अलवर), झिलाई (टोंक), भुसावर (भरतपुर) एवं नीम का थाना (सीकर) में नवीन कृषि महाविद्यालय तथा जोबनेर में डेयरी प्रौद्योगिकी महाविद्यालय स्थापित किए गये हैं। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के नए संघटक महाविद्यालय के रूप में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, राजगढ़ (चूरू) एवं मंडावा (झुंझुनूं) में कृषि महाविद्यालय प्रारम्भ किए गए हैं। कृषि विश्वविद्यालय, कोटा के अन्तर्गत हिंडौली (बूंदी) में कृषि महाविद्यालय खोला गया है। कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर में शैक्षणिक सत्र 2020-21 से डेयरी संकाय में 40 विद्यार्थियों के साथ अध्यापन शुरू किया गया है। कृषि अभियांत्रिकी संकाय इस सत्र से प्रारम्भ कर दिया जाएगा।●

सोलर टोपी : किसानों को मिलेगी तेज धूप और गर्मी से राहत

काश्तकारों को खेती-बाड़ी के अधिकतर काम तेज धूप में ही करने पड़ते हैं। विशेषकर मार्च-अप्रैल के तपते महीनों में रबी फसलों की कटाई, ग्रीष्मकालीन फसलें तथा खरीफ फसलों में अंत: शस्य क्रियाएं एवं इनकी कटाई जैसे काम दिनभर तीव्र धूप एवं गर्मी में ही होते हैं। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर की कृषि श्रम विज्ञान एवं सुरक्षा अनुसंधान परियोजना की टीम ने किसानों की इस समस्या का समाधान करने का प्रयास किया है। वैज्ञानिकों ने किसानों की इस समस्या को प्रमुखता से लेकर इसके निराकरण के लिए एक सोलर टोपी विकसित की है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस टोपी में 3 वाट का एक सोलर पैनल लगा है जो कि इसमें लगे पंखे को संचालित करता है। पंखे से बनने वाली हवा का संचरण सिर के चारों तरफ से ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ होता है जिससे शरीर के आसपास माइक्रो क्लाइमेट विकसित होता है। कृषि कार्य के दौरान शरीर के आसपास वायु का यह संचरण वाष्पीय शीतलन प्रभाव के कारण शरीर के तापमान को कम बनाये रखने में सहायक होती है। टोपी में लगी प्लग से वायु के प्रवाह को कम अथवा अधिक किया जा सकता है। इस टोपी की लागत लगभग दो हजार पांच सौ रुपए है। ●

फ्री रेंटल स्कीम

किसानों को घर बैठे ऑनलाइन मिल रही है ट्रैक्टर और कृषि यंत्रों की फ्री सेवा

कोविड से पैदा हुए विषम आर्थिक हालातों के बीच राज्य में करीब 24 हजार छोटे एवं सीमांत किसान इस स्कीम का फायदा ले चुके हैं।

इस स्कीम से न केवल किसानों को समय पर फ्री सेवा मिलने से आर्थिक फायदा हो रहा है बल्कि ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्रों के मालिक रेंटर्स को भी अच्छा रोजगार मिल रहा है। अब उन्हें भुगतान भी तुरन्त हो जाने से उधारी जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है।

किसान घर बैठे ही मोबाइल से मैसेज एवं कॉल करते हैं और खेत की जुताई-बुवाई के लिए ट्रैक्टर-कृषि यंत्र हाजिर हो जाते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री में। यह सम्भव हुआ है कृषि मंत्री श्री लालचंद कटारिया की पहल पर कृषि विभाग की ओर से टैफे कम्पनी के माध्यम से शुरू की गई फ्री रेंटल स्कीम से। कोविड से पैदा हुए विषम आर्थिक हालातों के बीच राज्य में करीब 24 हजार छोटे एवं सीमांत किसान इस स्कीम का फायदा ले चुके हैं।

इस योजना से लाभान्वित हुए भरतपुर जिले के नगर तहसील के जयश्रा गांव के किसान अमरचंद बताते हैं कि योजना की जानकारी मिलते ही उन्होंने जे फॉर्म सर्विसेज के टोल फ्री नम्बर पर रजिस्ट्रेशन करवाकर डिस्क हैरो के लिए बुकिंग करवाई। इसके दो दिन बाद टैफे जे फार्म के जिला फील्ड ऑफिसर ने फोन पर उनसे संपर्क किया और पूरी जानकारी लेकर उनके कार्य के लिए एक रेंटर की व्यवस्था करवा दी। रेंटर ने खेत पर पहुंचकर 3 घण्टे ट्रैक्टर चलाया और 6 बीघा

– सोहन लाल
जनसम्पर्क अधिकारी

में डिस्क हैरो निकाल दिया। इसके लिए उन्हें कोई भुगतान नहीं करना पड़ा। घर बैठे ही इससे उनका समय पर काम हो गया और 3 हजार रुपए की बचत हो गई। उन्होंने बताया कि कोविड काल में गांवों में पैसों की व्यवस्था करने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ती है लेकिन कृषि विभाग और टैफे कम्पनी की इस योजना ने हमारा काम आसान कर दिया है।

भुगतान सीधा रेंटर के बैंक खाते में

अलवर जिले की मुंडावर तहसील के टोडरपुर गांव के किसान लीलाराम ने भी फ्री रेंटल स्कीम का लाभ लिया है। उन्होंने भी स्कीम की जानकारी मिलते ही कम्पनी के टोल फ्री नम्बर पर सम्पर्क कर कल्टीवेटर के लिए बुकिंग कराई। जिला फील्ड ऑफिसर ने उनसे सम्पर्क कर रेंटर उपलब्ध करा दिया। रेंटर ने उनके खेत पर ढाई घण्टे कल्टीवेटर चलाकर 5 बीघा में कार्य किया। इसका भुगतान टैफे कम्पनी ने सीधा रेंटर के बैंक खाते में कर दिया।

लीलाराम कहते हैं कि इस स्कीम की बदौलत ही समय पर अच्छा काम हो गया और न इसके लिए कोई राशि चुकानी पड़ी। इससे उनके 3 हजार रुपए बच गए।

रेंटर को रोजगार और समय पर भुगतान

इस स्कीम से न केवल किसानों को समय पर फ्री सेवा मिलने से आर्थिक फायदा हो रहा है बल्कि ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्रों के मालिक रेंटर्स को भी अच्छा रोजगार मिल रहा है। उन्हें भुगतान भी तुरन्त हो जाने से उधारी जैसी समस्या का भी सामना नहीं करना पड़ता है।

भरतपुर जिले के जयश्रा गांव के रेंटर मूलचंद के मुताबिक वह एक साल पहले से ही इस स्कीम से जुड़े हुए हैं। उन्हें समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिली कि कृषि विभाग और टैफे कम्पनी इस साल भी किसानों के खेतों में फ्री कार्य करेगी तो उन्होंने क्षेत्र के कई जरूरतमंद किसानों का मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवाया। उन्हें जे फॉर्म एप्लीकेशन पर किसानों की बुकिंग की डिमांड मिली। कम्पनी के फील्ड ऑफिसर ने फोन से सम्पर्क किया और किसानों के कृषि कार्य करने के लिए नियुक्त किया। उन्होंने 21 काश्तकारों के खेतों में 123 बीघा में ट्रैक्टर चलाया। इसका कुल 61 हजार 500 रुपए का बिल बना जिसमें से 41 हजार 900 रुपए काम करने के 7 दिन के भीतर बैंक खाते में आ गए। शेष राशि भी जल्दी ही मिल जाएगी।

इस स्कीम से न केवल किसानों को समय पर फ्री सेवा मिलने से आर्थिक फायदा हो रहा है बल्कि ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्रों के मालिक रेंटर्स को भी अच्छा रोजगार मिल रहा है। उन्हें भुगतान भी तुरन्त हो जाने से उधारी जैसी समस्या का भी सामना नहीं करना पड़ता है।

अलवर जिले के टोडरपुर गांव के पायल हायरिंग सेंटर के रवि कुमार ने क्षेत्र के 80 किसानों के 400 बीघा में 1 लाख 56 हजार रुपए का कार्य किया। इसमें से 48 हजार 806 रुपए का भुगतान सीधा ऑनलाइन बैंक खाते में हो गया है और बची हुई राशि भी जल्दी ही खाते में आ जाएगी। इसी तरह जयपुर जिले की जमवारामगढ़ तहसील के जयचन्दपुरा गांव के चौधरी कस्टम हायरिंग सेंटर के सुरेश कुमार जाट बताते हैं कि उन्होंने अब तक 18 किसानों के कार्य किया है जिसका पूरा भुगतान भी हो चुका है। अभी 10 किसानों के और ऑर्डर आए हुए हैं जिन्हें पूरा करना है। सुरेश जाट ने पिछले साल भी इस स्कीम के तहत 30 किसानों के यहां फसल कटाई एवं थ्रेसिंग का कार्य किया था।

अब तक करीब 24 हजार किसान लाभान्वित

फ्री रेंटल स्कीम से अब तक राज्य के करीब 24 हजार किसान लाभान्वित हो चुके हैं। कृषि विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री भास्कर ए. सावंत ने बताया कि 1 जून से शुरू की गई इस योजना के तहत अब तक 23 हजार 810 किसानों को लाभ मिल चुका है। उन्होंने बताया कि विभिन्न रेंटर्स ने किसानों के 42 हजार 613 एकड़ जमीन पर 68 हजार 286 घंटे सेवा मुहैया करा दी है। उन्होंने बताया कि छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए यह सेवा आगामी 31 जुलाई तक जारी रहेगी।

ऐसे ले सकते हैं स्कीम का लाभ

कृषि आयुक्त डॉ. ओमप्रकाश ने बताया कि काश्तकार https://jfarmservices.com लिंक के माध्यम से खुद को JFarm Services एप पर रजिस्टर कर ऑर्डर बुक कर सकते हैं। साथ ही ट्रैक्टर मालिक भी इसी लिंक के माध्यम से अपने आप को जोड़कर ऑर्डर स्वीकार कर सकते हैं। इसके अलावा टोल फ्री नम्बर 1800-4200-100 पर फोन करके भी इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। ऑर्डर केवल खेती के यंत्रों जैसे हल, रोटावेटर, प्लाउ, बिजाई मशीन इत्यादि के लिए ही मान्य होगा। एक किसान का केवल एक ही ऑर्डर मान्य होगा।

उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष भी कृषि विभाग के प्रयासों से कोविड काल में करीब 27 हजार किसानों को एक लाख घण्टे से ज्यादा की नि:शुल्क सेवा दी गई थी।●

सहकारी ऋण से किसान का उत्थान

–ओटाराम चौधरी
सहायक निदेशक (जनसम्पर्क)

सहकारी आंदोलन प्रत्येक देश में उसके देशवासियों के अधिकाधिक समुदाय की महत्ती आवश्यकताओं को पूरी करने के उद्देश्य से शुरू हुआ है। इंग्लैंड में उपभोक्ता भण्डार, इटली में मजदूरों की ठेका समितियां, जर्मनी में ऋण व उपभोक्ता समितिया, कनाडा में क्रय-विक्रय समितियां एवं भारत में कृषि ऋणदात्री समितियों से सहकारी आंदोलन की शुरुआत हुई है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। अत: भारत में सहकारी आंदोलन कृषि संबंधी आवश्यक साधनों को जुटाने के उद्देश्य को लेकर शुरू हुआ।

भारतीय कृषक की मुख्य समस्या समुचित अर्थ की व्यवस्था रही है। अत: सहकारी आंदोलन का उद्देश्य किसान को पर्याप्त ऋण की व्यवस्था कराना रहा है ताकि किसान को साहूकार के पास हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं रहे। भारतीय सहकारी आंदोलन मुख्यतया ऋण आंदोलन रहा है और आज भी है। हालांकि अब बदलाव का दौर शुरू हुआ है तथा समितियां विभिन्न व्यवसाय कर सहकारी आंदोलन को मजबूती दे रही हैं।

सहकारी पद्धति में ऋण का अपना एक संगठन है। इसके लिए प्रत्येक राज्य में एक शीर्ष सहकारी बैंक होता है। इस बैंक की मुख्यतया केन्द्रीय सहकारी बैंक सदस्य होती है। शीर्ष बैंकों को नाबार्ड से ऋण मिलता है। यह फसली ऋण सरकार की जमानत के फलस्वरूप मिलता है। अभी यह 4.50 प्रतिशत ब्याज दर पर मिल रहा है।

शीर्ष सहकारी बैंक के सदस्य केन्द्रीय सहकारी बैंक होते हैं। राजस्थान में 29 केन्द्रीय सहकारी बैंक जिला स्तर के सहकारी संगठन हैं। इन्हें अपेक्स बैंक जो कि राज्य का शीर्ष सहकारी बैंक है, से ऋण 4.70 प्रतिशत की दर से मिलता है। केन्द्रीय सहकारी बैंक के सदस्य प्राथमिक सहकारी समितियों, क्रय-विक्रय सहकारी समितियों, जिले की अन्य समितियां व व्यक्तिगत सदस्य होते हैं। यह बैंक प्राथमिक ऋणदात्री समितियों को ऋण देते हैं तथा इनसे 5 प्रतिशत ब्याज दर लेते हैं।

प्राथमिक ऋणदात्री समितियां अपने सदस्यों के लिए केन्द्रीय सहकारी बैंक से 5 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण लेकर उन्हें उत्पादन कार्यों के लिए ऋण देती है तथा सदस्य किसानों से 7 प्रतिशत ब्याज दर लेती है। इस प्रकार सहकारी समितियों के सदस्यों को 7 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन राजस्थान में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की पहल के कारण शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर किसानों को यह ऋण उपलब्ध होता है। सरकार किसानों के ब्याज के पेटे अनुदान देकर इसकी क्षतिपूर्ति राशि सहकारी बैंकों को देती है।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत किसानों के प्रति संवेदनशील हैं। किसानों की ऋण माफी का फैसला लेकर लगभग 21 लाख किसानों का 15500 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण माफ किया है। सरकार ने कोविड-19 के दौरान किसानों के हित में फैसले लेकर किसान एवं उसके परिवार को राहत दी है।

प्रत्येक व्यक्तिगत सदस्य, प्राथमिक सहकारी समिति व केन्द्रीय सहकारी बैंक व अपेक्स बैंक को ऋण प्राप्त करने के लिए साख नीति है। यह नीति रजिस्ट्रार सहकारी समितियों द्वारा जारी की जाती है और साख सीमा के अन्तर्गत ऋण मिलता है।

अत: उपर्युक्त सहकारी ऋण संगठन के ढांचे से यह स्पष्ट है कि रुपया नाबार्ड से आता है यदि निश्चित समय पर यह रुपया नहीं चुकाया जाता है और रकम समय पर नहीं चुकाने का कोई खास कारण नहीं होता है तो ऋण नहीं मिलता है अतएव रुपये का आदान-

प्रदान जारी रखने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्तिगत सदस्य समय पर समिति का ऋण, समिति केन्द्रीय सहकारी बैंक का व केन्द्रीय सहकारी बैंक शीर्ष बैंक का ऋण चुकाए।

राजस्थान में सबसे पहले वर्ष 1904 में अजमेर में सहकारिता की शुरूआत हुई। आजादी के समय राज्य में 2669 सहकारी समितियां कार्यरत थी और केवल 1 प्रतिशत ग्रामीण परिवार ही सहकारिता के दायरे में थे आज राज्य में 35 हजार से अधिक विभिन्न सहकारी समितियां है, जिनके 1 करोड़ से अधिक सदस्य हो गए है और यह प्रदेश के आर्थिक विकास में अपनी हिस्सेदारी निभा रही है।

राजस्थान में किसानों से संबंधित प्रमुख सहकारी गतिविधियों में फसल की तात्कालिक जरूरत पूर्ति के लिए अल्पकालीन फसली सहकारी ऋण का वितरण, कृषि के लिए आधारभूत सुविधाऐं उपलब्ध कराने के लिए पांच से पन्द्रह साल की अवधि के कृषि ऋण, विपणन सहकारी समितियों के माध्यम से काश्तकारों को कृषि आदानों का वितरण, कृषि जिन्सों की समर्थन मूल्य पर खरीद, कृषि उत्पादों का विपणन सहित अन्य संचालित की जा रही है।

इन गतिविधियों का संचालन के लिए राजस्थान राज्य सहकारी बैंक, राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक जैसी सहकारी संस्थायें सदस्य सहकारी संस्थाओं को ऋण सहित अन्य सुविधाऐं उपलब्ध कराकर किसानों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में अपना योगदान दे रही है। सहकारी ऋण समय एवं उद्देश्य की दृष्टि से तीन प्रकार के होते है–अल्पकालीन, मध्यकालीन ऋण एवं दीर्घकालीन ऋण।

अल्पकालीन ऋण

राजस्थान राज्य सहकारी बैंक की स्थापना 14 अक्टूबर, 1953 को हुई ग्रामीण एवं कृषक समुदाय को अल्पकालीन कृषि ऋण, गैर कृषि ऋण रोजगारोन्मुख योजनाओं हेतु

ऋण उपलब्ध कराने के लिए स्थापित किया है। बैंक 29 केन्द्रीय सहकारी बैंकों एवं 6700 से अधिक ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, गुणात्मकता एवं नैतिक मूल्यों के साथ काश्तकारों को सेवाऐं दे रहा है। बैंक अल्पकालीन फसली ऋण किसानों को वितरित हेतु उपलब्ध कराता है।

अल्पकालीन फसली ऋण वितरण कार्यक्रम को एकरूपी, पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित बनाने के दृष्टिकोण से किसानों को फसली ऋण आधार आधारित अभिप्रमाणन के पश्चात डिजीटल मेम्बरशीप रजिस्टर के माध्यम से किये जाने हेतु ''सहकारी फसली ऋण ऑनलाईन पंजीयन एवं वितरण योजना, 2019'' माह जुलाई, 2019 में प्रारंभ कर योजनान्तर्गत निरंतर ऋण वितरण किया जा रहा है।

अल्पकालीन सहकारी फसली ऋण के लिए किसान को ग्राम सेवा सहकारी समिति का सदस्य होना आवश्यक है। किसान की पात्रता के आधार पर उसे अधिकतम 1.50 लाख रूपये का फसली ऋण शून्य प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध कराया जाता है। इस ऋण की अवधि खरीफ फसल के लिए अप्रेल से अगस्त माह तक तथा रबी फसल के लिए सितम्बर से मार्च माह तक के लिए होती है। इसमें किसानों को खरीफ फसल के लिए ऋण चुकारा 31 मार्च को करना होता है। जबकि रबी फसल के लिए आगामी वित्तीय वर्ष की 30 जून तक ऋण चुकाना होता है। देय तिथि से बाद में ऋण चुकाने वाले काश्तकारों को ब्याज का भुगतान करना होता है।

वर्ष 2020-21 में 26 लाख से अधिक किसानों को 15235.33 करोड़ रूपये का फसली ऋण वितरित किया गया। किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर मिलने वाले इस फसली ऋण के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने पूर्ववर्ती कार्यकाल के दौरान वर्ष 2012 से ब्याज अनुदान देने की शुरूआत की थी। इस बदौलत ही राज्य सरकार 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान सहकारी बैंकों को देती है, जिससे शून्य ब्याज दर पर किसानों को सहकार फसली ऋण सुविधा मिल रही है।

मध्यकालीन कृषि ऋण

मध्यकालीन कृषि निवेश अंतर्गत सहकारी बैंकों द्वारा कृषि से सम्बद्ध गतिविधियों के लिए कृषि ऋण उपलब्ध करवाये जाते हैं। वर्तमान में मुख्यत: सहकार किसान कल्याण योजना अंतर्गत इस प्रकार के ऋण उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। इस योजना में

अधिकतम 10 लाख रुपये तक का ऋण किसानों को दिया जा रहा है। जो 11 प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध होता है।

सहकारी बैंकों से मध्यकालीन कृषि ऋण किसानों को कृषि यंत्रीकरण, सिंचाई साधन, बागवानी विकास, डेयरी विकास, सौर ऊर्जा पम्प, ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, व्हाइट हाउस, ड्रिप सिंचाई संयंत्रों हेतु वित्त पोषण, चारा संग्रहालय एवं भण्डारण एवं कृषि उपज के विरुद्ध काश्तकार को रहन ऋण के लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पैक्स/लैम्प्स के माध्यम से असिंचित भूमि होने की स्थिति में 50 हजार रुपये तक तथा सिंचित भूमि होने की स्थिति में 1 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता है।

कृषि उपज रहन ऋण

किसानों को फसल का बेहतर मूल्य दिलाने, खरीद के लिए सुगम एवं विकेन्द्रीकृत व्यवस्था करने और उपज को रहन रखकर कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत सरकार निरंतर कदम उठा रही है।

आमतौर पर बाजार में फसल आने के समय जिन्सों के भाव कम होते हैं लेकिन आवश्यकताओं की पूर्ति और संस्थागत ऋणों को चुकाने के लिए किसान कम दामों पर ही फसल बेचने को मजबूर हो जाते हैं। इन परिस्थितियों से बचाकर किसान को तात्कालिक वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सहकार किसान कल्याण योजना में प्रतिवर्ष 50 करोड़ रुपये का अनुदान देने का निर्णय लिया है।

इस योजना के तहत किसानों को उनके द्वारा रहन रखी गई उपज के बाजार मूल्य या समर्थन मूल्य, जो भी कम हो, के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा तथा मूल्यांकित राशि की 70 प्रतिशत राशि रहन ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। लघु एवं सीमान्त किसानों के लिए 1.50 लाख रुपये एवं बड़े किसानों के लिए 3 लाख रुपये का ऋण मात्र 3 प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। किसान को 90 दिवस की अवधि के लिए यह ऋण मिलता है। विशेष परिस्थितियों में यह 6 माह तक हो सकती है। इस योजना के तहत पैक्स या लैम्प्स के सभी ऋणी एवं अऋणी किसान सदस्य उपज रहन ऋण लेने के पात्र हैं। वर्ष 2020-21 में किसानों को 20.46 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया।

दीर्घकालीन कृषि ऋण

किसानों को दीर्घकालीन कृषि ऋण राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के माध्यम से प्राथमिक भूमि विकास बैंकों द्वारा दिया जाता है। राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की स्थापना 26 मार्च, 1957 को हुई । जिला/तहसील स्तर पर 36 प्राथमिक भूमि विकास बैंक कार्यरत हैं। प्राथमिक बैंकों द्वारा उनकी शाखाओं के माध्यम से राज्य के किसानों एवं लघु उद्यमियों को वर्तमान में 10 प्रतिशत ब्याज दर पर दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराये जा रहे हैं। इस प्रकार के ऋण लघु सिंचाई, कृषि यंत्रीकरण एवं कृषि सम्बद्ध गतिविधियों के लिए दिए जाते हैं।

किसान लघु सिंचाई के कार्यों को जैसे - नवकूप/नलकूप, कूप गहरा, पम्पसेट, फव्वारा/ड्रिप सिंचाई, विद्युतीकरण, नाली निर्माण, डिग्गी/हौज निर्माण इत्यादि के लिए

भूमि विकास बैंकों से ऋण ले सकते हैं। इसी प्रकार कृषि यंत्रीकरण के कार्यों जैसे - ट्रैक्टर, कृषि यंत्रादि, थ्रेशर, कम्बाइन हार्वेस्टर इत्यादि तथा कृषि सम्बद्ध गतिविधियां जैसे डेयरी, भूमि सुधार, भूमि समतलीकरण, कृषि भूमि क्रय, अनाज/प्याज गोदाम निर्माण, ग्रीन हाउस, कृषि कार्य हेतु सोलर प्लान्ट, कृषि योग्य भूमि की तारबन्दी/बाउण्ड्रीवाल, पशुपालन, वर्मी कम्पोस्ट, भेड़ / बकरी / सुअर / मुर्गी / रेशम कीट / मधुमक्खी पालन, उद्यानीकरण, ऊंट / बैल गाड़ी क्रय इत्यादि के लिए भी इस प्रकार के कृषि ऋण भूमि विकास बैंकों द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत किसानों के प्रति संवेदनशील हैं। किसानों की ऋण माफी का फैसला लेकर लगभग 21 लाख किसानों का 15500 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण माफ किया है। सरकार ने कोविड-19 के दौरान किसानों के हित में फैसले लेकर किसान एवं उसके परिवार को राहत दी है, चाहे वह कम ब्याज पर ऋण की उपलब्धता हो या समय पर खाद बीज की व्यवस्था हो या किसान की उपज बेचान की सुगम व्यवस्था हो या समय पर उपज बेचान का भुगतान या फसल बीमा का भुगतान सहित अन्य ऐसे महत्त्वपूर्ण निर्णयों के द्वारा मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत किसानों को आर्थिक संबल प्रदान कर रहे हैं।●

बूंदी में सब्जी उत्कृष्टता केन्द्र

बिना मिट्टी सब्जी उपजाने की तैयारी

– रचना शर्मा
सहायक निदेशक (जनसम्पर्क)

बूंदी में स्थापित सब्जी उत्कृष्टता केन्द्र अपने विविध नवाचारों से खेती किसानी को समृद्ध करने की दिशा में बढ़ रहा है। व्याधियों से सुरक्षित खेती, मल्चिंग व लो-टनल जैसी तकनीक से खेती के प्रोत्साहन के साथ ही अब यहां उच्च पौष्टिकता वाली देशी-विदेशी सब्जियों को 'हाइड्रोपोनिक्स तकनीक' से यानी बिना मिट्टी, पानी में उगाने की तैयारी की जा रही है। इजरायली तकनीक पर आधारित इस नवाचार में थोड़े ही पानी में सब्जियों की फसल तैयार की जाएगी। इसके लिए परियोजना स्थापित की जा रही है।

सब्जी उत्पादन में बूंदी अग्रणी जिला है। यहां मटर, शिमला मिर्च, खीरा, टमाटर, करेला, गोभी आदि सब्जियां प्रचुर मात्रा में पैदा होती हैं। किसानों की उपज को अधिक गुणवत्तापूर्ण बनाने तथा राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय बाजार तक उनकी पहुंच बनाकर किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में सब्जी उत्कृष्टता केन्द्र कार्य कर रहा है।

अगले चरण में यहां शुरू होने वाली 'हाइड्रोपोनिक्स' परियोजना में इस तकनीक से ना केवल स्थानीय बल्कि जुकुनी, पार्सली, ब्रोकली जैसी विदेशी सब्जियां तैयार की जायेंगी। किसानों को प्रशिक्षण देकर इनकी पैदावार के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस तकनीक की खूबी है कि काफी कम पानी में पैदावार की जा सकती है। पानी की बचत के दृष्टिगत यह तकनीक भविष्य की तकनीक बनने जा रही है। इसमें मिट्टी के स्थान पर पौष्टिक तत्त्व वाले पानी का उपयोग किया जाता है। इसमें मामूली पानी की आवश्यकता होती है। उपयोग में लिया पानी भी पुन: काम में लिया जा सकता है।

मृदा एवं मौसम जनित व्याधियों से फसल अप्रभावित रहती है व अधिक स्वस्थ होती है तथा बेमौसम भी इच्छित उपज प्राप्त की जा सकती है। चूंकि बूंदी सब्जी उत्पादन में अग्रणी है तथा पानी की भी समस्या है, ऐसे में यह सब्जी उत्पादक तकनीक किसानों के लिए वरदान साबित हो सकती है। इसमें परियोजना स्थापना के समय ही राशि का निवेश करना होता है। इसके बाद तुलनात्मक रूप से अन्य खेती के बजाय कम ही खर्च आता है।

सब्जी उत्कृष्टता केन्द्र में हाइटेक प्लग नर्सरी विशिष्ट है जो राजस्थान की अपनी तरह की पहली है। इस नर्सरी में उच्च गुणवत्ता वाले बीज तैयार कर उनकी पौध तैयार की जाती है। पूरा संयंत्र पूर्णत: स्वचालित है जिसकी सम्पूर्ण मॉनिटरिंग डिजिटल माध्यम से की जा सकती है। यहां बीजों की प्रकृति के अनुसार तापमान रखते हुए पौध तैयार की जाती है। बूम इरिगेशन से इनमें सिंचाई होती है। यहां किसानों द्वारा लाए गए बीजों को उपचारित कर गुणवत्तापूर्ण बनाया जाता है तथा उनसे स्वस्थ पौध तैयार कर उन्हीं किसानों को दी जाती हैं। इससे किसानों को कम लागत में उच्च श्रेणी की पौध मिल जाती है अन्यथा बाजार से मिलने वाले या स्वयं किसान द्वारा तैयार किए गए बीजों में से 50 फीसदी का ही अंकुरण होता है।

परियोजना की स्थापना का उद्देश्य नवीन कृषि तकनीकी प्रदर्शन द्वारा सघन प्रणाली की स्थापना, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार हेतु वर्ष भर उच्च गुणवत्ता का सब्जी फसल उत्पादन है। प्रति इकाई क्षेत्रफल से अधिकतम उत्पादकता का लाभ प्राप्त करना तथा तकनीकी के साथ किसानों का नेतृत्व करना भी है। मल्च एवं लो-टनल के साथ ओपन खेती, पॉली हाउस एवं शेडनेट में संरक्षित खेती प्रदर्शन किए जाते हैं। सूक्ष्म सिंचाई एवं उर्वरक प्रबंधन, सूखारोधी एवं कम पानी की फसलों की जांच, किस्मों के अनुरूप सिफारिश, समन्वित कीट प्रबंधन, फसलोत्तर प्रबंधन के लिए पैक हाउस एवं मूल चैन स्थापना, मूल्य संवर्धन हेतु उत्पाद का प्रसंस्करण भी संस्थान के उद्देश्यों में सम्मिलित है।

नवीन कृषि तकनीकी प्रदर्शन द्वारा सघन प्रणाली की स्थापना राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार हेतु वर्ष भर उच्च गुणवत्ता की सब्जी फसल उत्पादन पर फोकस है।

फोटो–फीचर

छाया : अशोक गुरावा, सविता चौहान, सूजस, कृषि विभाग

सात समन्दर पार तक बून्दी बासमती की महक

– रचना शर्मा
सहायक निदेशक (जनसंपर्क)

हाड़ौती की धरा अपनी प्राकृतिक संपदा के लिए विख्यात है, वहीं विविध खाद्यान्नों की उपज से भी संपन्न है। हाड़ौती की जन्मस्थली बूंदी भरपूर धान उपजा कर ''अन्नपूर्णा'' का रूप चरितार्थ कर रही है। यहां के बासमती चावल ने अपनी खूबियों से बूंदी के नाम को सात समंदर पार तक पहुंचाया है।

रेगिस्तानी आबोहवा वाले अरब सर्दीले–बर्फीले यूरोपियन व अमेरिकन देशों के लोगों की थाली बूंदी की बासमती के बिना अधूरी रहती है। पुलाव, बिरयानी के शौकीनों को तो बूंदी का बासमती चावल ही भाता है। बूंदी बासमती का यह मुकाम यहां के श्रमवीर धरती पुत्रों और उनके श्रम को तराशने वाले व्यापारिक वर्ग के संयुक्त उद्यम का ही प्रतिफल है।

वर्तमान में बूंदी जिले में चावल का लगभग 12.5 सौ करोड़ का सालाना कारोबार है। उत्पादन लगभग 3.60 लाख मीट्रिक टन है जिसमें से 2.50 लाख मीट्रिक टन का निर्यात है। राष्ट्रीय– अंतरराष्ट्रीय स्तर की चुनौतियों के बावजूद यह सम्पदा बूंदी के लिए सशक्त संबल बनकर खड़ी है।

रंग– रूप– स्वाद..सभी अनूठा'

बूंदी में चावल उत्पादन का चलन हालांकि हाड़ौती के अन्य जिलों से आया लेकिन रंग, रूप, स्वाद और महक में बूंदी बासमती ने सबको पीछे छोड़ दिया। हाड़ौती संभाग में सबसे ज्यादा 24 चावल मिल बूंदी में हैं। इनमें प्रतिवर्ष औसतन 5 लाख टन धान की प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग से बनने वाला ''सेला'' चावल ही मुख्य रूप से निर्यात किया जाता है। बूंदी के बासमती चावल की भारी मांग खाड़ी देशों में तो रहती ही है, अमेरिका, एशिया, अफ्रीका में भी यहां से चावल निर्यात होता है।

बूंदी बासमती की सेला या पैरा बॉयल किस्म प्रमुख रूप से निर्यात की जाती है। धान से विशेष प्रक्रिया द्वारा प्रोसेसिंग के जरिए सेला चावल तैयार किया जाता है। चावल की यह सेला किस्म भी एक प्रकार से बूंदी की ही देन है। संभवतः इसी कारण इसकी विशिष्टता भी बनी हुई है। धान की खेती और चावल उद्योग में शुरुआती दौर से लगे श्री मदन गोपाल शर्मा बताते हैं कि चंबल और नहरी तंत्र के कारण धान और चावल उद्योग यहां फला फूला। शुरुआती दौर में धान से निकला चावल क्षेत्र की गरम आबोहवा के कारण रंग रूप और गुणवत्ता में प्रभावित हो जाता था। इसमें चूड़ीनुमा दरारें पड़ जाती थीं। इस समस्या का समाधान यहां के चावल उत्पादकों ने ''सेला'' किस्म बनाकर किया जो आज पुलाव, बिरयानी की खास महक और स्वाद के लिए मशहूर है। इसके लिए कच्चे चावल को निर्धारित तापमान पर भाप में पकाने और सुखाने की प्रक्रिया से सेला चावल तैयार किया जाता है। यही चावल पुलाव, बिरयानी की महक और स्वाद बढ़ाता है। सेला बनाने की यह प्रक्रिया पहले परंपरागत तरीके से बड़े–बड़े पात्रों में धान को हल्का पकाकर और सुखाकर तैयार की जाती थी जिसमें मेहनत और समय

के साथ जोखिम भी रहता था लेकिन समय के साथ-साथ यह कार्य अब मशीनों के साथ बखूबी हो रहा है। कुछ प्लांट तो पूर्णतया स्वचालित हैं जहां खेत से आए कच्चे धान की सफाई, ग्रेडिंग, सोर्टिंग, पैरा बॉयलिंग, ड्राइंग से लेकर पैकिंग तक समस्त प्रक्रियाएं मशीन से होती हैं। इसमें लगभग 14 घंटे चावल को गलाया जाता है और फिर अलग-अलग तापमान पर इतने ही घंटे सुखाया जाता है। तत्पश्चात् छिलका उतारकर इसे अंतिम रूप दिया जाता है। चावल के सामान्य दाने की लंबाई 8.35 एमएम होती है जबकि बूंदी का चावल 8.45-50 एमएम तक लंबा होता है। इसकी सफेदी भी अपेक्षाकृत अधिक है।

चुनौतियों से मुकाबले को बढ़ रहे कदम

एक समय बूंदी का चावल निर्यात बहुत उत्साहजनक स्थिति में था लेकिन अंतरराष्ट्रीय

व्यापार संधियों से यह तेजी से प्रभावित हुआ। सबसे बड़े खरीददार ईरान और खाड़ी देशों में निर्यात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। वर्तमान में स्वास्थ्य जागरूकता के कारण ऑर्गेनिक उत्पाद की मांग तेजी से बढ़ी है जिसके कारण भी निर्यात पर असर पड़ा है। इसी बीच कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक स्तर पर होटल इंडस्ट्री के ठप्प होने से भी इसका कारोबार प्रभावित हुआ है। चावल उद्योग के संघ के अध्यक्ष नीरज गोयल बताते हैं कि राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक नीतियों का सीधा असर इस कारोबार पर है। निर्यात घटा है तथा यथेष्ट मूल्य भी नहीं मिल पाता। साथ ही देश की आंतरिक व्यापारिक नीतियां, डीजल की बढ़ती कीमत आदि भी इसे प्रभावित करती हैं। चावल कारोबार से जुड़े राजेश तापड़िया बताते हैं कि साल दर साल पानी की कमी, बिजली की उपलब्धता भी इसे प्रभावित करती हैं। उनकी अपेक्षा है कि सुदृढ़ व्यापारिक नीतियों से ही इस उद्योग को पंख मिल सकेंगे। सब चुनौतियों के बावजूद बूंदी को धान से आस है। भविष्य की मांग की दृष्टि से कीटनाशकों के सीमित उपयोग की ओर सोच बढ़ रही है, कदम बढ़ने लगे हैं। चावल कारोबारी रमनदीप शर्मा बताते हैं कि बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान की ओर से चलाए जा रहे ''एरिया मल्टी पेस्टिसाइड्स अवेयरनेस कैंपेन'' को स्थानीय चावल उत्पादक एवं व्यापारिक वर्गों के समन्वय से किसानों तक पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। चावल उद्योग संघ इस दिशा में प्रयत्नशील है। सेमिनार

तथा साहित्य वितरण के जरिए अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता के साथ पर्यावरण का ध्यान रखते हुए कीटनाशकों के प्रयोग पर अंकुश लगाने के लिए जागरूक किया जाने लगा है। किसानों को कीट प्रबंधन, फसल अवशेष प्रबंधन आदि की जानकारी दी जा रही है।

सीमावर्ती राज्यों से भी अच्छी आवक

बूंदी के चावल की मांग का आलम यह है कि हाड़ौती के अन्य जिलों के साथ-साथ इसके सीमावर्ती राज्यों से भी बड़ी मात्रा में धान की आवक बूंदी में हो रही है जिसे प्रोसेसिंग के जरिए गुणवत्तापूर्ण और मांग के अनुरूप बनाया जाता है। यहां की प्रमुख कृषि उपज मंडी कुंवारती में साल में औसतन एक लाख बोरी धान की आवक होती है। हाड़ौती के कोटा, बारां, झालावाड़ जिलों के अलावा मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के निकटवर्ती क्षेत्रों से भी धान यहां आता है। जिले में बूंदी, तालेड़ा और केशोरायपाटन प्रमुख धान उत्पादक क्षेत्र हैं। गत 5 वर्षों के परिदृश्य पर नजर डालें तो यहां चावल पैदावार का रकबा बढ़ा है परंतु उत्पादन में अपेक्षाकृत कमी आई है।●

वर्षवार धान के फसल क्षेत्र उत्पादन की स्थिति

क्र.सं.	वर्ष	फसल क्षेत्र (हैक्टेयर)	उत्पादन (मीट्रिक टन)
1.	2020-21	63218	2,14,331
2.	2019-20	57825	1,79,509
3.	2018-19	50213	2,01,860
4.	2017-18	47006	1,30,363
5.	2016-17	44345	2,65,970

Jodhpuri Handicraft: Acquiring Prominent Place in International Market

-Sakshi Purohit
PRO, Jodhpur

Historical City of Jodhpur, the second largest district of Rajasthan and remotely located in the west on the map of our country is a hub of artistic furniture and handicraft items. Jodhpur is also known for its traditional heritage, historical foundation and a city established by Rao Jodha in 1459. A prominent kingdom of Marwar region has enamoured itself as "cultural capital of Rajasthan" in due course of time with many historical events in its back drop. The city is also identified by its Ummed Palace, Mehrangarh Fort, Chamunda Mata Temple in Mehrangarh Fort, stone made houses with blue colour cladding and the culture flowing out of their historical precincts, displays an ethnic and world famous handicrafts culture to the world. The city known for its chivalry and hospitality has also been successful in bringing handicrafts artistry and wooden craft under one umbrella. The artistic touch and the craftsmanship and the master pieces created by these artisans have not only brought glory to the state but also have placed Jodhpur in a category of world class mercentile. Thus making Jodhpur's handicrafts industry spectrum of designers hub, be it field of stone cutting, wooden furniture, clothing and pottery.

The handicrafts industry of Jodhpur was established ages ago and few of pioneer industries were Lalji Handicrafts and since then more and more entrepreneurs joined the success story of Jodhpuri Handicrafts. Today all the manufacturers, exporters and other person closely related to handicrafts industry keep on putting their concerted efforts, restructuring the business and keeping their enterprises abreast with international standards and competitiveness, conscious strategic shift from traditional handicrafts and artistic furniture to gift ware and life style products particularly catering for the contemporary demands of the international market. And the commitment further rose to manufacturing of accessories of home decors, with world class design development and honouring time bound commitment. From original to recycled, from rusty antique finishes to contemporaries and from traditional to exquisite artistic blend, the Jodhpur handicraft industry has risen up from scratch and achieved fame on the rampants of world's handicrafts industry. The handicrafts industry has become the power house to sustain the economy of the state in general and region in particular. It is economically important & has high potential for export and thereby earning for the national

forex reserve i.e. approx. Rs. 1500 crores a year.

It is the prominent employment generating industry, to the tune of approx 2 lac persons are associated with the industry and earning their livelihood. Handicrafts industry of Jodhpur is also promoting cottage industries in the rural areas around Jodhpur.

Industry is eco friendly as there is no use of big machinery or high power consumption. It is not dependent upon imported substances including technology in the manufacturing process.

Export trade has helped in opening of inland container depots in the Jodhpur, one in Govt. sector, one in private sector and one by the Railways.

Jodhpur is completely unique when it comes to handicrafts. If we talk about China that works on quantity and voluminous orders where as Jodhpur's creativity and exclusivity attracts customers from all over the world.

The Rajasthan Government is continuously promoting the industries and business even in the times of pandemic.

The State Government indeed play an important role in promoting business houses, entrepreneurs including the new budding entrepreneurs and industries. Rajasthan Government's "Yuva Protsahan Yojna" is really very helpful to promote new talents.

RIICO is also developing new industrial areas in which so many types of relaxation are given by the Government which is again very beneficial to the handicrafts businesses.

The State Government's support is the key factor because of which Jodhpur's handicrafts business is getting premium position at worldwide platform. The products are being exported almost everywhere in countries like Australia, Japan, Gulf whole Europe, America and Canada etc.

Jodhpur has already got its fame in antique furniture, bone furniture, modern wooden and iron furniture as well as the gift items/ articles and many more. Talking about the future of Jodhpur's handicrafts, it's going to shine high for ages because of its ergonomical designs and development concepts.•

Communication Through Folk Media

- Hema Khanna
Journalist

The folk media is a projection of community's aspirations and culture and is well known for its due acceptability, cultural relevance, entertainment value in its own localized dialect, flexibility, message repetition ability as its virtue. It is an effective way of communicating with the rural communities where literacy rate is poor. This is because of the reason that message delivered in this way with the help of community people is well understood and well accepted.

Folk arts of Rajasthan touches the heart because it is alive with the warmth of the artists' soul.

And also, because it is not possible to reach to every person in the far flung areas of the state through electronic or print media so the aide & assistance of the folk media is being taken to communicate with rural audiences in their natural surroundings

No denying to the fact that Rajasthan is known to have a several kinds of folk arts including folk lore, traditional dances, folk songs, like kachhi ghodi, terah taali, kavadiyas etc., which are forms of entertainment, evolved as grassroot expressions of the ethics and life styles of the people, dealing with values as well as information. However folk performances viz puppet shows, magic shows, nukkad natak are being chiefly concentrated on by the government department for dissemination of information and generating awareness under various health and development projects and programmes.

These days government it clear that the interactive and engaging nature of the folk media intervention has made it possible for the individuals to come out of their shells, spurring conversations between them and their peers, about sensitive topics

During the course of interpersonal communication with the rural masses, it is learnt that the folk performances have tremendous potential to change individual level attitudes about those infected and affected by different diseases, as well as change individual behaviors, after overcoming certain personal and community level barriers .

In such a scenario, it becomes imperative to focus on information dissemination as a tool to spread awareness. The folk media have become an effective tool in arousing the zeal & enthusiasm of the rural masses for fighting the menace of various diseases and promoting development and growth as it inspires the people to perceive the message or information more effectively.•

आंगनबाड़ी केन्द्रों में किचन गार्डन

गर्भवती, धात्री माताओं, बच्चों को मिल सकेगा पोषण

– सौरभ सिंघारिया
जनसम्पर्क अधिकारी

राजसमंद जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चों और गर्भवतियों, धात्री माताओं को पोषित करने के लिऐ किचन गार्डन और पोषण वाटिका विकसित किए जा रहे हैं। पहले चरण में जिले में लगभग 244 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषण वाटिका बना दी गयी हैं। दूसरे चरण में जिले के 200 आंगनबाड़ी केन्द्रों का चयन कर मनरेगा के माध्यम से कार्य करवाकर पोषण वाटिका विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।

पोषण अभियान के तहत विकसित हो चुके आंगनबाड़ी केन्द्रों पर लाभार्थियों को दिये जाने वाले पोषाहार के साथ-साथ आंगनबाड़ी केन्द्रों पर उपलब्ध पौष्टिक सब्जियां एवं फल आदि वितरण किये जा रहे हैं। जिले की समस्त परियोजना के माध्यम से पोषण वाटिका के फोटो एवं सब्जियां तथा फल वितरण करते हुए ग्रुप में शेयर किये जाते हैं। पोषण वाटिका में उपलब्ध सब्जियों के स्टॉक व वितरण रजिस्टर बनाये गये हैं जिसमें कार्यकर्ता लेखा-जोखा रखेगी। महिला एवं बाल विकास विभाग की महिला सीडीपीओ, पर्यवेक्षक और एनटीटी शिक्षकों को जिम्मेदारी दी गयी है। ये अपनी निगरानी में किचन गार्डन तैयार करा रहे हैं।

पोषण वाटिका विकसित करने के लिए निदेशालय स्तर से चयनित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पिछले वर्ष 10,000 रुपये प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र पर व्यय किए गए। मनरेगा के माध्यम से चयनित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर समतलीकरण एवं पौधरोपण के लिये गड्ढे खुदवाने के कार्य करवाये गये। इस वर्ष भी महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिला परिषद को चयनित 200 आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची भेजी गयी है जहां पोषण वाटिका विकसित करने हेतु समतलीकरण, पौधरोपण हेतु गड्ढे एवं पौधों की व्यवस्था जिला परिषद द्वारा करवायी जाएगी।

पोषण वाटिका में तीन प्रकार के पौधे

- वाटिका की फेसिंग के लिए पौधे- मेहंदी, करौंदे, संतरे, नींबू आदि।
- फलों के पौधे - अमरूद, केला, अनार, पपीता, बेर, आम, आँवला, किन्नू, संतरा, बील, करौंदे, जामुन आदि।
- सब्जियों के पौधे - भिण्डी, लौकी, तोरई, टमाटर, मिर्च, मूली, धनियां, पुदीना, प्याज, आलू, मटर, खीरा, ककड़ी पालक, मैंथी, चौलाई आदि। साथ ही पोषण वाटिका में औषधीय पौधों को भी लगाया जा सकता है जैसे तुलसी, गिलोय आदि।

जिला परिषद एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के समन्वय से पोषण वाटिका का निर्माण करवाया है जिसमें आंगनबाड़ी केन्द्र पर आने वाली गर्भवती, धात्री, महिलाओं एवं बच्चों को लाभ मिल रहा है। इससे लोगों में पौष्टिक फल व सब्जियों के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी। ●

राजस्थान में विधानमण्डल (विधानसभा) का उद्भव एवं विकास

(1913 से वर्तमान तक)

– डॉ. गोरधन लाल शर्मा
राजस्थान प्रशासनिक सेवा

बीकानेर राजस्थान (राजपूताना) का पहला रियासती राज्य था जिसमें महाराजा गंगा सिंह ने सर्वप्रथम जनप्रतिनिधि सभा (House of Representatives) की स्थापना में अग्रणी कदम उठाया।

- राजपूताना के इस प्रथम विधानमण्डल (जनप्रतिनिधि सभा) का उद्घाटन 10 नवम्बर, 1913 को हुआ।
- जन प्रतिनिधि सभा द्वारा नवम्बर, 1913 से मार्च, 1947 तक 116 सरकारी विधेयक पारित किए गए जिन्होंने कानून का रूप लिया।

बांसवाड़ा राज्य

- बांसवाड़ा राजपूताना का दूसरा राज्य था जहां के शासक ने 3 फरवरी, 1939 को राज्य परिषद् के गठन की घोषणा करने का कदम उठाया।
- रियासती राज्य का दीवान उक्त परिषद् का पदेन अध्यक्ष होता था। वर्ष 1939 से 1946 तक परिषद का कुल 6 बार अधिवेशन आहूत किया गया इसमें मात्र 12 दिवस कार्य हुआ।

जोधपुर राज्य

- जोधपुर राज्य में महाराजा उम्मेद सिंह ने एक प्रतिनिधि परामर्शदात्री सभा के गठन की घोषणा की और एक अप्रैल, 1941 को इसके लिए संविधान स्वीकृत किया गया।

- सभा का शुभारम्भ 15 जनवरी, 1942 को हुआ। यद्यपि सभा को कोई वित्तीय और विधायी अधिकार प्राप्त नहीं थे तथापि सभा को जन महत्त्व के कतिपय विषयों – शिक्षा, जन स्वास्थ्य, कस्टम्स, सहकार एवं स्वायत्त शासन से सम्बन्धित कार्यों पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त थी।
- उक्त विधानसभा में 52 निर्वाचित सदस्य तथा कुछ मनोनीत तथा पदेन सदस्य थे। वर्ष 1944 में महाराजा द्वारा गवर्नमेंट ऑफ जोधपुर एक्ट पारित किया गया।
- जोधपुर की प्रतिनिधि परामर्शदात्री सभा की वर्ष 1942 से 1945 के मध्य 10 बैठकें हुईं और 64 दिवस कार्य हुआ।
- मार्च–अप्रैल, 1947 में सभा के चुनाव सम्पन्न हुए। फरवरी, 1947 में महाराजा द्वारा उक्त सभा के कार्यकाल को घटाकर 4 से 3 वर्ष में परिवर्तित किया गया और मनोनीत उपाध्यक्ष के स्थान पर निर्वाचित उपाध्यक्ष का प्रावधान किया गया।

बूंदी रियासत

- बूंदी में 18 अक्टूबर, 1943 को महाराजा ईश्वरी सिंह ने धारा सभा का गठन किया जिसमें कुल 23 सदस्य थे, इनमें 12 निर्वाचित तथा 11 मनोनीत सदस्य थे।
- धारा सभा द्वारा 10 जुलाई, 1947 को बूंदी राज्य संविधान एक्ट, 1947 पारित किया गया जिसमें सभा का कार्यकाल 4 वर्ष का रखा गया।
- धारा सभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार संयुक्त निर्वाचन पद्धति तथा गुप्त मतदान के आधार पर होता था।

डूंगरपुर रियासत

- डूंगरपुर में वर्ष 1918 ई. में महारावल ने एक राज शासन सभा का गठन किया जो दीवानी मामलों में रियासत के उच्च न्यायालय तथा आपराधिक मामलों में सत्र न्यायालय की शक्तियां रखती थी।
- इस राज शासन सभा में कुछ सरदार, अधिकारी तथा गणमान्य नागरिक सम्मिलित थे।
- वर्ष 1936 में महारावल द्वारा उक्त सभा को विधायी कार्य सौंपे गए, परिणामस्वरूप यह एक विशिष्ट विधानसभा के रूप में संचालित होने लगी।

जयपुर राज्य

- जयपुर के महाराजा मानसिंह – द्वितीय ने 1 जून, 1944 को कांस्टीट्यूशन एक्ट, द गवर्नमेंट ऑफ जयपुर एक्ट, 1944 पारित किया।
- इस अधिनियम में एक द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान था जिसमें एक प्रतिनिधि सभा तथा दूसरा सदन विधान

परिषद् था।

- उक्त दोनों सदनों के लिए 10 तथा 15 मई, 1945 को निर्वाचन हुए जिसमें राज्य प्रजा मण्डल को बहुमत प्राप्त हुआ।
- उक्त विधायिका का उद्घाटन महाराजा द्वारा 5 सितम्बर, 1945 को किया गया। 1 मार्च, 1948 को संविधानिक सुधारों की घोषणा के साथ जयपुर राज्य में पूर्ण जन प्रतिनिधि सरकार का गठन हुआ और जयपुर राज्य विधान मण्डल ने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त किया।

भरतपुर राज्य

- भरतपुर के महाराजा किशन सिंह ने 27 मार्च, 1927 को शासन समिति के गठन की मंशा जाहिर की और सितम्बर, 1927 में शासन समिति अधिनियम प्रभावी हुआ लेकिन किन्हीं कारणों से समिति अस्तित्व में नहीं आ सकी।
- वर्ष 1942 में भरतपुर राज्य प्रजा परिषद् में सत्याग्रह के फलस्वरूप 1 अक्टूबर, 1942 को भरतपुर राज्य प्रतिनिधि सभा का गठन हुआ।
- यह सभा 50 सदस्यीय थी जिसके 37 सदस्य निर्वाचित तथा 13 मनोनीत होते थे। सितम्बर, 1943 में समिति (सभा) के चुनाव सम्पन्न हुए।
- भरतपुर राज्य प्रतिनिधि सभा (शासन समिति) को शासन पर विधेयकों पर चर्चा करने तथा प्रस्ताव पारित करने की शक्तियां प्रदत्त थीं और समिति का कार्यकाल 3 वर्ष था।

उदयपुर (मेवाड़) रियासत

- श्री कन्हैयालाल माणिक्य लाल मुंशी ने मई, 1947 में मेवाड़ रियासत का संविधान तैयार किया जिसे महाराजा द्वारा यथारूप 27 मई, 1947 को अनुमोदित (पारित) किया गया। इसमें वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचित विधायिका का प्रावधान था।
- मेवाड़ विधायिका 56 सदस्यीय थी जिसमें 51 निर्वाचित तथा 5 मनोनीत होते थे। मनोनीत सदस्यों में सभा का अध्यक्ष, रियासत का प्रधानमंत्री तथा 3 मंत्री होते थे।
- प्रथम निर्वाचन 4 अप्रैल, 1948 को हुआ। इस दौरान ही मेवाड़ राज्य प्रजा मण्डल द्वारा इसके बायकॉट की घोषणा की गई और मेवाड़ के मुंशी संविधान का अस्तित्व भी समाप्त हो गया।

टोंक रियासत

- टोंक रियासत के लिए 25 सदस्यीय (12 निर्वाचित एवं 13 मनोनीत) मजलिस-ए-आम का गठन 3 फरवरी, 1941 को हुआ।
- राज्य कौंसिल के उपाध्यक्ष उक्त मजलिस के पदेन सभापति होते थे।
- मजलिस-ए-आम के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से सदस्यों का निर्वाचन पंचायतों के सरपंचों द्वारा जबकि नगरीय क्षेत्रों से नगर पालिका के सदस्यों द्वारा निर्वाचन किया जाता था।
- वर्ष 1941 से 1945 के मध्य मजलिस के मात्र दो एक-दिवसीय सत्र हुए इनमें केवल एक कानून पारित हुआ।
- तत्कालीन राजस्थान में आजादी से पूर्व केवल बांसवाड़ा, बीकानेर, जयपुर और मारवाड़ में ही विधान मण्डल कर्मशील थे। लेकिन इन विधानमण्डलों में समरूपता नहीं थी। ये एक प्रकार के सलाहकार मण्डल थे जिनमें अधिकतर जागीरदार तथा पूंजीपति ही सदस्य होते थे, जन सामान्य का प्रतिनिधित्व नगण्य होता था।

राजस्थान की प्रथम विधानसभा (1952-57)

- राजस्थान की प्रथम विधानसभा 29 मार्च, 1952 को चुने हुए जनप्रतिनिधियों द्वारा शपथ लिए जाने के साथ अस्तित्व में आई। प्रथम विधानसभा के गठन की अधिसूचना 23 फरवरी, 1952 को प्रकाशित हुई।
- विधानसभा के सदस्यों की संख्या परिसीमन आयोग के प्रतिवेदन के आधार पर निर्धारित होती है।
- पहली विधानसभा (1952-57) में सदस्यों की संख्या 160 थी और तत्कालीन अजमेर राज्य का राजस्थान में विलय (नवम्बर, 1956) हो जाने के बाद इसकी सदस्य संख्या बढ़कर 190 हो गई थी।
- प्रथम विधानसभा के पांच साल के कार्यकाल में तीन मुख्यमंत्री बने-
  1. श्री टीकाराम पालीवाल
  2. श्री जयनारायण व्यास
  3. श्री मोहनलाल सुखाड़िया
- प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष श्री नरोत्तम लाल जोशी, उपाध्यक्ष श्री लाल सिंह शेखावत, सरकारी मुख्य सचेतक श्री मथुरादास माथुर तथा नेता प्रतिपक्ष श्री जसवंत सिंह थे। श्री मंशाराम पुरोहित प्रथम विधानसभा के दौरान सचिव के पद पर कार्यरत रहे।
- प्रथम विधानसभा के आम चुनाव में कोई भी महिला प्रत्याशी जीतकर विधानसभा नहीं पहुंची लेकिन उपचुनावों में बांसवाड़ा से यशोदा देवी (नवम्बर, 1953 में) तथा कमला बेनीवाल (जून, 1954 में) चुनाव आमेर 'ए' से जीतकर विधानसभा पहुंची थीं।
- राजस्थान की दूसरी विधानसभा (1957-62) और तीसरी विधानसभा (1962-67) में सदस्यों की संख्या 176 थी।
- चौथी विधानसभा (1967-72) और पांचवीं विधानसभा (1972-77) में सदस्य संख्या बढ़कर 184 हो गई।
- छठी विधानसभा (1977-80) के समय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 200 हो गई और तब से वर्तमान पन्द्रहवीं विधानसभा (2018 से निरन्तर) तक इसकी संख्या 200 ही है।
- प्रथम विधानसभा की शुरुआत 29 मार्च, 1952 को मानसिंह टाउनहाल जयपुर में हुई जो 2001 में लालकोठी स्थित नए विधानसभा भवन में स्थानान्तरित हो गई।●

विकास के पथ पर अजमेर

कोरोना मैनेजमेंट, रोजगार, ग्रामीण और शहरी विकास पर फोकस

राज्य सरकार द्वारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में समानांतर विकास, रोजगार और कोरोना महामारी संक्रमण की रोकथाम की प्राथमिकताओं पर अजमेर में भी पूरा फोकस है। अजमेर जिले में विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर संवेदनशीलता के साथ काम किया जा रहा है। पिछले सवा साल से कोरोना महामारी संक्रमण और इसके साइड इफेक्ट से जूझ रहे जिला प्रशासन ने कुशल चिकित्सा प्रबन्धन के साथ ही रोजगार, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक इनकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अथक काम किया।

पिछले साल लॉकडाउन की शुरुआत के साथ ही अजमेर में आमजन की जान बचाने, उन्हें राहत प्रदान करने, रोजमर्रा की वस्तुओं की आपूर्ति, रोजगार और उद्योगों के संचालन के लिए रणनीति बनाकर काम किया गया। इसके साथ ही सरकारी योजनाओं और राहत कार्यों का दायरा बढ़ा कर प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचाया गया।

महामारी की पहली और दूसरी लहर के दौरान सबसे बड़ी चुनौती चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाने और इनके बेहतरीन प्रबन्धन की थी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत, चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा और प्रभारी मंत्री श्री लालचंद कटारिया के नेतृत्व में जिले में प्रत्येक व्यवस्था पर लगातार मॉनिटरिंग की गई। जिला कलक्टर श्री प्रकाश राजपुरोहित की अगुवाई में टीम ने 24x7 काम किया। कोविड प्रबन्धन के तहत चिकित्सा सुविधाओं और कोरोना बैड की उपलब्धता को संभाग के

– भानुप्रताप सिंह गुर्जर
जनसंपर्क अधिकारी

सबसे बड़े राजकीय जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय से लेकर सीएचसी स्तर तक फैलाया गया। इसके साथ ही ऑक्सीजन मैनेजमेंट पर भी पूरा जोर रहा। जिले में उपलब्ध ऑक्सीजन के साथ ही चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने जिले के बाहर से भी ऑक्सीजन उपलब्ध कराए रखी। राज्य सरकार व अन्य माध्यमों से 26 ऑक्सीजन प्लांटों को मंजूरी दी गई। इनका काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जिले में बड़ी संख्या में कोरोना पीड़ितों को मदद मिली। इसके अलावा अन्य बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए भी यह योजना वरदान साबित हो रही है।

कोरोना प्रबन्धन के तहत ज्यादा से ज्यादा सैंपलिंग, घर-घर सर्वे, अस्पतालों में ऑक्सीजन, आईसीयू व वैंटिलेटर बेड की संख्या में बढ़ोतरी, टेस्टिंग क्षमता में बढ़ोतरी, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, जीवनरक्षक दवाओं की पर्याप्त आपूर्ति और बड़ी संख्या में मेडिकल स्टाफ की अथक मेहनत ने जिले में कोरोना संक्रमण का सामना करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। चिकित्सकों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए बिना रुके, बिना थके काम किया।

चिकित्सा के साथ ही रोजगार उपलब्धता के लिए भी अजमेर ने काम किया। राज्य सरकार की ओर से अनुमत गतिविधियों के तहत उद्योगों के संचालन, उनमें पर्याप्त संख्या में श्रमिकों की उपलब्धता और कच्चे माल की आपूर्ति ने लॉकडाउन और पाबंदियों में भी रोजगार की रफ्तार बनाए रखी। महात्मा गांधी नरेगा से गांवों में लाखों लोगों को रोजगार दिया गया। गांवों में मनरेगा के तहत रिकॉर्ड श्रमिकों को पंजीकृत कर रोजगार प्रदान किया गया है।

जिले में विकास की गाड़ी भी पूरी क्षमता के साथ चलती रही। अजमेर शहर में स्मार्ट सिटी योजना के तहत करीब सौ प्रोजेक्ट पर नियमित काम चल रहा है। कई प्रोजेक्ट लॉकडाउन और कोरोनाकाल में पूरे कर लिए गए। स्मार्ट सिटी योजना की इसी रफ्तार के कारण अजमेर देशभर में 21 वें स्थान पर आ गया है।

डॉ. रघु शर्मा
चिकित्सा मंत्री, राजस्थान

कोविड प्रबन्धन के तहत चिकित्सा सुविधाओं और कोरोना बैड की उपलब्धता को संभाग के सबसे बड़े राजकीय जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय से लेकर सीएचसी स्तर तक फैलाया गया।

राज्य सरकार ने घोषणा की है कि कोई भूखा नहीं सोएगा। इसके लिए इंदिरा रसोई, एक्सप्रेसिया, फूड पैकेट और भामाशाहों की मदद से लाखों व्यक्तियों को खाद्य सामग्री व नकद राहत पहंचाई गई है। इसी के साथ पालनहार व अन्य पेंशन योजनाओं में भी बड़ी संख्या में पात्र व्यक्तियों को राहत दी गई है। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में घोषित मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना में पीड़ित परिवारों को बिना आवेदन एक लाख रुपए की सहायता दी जा रही है। इसी तरह अन्य योजनाओं में भी आमजन को लाभान्वित किया गया है। जिले में कोरोना जन-जागरूकता, कृषि एवं पशुपालन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, सार्वजनिक निर्माण विभाग सहित अन्य योजनाओं में भी महत्त्वपूर्ण कार्य हुए हैं।●

दुनियाभर में दिख रही मकराना मार्बल की चमक

हजारों लोगों को मिल रहा रोजगार

मार्बल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है – नागौर जिले का मकराना

–हेमन्त छीपा
जनसंपर्क अधिकारी

राजस्थान के खनिज पदार्थ जहां राज्य व देश को समृद्ध करते हैं वहीं अपनी विशिष्टता के कारण से विश्व में भी अपनी पहचान रखते हैं। इसमें संगमरमर पत्थर के लिए प्रसिद्ध नागौर जिले के मकराना का अपना विशिष्ट स्थान है जो इसी विशिष्टता के कारण मकराना मार्बल भी कहलाता है।

मकराना का नाम आते ही आगरा के ताजमहल एवं कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल की चमचमाती सफेदी आंखों के सामने आ ही जाती है। संगमरमर की सफेदी का पर्याय बने मकराना के मार्बल उद्योग की चमक आज भी कायम है। मध्यकाल के पूर्व से ही घर-घर में चकला, खरल, गमले, टेबल, डिजायनर कुर्सियां, खिलौने सहित सजावटी सामान बनाकर राष्ट्रीय स्तर पर मार्बल की आधुनिक कलाकृतियों से लोगों को परिचय कराने वाले कुटीर उद्योग आज भी रोजगार प्रदान कर रहे हैं।

मार्बल का वैशिष्ट्य

मकराना के मार्बल की चमक सैकड़ों साल तक गायब नहीं होती, इसका जीवंत उदाहरण आगरा का ताजमहल है जो आज भी अपनी चमक व आभा से लाखों देशी एवं विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इसमें कैल्सियम की मात्रा अधिक होने से यह मार्बल गुणवत्ता एवं टिकाऊपन में इटली, वियतनाम, राजनगर, अम्बाजी व कटनी में निकलने वाले स्टोन से श्रेष्ठ है।

मार्बल की किस्म

मकराना के मार्बल की विभिन्न किस्मों से अलबेटा सफेद मार्बल को उत्तम श्रेणी का

माना जाता है। इनमें चकडूंगरी, माताभर, कालानाडा रेंवत डूंगरी, मकराना कुम्हारी, बोरावड़ कुम्हारी, देवी रेंज, गुणावती रेंज, चौसिरा रेंज, साहबवाली रेंज, नहर रेंज, उलोड़ी रेंज, गुलाबी रेंज, भोंट रेंज, मोरेड़, पहाड़कुआँ व कोलाडूंगरी रेंज की मार्बल खानें शामिल हैं। मकराना मार्बल कैल्साइट का अकूत स्रोत है तथा इस पत्थर में 98 प्रतिशत तक कैल्सियम की मात्रा मिलती है। मार्बल के सॉलिड पत्थरों को काटकर स्लैब निकाले जाते हैं जो इमारतों की फर्श में लगाने के काम आता है।

इमारती पत्थर की श्रेणी के मार्बल की घड़ाई कर उसे मंदिरों व अन्य इमारतों में लगाने हेतु आकार दिया जाता है जिसे घड़वा पत्थर बोलते हैं। इस उद्योग में करीब एक हजार घड़ाई कारखाने संचालित हैं जिनमें करीब 30 हजार मजदूर नियोजित हैं। जो कि पत्थर में कलाकारी कर उसे आकार देते हैं। इसके बाद बचे हुए वेस्ट को खण्डा कहते हैं जो कैल्साइट पाउडर बनाने वाली कंपनियों में काम आता है। खानों से निकलने वाला मलबा मिट्टी, रेगिस्तानी धूलभरी मिट्टी में सड़क को ग्रेवल करने के काम में लिया जाता है।

विश्व प्रसिद्ध इमारतों में मकराना मार्बल

विश्व प्रसिद्ध दिलवाड़ा के जैन मन्दिर, मथुरा में श्रीकृष्ण मंदिर, मां वैष्णो देवी मंदिर, देशनोक स्थित करणी माता मंदिर, अबूधाबी की शेख जायद मस्जिद, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, लखनऊ का अम्बेडकर पार्क, मुम्बई

की हाजी अली दरगाह, अजमेर ख्वाजा साहब की दरगाह, अक्षरधाम मंदिर, जयपुर स्थित लक्ष्मीनारायण (बिड़ला) मंदिर, मुम्बई व वृंदावन स्थित इस्कॉन मंदिर, पाकिस्तान के लाहौर की मोती मस्जिद तथा लुधियाना के दु:ख निवारण साहेब गुरुद्वारा, विश्व के श्वेतांबर जैन मंदिरों, दिगंबर जैन मंदिरों, स्वामी नारायण मंदिरों, अमरपुरा नागौर स्थित संत लिखमीदास का स्मारक सहित विश्व की नामचीन इमारतों में मकराना का मार्बल जड़ा है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार में रखे अभिलेखों में आगरा तक संगमरमर पहुंचाने का उल्लेख है।

मकराना ग्लोबल हेरिटेज में शामिल

इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जिओलॉजिकल साइंस (आईयूजीएस) की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने ग्लोबल हेरिटेज स्टोन रिसोर्सेज के भारतीय शोध दल के प्रस्ताव पर मकराना मार्बल को ग्लोबल हेरिटेज के रूप में मान्यता प्रदान की। मकराना मार्बल व्यवसाय को वैश्विक स्तर पर चमक मिली है।

हजारों मजदूरों को मिल रहा रोजगार

मार्बल खदानों, गैंगसा प्लांट, मार्बल ड्रेसिंग प्लांट, कटिंग मशीन, पॉलिश मशीन, पत्थर तराशने के कारखाने, कई घरों में मार्बल आधारित चल रहे कुटीर उद्योग, मार्बल जुड़ाई (फिटिंग) में करीब 30 हजार से अधिक मार्बल श्रमिक कार्यरत हैं। इसी तरह खदानों, कारखानों, मार्बल गोदाम एवं प्रतिष्ठान पर कच्चे एवं निर्मित माल आदि को लाने व ले जाने में ट्रक, ट्रैक्टर-रेड़ी, मोबाइल क्रेन, एलएनटी एवं जेसीबी मशीन, छकड़ा गाड़ी आदि के माध्यम से लोडिंग-अनलोडिंग के कार्य में श्रमिक जुड़े हैं। मकराना में 900 से भी अधिक मार्बल की खदानें हैं। इन खदानों में हजारों मजदूरों को रोजगार प्राप्त होता है। खदानों का सालाना टर्न ओवर 400 करोड़ रुपए से भी अधिक है। वर्तमान में मकराना क्षेत्र में मार्बल चीरने वाली लगभग 500 गैंगसा मशीनें हैं। इस कारोबार से 5 हजार मार्बल व्यापारी व लगभग 50 हजार मजदूरों को रोजगार मिलता है।

कोचिंग संस्थानों से सालाना 400 करोड़ रुपये से अधिक की आय

सीकर की एजुकेशन हब के रूप में पहचान

शिक्षा के क्षेत्र में सीकर एजुकेशन हब के रूप में अपनी पहचान साबित कर रहा है। पिछले दस वर्षों में सीकर में दूसरे राज्य व जिलों से कोचिंग के लिए आने वाले विद्यार्थियों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। इससे यहां पर रोजगार के नए अवसर बने हैं। प्रदेश में कोटा, अजमेर, पिलानी के बाद अब शिक्षा नगरी के रूप में सीकर का नाम आता है।

सीकर शहर की कुल आबादी तीन लाख की है। यहां पर 15 बड़े कोचिंग संस्थानों सहित 120 से अधिक कोचिंग संस्थान संचालित हैं। यहां पर विद्यार्थी इंजीनियरिंग, मेडिकल, डिफेंस, शिक्षक भर्ती सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हर साल जुटते हैं। यहां पर तीन सौ से ज्यादा हॉस्टल व मैस संचालित हैं।

सतत कठिन परिश्रम –सफलता का मंत्र

सीकर के कोचिंग का सक्सेस मंत्र कड़ी मेहनत है। यही सीकर की ताकत है और भरोसा भी। इसलिए विद्यार्थी और अभिभावकों को सीकर के कोचिंग संस्थानों पर पूरा भरोसा है। हर साल 20 से 25 हजार विद्यार्थी डॉक्टर, इंजीनियर बनने के सपने साकार करने के लिए यहां आते हैं।

शहर के कोचिंग संस्थानों में छात्रों के सतत् एवं सर्वांगीण विकास के लिए व्यक्तिगत विकास, मॉक इन्टरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, कम्यूनिकेशन स्किल की क्लासेज पर विशेष बल दिया जाता है ताकि छात्रों में तकनीकी एवं व्यावहारिक ज्ञान का समुचित विकास हो सके।

कोचिंग संस्थानों में अध्ययन के लिए उपलब्ध सुविधाएं एवं शांत प्राकृतिक वातावरण विद्यार्थी को अपने अध्ययन के प्रति उत्साहित, सकारात्मक एवं जीवन्त बनाता है ताकि वे जीवन में चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो सके। शिक्षण संस्थानों का आधारभूत शैक्षिक ढांचा एवं आदर्श वातावरण विद्यार्थी को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए उत्साहित करता है। सीकर में कोचिंग एजुकेशन का यह कारोबार अब 400 करोड़ रुपए सालाना से अधिक का हो चुका है जबकि सभी कोचिंग-स्कूलिंग और इससे जुड़े उद्योगों का कुल कारोबार हजारों करोड़ रुपए तक पहुंच गया है।

सीकर शहर की कुल आबादी तीन लाख की है। यहां पर 15 बड़े कोचिंग संस्थानों सहित 120 से अधिक कोचिंग संस्थान संचालित हैं। यहां पर विद्यार्थी इंजीनियरिंग, मेडिकल, डिफेंस, शिक्षक भर्ती सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हर साल जुटते हैं। यहां पर तीन सौ से ज्यादा हॉस्टल व मैस संचालित हैं।

कोचिंग की शुरुआत

सीकर में कोचिंग की शुरुआत लगभग 25 साल पहले हुई थी। शुरुआत में सिर्फ चार छात्र थे। इन सभी छात्रों का पहले ही साल में चयन हुआ था। अब कई कोचिंग संस्थान यहां संचालित हैं जिनमें अध्ययन कर हर वर्ष हजारों छात्र-छात्राएं डॉक्टर-इंजीनियर बनते हैं।

एजुकेशन हब

सीकर में विभिन्न कोचिंग संस्थानों में स्कूल ही नहीं यहां कॉलेज की पढ़ाई के साथ-साथ डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, सैनिक से लेकर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। यहां आवासीय सुविधा के साथ विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं।

– पूरणमल
जनसम्पर्क अधिकारी

कोचिंग संस्थानों में खेलकूद गतिविधियों का विशेष ध्यान रखा जाता है। क्रिकेट, फुटबाल, वॉलीबाल, बास्केटबाल, स्विमिंग से लेकर निशानेबाजी व जिम तक की सुविधा विद्यार्थियों को उपलब्ध हैं जो शारीरिक विकास के लिए अति आवश्यक हैं। विद्यार्थियों को तनावमुक्त बनाए रखने के लिए विशेषज्ञों की सहायता से समय-समय पर लाइव मोटिवेशनल सत्र करवाया जाता है।

ऑनलाइन अध्ययन

इस सुविधा के उपयोग से विद्यार्थी अपने घर पर ही रहकर अध्ययन कर सकते हैं। कक्षा कक्ष की तरह ऑनलाइन अध्ययन में भी एक दूसरे से सवाल-जवाब कर सकते हैं। वास्तव में ऑनलाइन अध्ययन की प्रक्रिया स्कूली शिक्षा के लिए एक सुरक्षित विकल्प है।

आय का जरिया

शहर में कोचिंग शिक्षण संस्थान स्थानीय लोगों की आय का जरिया बन रहे हैं। शहर में सब्जी व फास्ट फूड के ठेलों, पान की दुकान से लेकर बड़े स्टोर मॉल, हॉस्टल भी संचालित हो रहे हैं जो स्थानीय लोगों की आर्थिक आय में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। सीकर शहर में हजारों छात्र निजी मकानों में किराये में रहते हैं जिससे भी सैकड़ों परिवारों को किराये से आर्थिक लाभ मिलता है।

बदल रहा प्रदेश में शिक्षा का स्वरूप

अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय से

– अमनदीप
जनसम्पर्क अधिकारी

जयपुर में मानसरोवर स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) शिक्षा का एक उत्कृष्ट केंद्र बनकर उभरा है। इस विद्यालय को वर्ष 2019 में एमजीजीएस (अंग्रेजी माध्यम) में परिवर्तित कर दिया गया था।

अंग्रेज माध्यम के इस महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, मानसरोवर के प्रतिभाशाली छात्र एक नई राह कायम कर रहे हैं। इस विद्यालय के सृजनशील छात्रों आशुतोष सोनी तथा मोहित साहू का वर्ष 2020-21 में सूचना व प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले प्रतिष्ठित इन्सपायर अवार्ड के लिए चयन हुआ है। यह अवार्ड कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को विज्ञान व प्रौद्योगिकी से जुड़े उत्कृष्ट मौलिक विचार तथा नवप्रवर्तन सृजित करने के लिए दिया जाता है। सरकारी स्कूल में अध्ययनरत इन बाल वैज्ञानिकों के तकनीकी नवाचारों की वजह से ये इन्सपायर अवार्ड के लिए चयनित हुए। नौवीं कक्षा के छात्र आशुतोष ने देश में सड़क दुर्घटनाओं में हताहत होने वाले वाहन चालकों की जान बचाने तथा द्रुतगति से चिकित्सकीय सहायता पहुंचाने के लिए एक अभिनव तथा वैज्ञानिक उपाय का विचार दिया। इस विचार के अंतर्गत वाहनों में ऐसे एक्सीडेंट डिटेक्टर सेंसर लगाए जाएंगे जो वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होते ही तुरंत सक्रिय हो जायेंगे तथा दुर्घटना स्थल की जानकारी जीपीएस के माध्यम से परिवारजनों तथा निकटतम अस्पतालों को भेज दी जाएगी जिससे दुर्घटना पीड़ित के प्राणों की रक्षा हो सकें। वहीं 10वीं के छात्र मोहित साहू ने जब देखा की छात्रावास में रहने वाले छात्रों को बर्तन धोने होते हैं तथा कई बार वे बर्तनों को अच्छे से साफ नहीं कर पाते तो इस प्रतिभावान छात्र ने अपनी वैज्ञानिक कल्पनाशीलता का उपयोग करते हुए एक ऐसी मशीन की रूपरेखा तैयार की जिससे आधुनिक तरीके से बर्तन साफ हो जायें तथा छात्रों का समय भी बच सकें। स्कूल की उपलब्धियों की सूची यहीं समाप्त नहीं होती। पहले दो सत्रों में ही महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, मानसरोवर की 26 छात्राएं गार्गी अवार्ड के लिये चयनित हो चुकी हैं। स्कूल ने लॉकडाउन के दौरान अप्रैल, 2020 से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कीं। शिक्षक छात्रों को पढ़ाने के लिए नियमित रूप से गूगल मीट तथा जूम एप का उपयोग करते हैं तथा व्हाट्सएप और गूगल फॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षाएं ली गई है। सभी कक्षाओं में अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन कराया जाता हैं। एक अनूठी पहल के रूप में इस विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबन्धन, जन्माष्टमी आदि पर्व वर्चुअली मनाए गए ताकि बच्चे इन त्योहारों के आनंद से भी वंचित ना हो तथा संक्रमण से भी सुरक्षित रहें। विद्यालय के दो शिक्षक श्रीमती सीता कंवर और डॉ. संतोष जाखड़ शिक्षा विभाग की परियोजना ई-कक्षा हेतु ई-कंटेंट तैयार कर रही हैं जिससे प्रदेशभर के बच्चे लाभांवित हो रहे हैं। विद्यालय में सारी गतिविधियां अंग्रेजी में संचालित होती हैं ऐसे में छात्रों को अंग्रेजी सीखने और बोलने का भरपूर अवसर मिलता है। गत वर्ष लॉकडाउन के दौरान स्कूल बंद हो जाने के बाद छात्र निराश थे। स्कूल के शिक्षकों ने छात्रों को फोन के माध्यम से प्रोत्साहित किया तथा अप्रैल महीने से व्हाट्सएप के माध्यम से गुरुजनों ने सभी विषयों पर स्व-निर्मित वीडियो भेजे ताकि छात्र आगे की पढ़ाई जारी रख सकें। अगस्त महीने से गूगल मीट तथा जूम एप पर लाइव कक्षाएं शुरू हुईं जिनसे विद्यार्थियों को स्कूल जैसा वातावरण प्राप्त हुआ। हम कभी भी अपने शिक्षकों को कॉल करके पढ़ाई संबंधी किसी भी संशय का समाधान कर सकते थे। अध्यापकों की मेहनत से हमारी शिक्षा लॉकडाउन में भी अवरुद्ध नहीं हुई। सामान्य परिवारों से आने वाले विद्यार्थियों के लिए महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल सर्वाधिक उपयुक्त हैं तथा खेल में रुचि रखने वाली विद्यार्थियों के लिए भी ये विद्यालय श्रेयस्कर हैं। इस विद्यालय के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर रस्साकसी प्रतियोगिता, राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर आयोजित ट्रैकिंग कैंप में भाग लेने तथा शैक्षिक भ्रमण पर जाने का मौका मिला। राष्ट्रपति से भी 14 नवम्बर, 2019 को मिलने का अवसर मिला। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, मानसरोवर को वर्तमान में फाइव स्टार रेटिंग प्राप्त है। श्रीमती अनु चौधरी के प्रेरणादायी नेतृत्व में स्कूल लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है जिसकी बानगी इस तथ्य में देखने को मिलती है कि सत्र 2020-21 में विद्यालय में 91 सीटों पर दाखिले के लिए 1 हजार 680 फॉर्म जमा हुए तथा राजस्थान के सरकारी स्कूलों के इतिहास में पहली बार प्रवेश लॉटरी सिस्टम से दिया गया।●

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय

सस्ती और सुलभ शिक्षा प्रदान करने में तत्पर

– डॉ. सुबोध कुमार अग्निहोत्री
एसोसिएट प्रोफेसर

शिक्षा समाज की प्रतिभाओं को तराशती है। किसी भी समाज की प्रगति उसकी उन्नतिशीलता को प्रकट करती है, वहीं एक सुसंस्कारित समाज की नींव शिक्षा की मजबूती पर निर्भर करती है। आज के चुनौतीपूर्ण परिवेश में शिक्षा के आयामों में लगातार परिवर्तन होते जा रहे हैं। विकास के प्रतिमानों को पुष्ट करने का एक महत्त्वपूर्ण कारक है - उच्च शिक्षा। अगर राष्ट्र का समग्र विकास करना है तो पढ़े-लिखे समाज के गुणीजन को नेतृत्व संभालना ही होगा। सुशिक्षा से ही विकसित समाज की परिकल्पना को सुदृढ़ किया जा सकता है। समाज में शिक्षा के वर्चस्व को कायम रखने के लिए जहां पारंपरिक माध्यमों का सहारा लिया जाता रहा है, वहीं वर्तमान परिवेश में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा माध्यम ने शैक्षिक प्रचार-प्रसार में अपना सशक्त हस्तक्षेप प्रदान किया है।

पूरी दुनिया के शैक्षिक परिवेश में ऐसे लोग जो किसी न किसी रूप में पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था का लाभ उठाने से वंचित रह गए हैं उन्हें अब मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से ज्ञान पाने का फायदा मिल रहा है। दूरस्थ शिक्षा माध्यम के व्यापक दर्शन की पृष्ठभूमि पर वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की स्थापना 23 जुलाई, 1987 को की गई थी जो आज विद्यार्थियों को ज्ञानवर्धक व रोजगारपरक शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए कटिबद्ध है। सात क्षेत्रीय केन्द्रों और 82 अध्ययन केन्द्रों के माध्यम से यह विश्वविद्यालय आज प्रगति के नए आयाम गढ़ रहा है। वर्तमान में सवा लाख से ऊपर विद्यार्थी यहां अध्ययनरत हैं। पीएच.डी. को मिलाकर 65 से ज्यादा कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। हर सत्र में विद्यार्थियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। परीक्षाओं का संचालन भी समय से सकुशल किया जा रहा है। कुलाधिपति की आशा के अनुरूप विद्यार्थियों के लिए अनेक रोजगारपरक पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। समाज के हर वर्ग को सस्ती और सुलभ शिक्षा प्रदान करने में वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय तत्पर है। विश्वविद्यालय का उद्यमिता एवं कौशल विकास केन्द्र भी कुशलतापूर्वक कार्य कर रहा है।

आज सूचना क्रांति के दौर में उन्नत तकनीक के जरिए घर बैठे ही विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की जा रही है। ऑनलाइन विद्यार्थियों के अनेक समूह एक प्लेटफॉर्म पर अपनी शंकाओं का समाधान कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के सभी पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। कंप्यूटर में साक्षरता दर बढ़ाने के उद्देश्य से राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ एक एमओयू भी साइन किया गया है। विश्वविद्यालय ने प्रवेश और परीक्षा संबंधी सभी कार्यों को ऑनलाइन संपादित करने की सुविधा प्रदान की है। विश्वविद्यालय की वेबसाइट vmou.ac.in जानकारियों से भरपूर है। प्रश्नबैंक, वीडियो लेक्चर के अलावा असाइनमेंट और किताबों के पीडीएफ वर्जन इस वेबसाइट पर मौजूद हैं जिसका हजारों विद्यार्थी लाभ उठा रहे हैं। वीएमओयू एप के जरिए विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की हर सेवा मौजूद है।

अब यूजीसी ने ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को भी संचालित करने की हरी झंडी दिखा दी है ऐसे में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा का महत्त्व और बढ़ गया है। कोविड महामारी के दौर में वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय ने अपनी उपयोगिता साबित करके एक बड़ा संदेश समाज को दिया है कि जब वक्त चुनौती भरा आता है तो शिक्षा व्यवस्था को सुचारु बनाने में उसका योगदान महत्त्वपूर्ण है। राज्य सरकार ने भी खुला विश्वविद्यालय की गतिविधियों की प्रशंसा की है और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के मार्ग को सुगम बनाने में अपने फैसलों में काफी लचीलापन भी दिखाया जो कि आज के मुश्किल दौर में सराहनीय हैं। विश्वविद्यालय राजस्थान के 33 जिलों में गांवों और ढ़ाणियों तक पहुंच गया है। समाज के हर वर्ग को कम खर्च वाली शिक्षा मुहैया करा रहा है।

देश में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में दूरस्थ शिक्षा ने अपना एक नया स्थान बना लिया है जिससे लाखों–करोड़ों लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इस व्यवस्था ने शिक्षा के प्रति एक विशेष अनुराग पैदा किया है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने भी राष्ट्र के समग्र विकास में उच्च शिक्षा की महत्त्वपूर्ण भूमिका को लेकर अनेक मूल्यवान दस्तावेज प्रकाशित किए हैं। इसी कड़ी में मुक्त शिक्षा पद्धति को भी प्रश्रय दिया गया है।

प्रो. आर.एल. गोदारा
कुलपति

चिकित्सा शिक्षा का सिरमौर बन रहा राजस्थान

–महेंद्र सैनी
जनसंपर्क अधिकारी

राजस्थान कई आधारभूत बदलावों और सुधारों का गवाह बना है। सन् 1991 के LPG (उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण) के दौर में भी राजस्थान किसी न किसी कारण से बीमारू राज्यों में शुमार किया जाता रहा। हालांकि बीते वर्षों में राज्य को विकास की दौड़ में आगे लाने के लिए तमाम प्रयास किए जाते रहे हैं। इक्कीसवीं सदी में अब इन प्रयासों में रंग भरते हुए भी देखे जा सकते हैं। चूंकि चिकित्सा शिक्षा विशेषज्ञता की मांग करता है इसलिए इस क्षेत्र में मानव संसाधन उपलब्ध कराना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। चिकित्सा शिक्षा विभाग राज्य भर में फैले 15 राजकीय क्षेत्र के और 8 निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों के अलावा 16 डेंटल कॉलेजों के साथ ही नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेजों का प्रबंधन भी करता है।

जब आज़ादी मिली तो 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले राजस्थान में सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज जयपुर में हुआ करता था परंतु आज सरकारी और निजी क्षेत्र को मिलाकर 23 मेडिकल कॉलेज स्थापित हो चुके हैं। शीघ्र ही राजकीय क्षेत्र में 16 नए मेडिकल कॉलेज भी तैयार हो जाएंगे।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत राज्य में मेडिकल सुविधाओं में निरंतर सुधार को लेकर काफी संवेदनशील हैं। मुख्यमंत्री के साथ ही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा के प्रयासों का नतीजा है कि राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां लगभग हर जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज होंगे।

राज्य में लगातार बढ़ रही हैं मेडिकल कोर्सेज में सीटें : वर्तमान में राजस्थान के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की कुल 2830 सीटें हैं। इनमें से 1850 सीटें जयपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, झालावाड़ और आरयूएचएस में हैं। 980 सीटें 7 नए खुले मेडिकल कॉलेजों में हैं। इनमें से भरतपुर, भीलवाड़ा, चूरू, डूंगरपुर और पाली मेडिकल कॉलेजों में प्रत्येक में 150 सीट हैं। बाड़मेर और सीकर मेडिकल कॉलेज क्रमश: 130 और 100 सीटों के साथ शुरू किए गए हैं।

राज्य सरकार निजी क्षेत्र को भी अवसरों की समानता उपलब्ध करा रही है। निजी क्षेत्र में 8 मेडिकल और 15 डेंटल कॉलेज स्थापित किए जा चुके हैं। इन कॉलेजों में एमबीबीएस की 1300 और बीडीएस की 1460 सीटें हैं।

वैश्विक महामारी कोरोना के क्रूरतम प्रहारों के बावजूद राज्य के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। पिछले 3 साल के समग्र आंकड़ों को देखें तो राज्य में राजकीय क्षेत्र में एमबीबीएस की सीटों की संख्या 1850 से बढ़कर 2830 हो चुकी है। वहीं पीजी (एमडी, एमएस आदि) की सीटें 1072 से बढ़कर 1255 हो चुकी हैं। इसी तरह बीएससी/एमएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या 715 से बढ़कर 870 की जा चुकी है।

चिकित्सा शिक्षा को समर्पित विश्व–विद्यालय का गठन : राज्य में चिकित्सा शिक्षा की बढ़ती संभावनाओं के समुचित दोहन के लिए जयपुर में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय है। आरयूएचएस अधिनियम–2005 के तहत चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में गुणवत्ता तथा समरूपता लाने के उद्देश्य से आरयूएचएस की स्थापना की गई थी। ये विश्वविद्यालय चिकित्सा शिक्षा के पाठ्यक्रम को लगातार संशोधित एवं उन्नयन करने तथा कई विभागों एवं विषयों में सामंजस्य के साथ अनुसंधान को प्रोत्साहित करता है। साथ ही चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान में विशिष्टता एवं गुणवत्ता के लिए भी प्रयत्नशील है। चिकित्सा शिक्षा निदेशालय की स्थापना मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की दूरदर्शी और संवेदनशील सोच का ही नतीजा है। श्री गहलोत ने अपने पिछले कार्यकाल में वर्ष 2011–12 के बजट भाषण में चिकित्सा क्षेत्र में बेहतर प्रबंधन के लिए चिकित्सा शिक्षा निदेशालय की स्थापना की घोषणा की थी।●

राज्य सरकार का उद्देश्य है कि देश के सबसे बड़े राज्य के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा और भोजन के अधिकार के साथ ही स्वास्थ्य का अधिकार भी प्रदान किया जाए। इसी के अनुरूप राज्य में नि:शुल्क दवा वितरण, नि:शुल्क जांच और चिरंजीवी जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। वर्तमान में राज्य के प्रत्येक लाभार्थी को 5 लाख रुपये तक की स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदान की गई है।

डॉ. रघु शर्मा
चिकित्सा मंत्री, राजस्थान

तकनीकी दुनिया में राजस्थान निर्वाचन आयोग की अभिनव पहचान

हैलो वोटर्स वेब रेडियो

– डॉ . सुधीर सोनी
स्वीप सलाहकार
निर्वाचन विभाग

भारत निर्वाचन आयोग के विविध नवाचार, मतदाता से जुड़ाव के प्रयोग एवं जागरूकता अभियानों के लिए उनका एक विशेष प्रभाग स्वीप कार्य करता है। इसे सिस्टेमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्ट्रोरल प्रोसेस (स्वीप) के रूप में जाना जाता है। इसके माध्यम से निरंतर ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिनसे एथिकल वोटिंग की दिशा में काम किया जा सके। साथ ही मतदान करने वाले व्यक्तियों को सभी प्रकार की सूचनाएं उचित माध्यम और समयबद्ध तरीके से मिल सकें इसका भी प्रयास किया जाता है।

21वीं सदी में सूचना क्रांति और डिजिटल अनुप्रयोगों ने देश को एक नई पहचान दी है। रेडियो इस पहचान का एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। वर्तमान पक्षों में मतदाता चेतना के क्रम में रेडियो को प्रयुक्त किया जाना एक महत्त्वपूर्ण आवश्यकता है। वैसे तो इस कार्य के लिए ऑल इंडिया रेडियो सभी निजी एफएम चैनल, कम्युनिटी रेडियो आदि बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं।

रेडियो ने अपने तरीके से मतदाताओं को जागरूक बनाने में अपनी विशेष भूमिका न केवल निभाई है बल्कि एक अभिनव पहचान भी स्थापित की है। धीरे-धीरे सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल जैसे-जैसे बढ़ा तो उसमें विविध नए प्रयोग भी होने लगे। इसी बीच पूरी दुनिया को वैश्विक महामारी कोविड-19 ने घेर लिया। ऐसे समय में जबकि सुरक्षा भी अपनानी है, दो गज की दूरी भी रखनी है और तमाम सूचनाओं से परिचित भी होना है इसलिए रेडियो फिर से अपनी एक अभिनव

पहचान लेकर आया है। इस बार यह अभिनव परिवर्तन 'वेब रेडियो' के रूप में सामने आया है। भारत निर्वाचन आयोग ने इसी महत्ता को पहचानते हुए 25 जनवरी, 2021 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर अपना एक अभिनव उपादान हैलो वोटर्स वेब रेडियो स्थापित किया है। यह एक माध्यम है जो पूरे देश में संवाद स्थापित करने का एक सेतु भी है और साथ ही साथ प्रत्येक प्रकार की सूचनाओं को मतदाताओं तक पहुंचाने में समर्थ है और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह भी है कि इसे किसी भी समय, किसी भी दिन, कहीं भी प्रयुक्त किया जा सकता है।

इसकी सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इसे श्रोता अपनी सुविधा से किसी भी समय सुन और देख सकता है। साथ ही अपनी विभिन्न शंकाओं के समाधान के लिए भी वह अपना पक्ष रख सकता है। हैलो वोटर्स वेब रेडियो को इस तरीके से बनाया गया है कि यह लोकप्रिय एफएम रेडियो की तरह ही आम आदमी को आकर्षित करता है। यहां मतदाता न केवल मतदान व उससे जुड़ी प्रक्रिया, मतदाता पंजीकरण, मतदाता को मिलने वाली सुविधाएं, मतदाता के अधिकार जैसे मुद्दों पर जानकारी ले सकते हैं साथ ही साथ में उसमें विविध प्रकार के गीत, ड्रामा, आपसी बातचीत, संवाद के लोकप्रिय तत्त्वों से परिचित हो सकते हैं।

इसकी सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि देश के विभिन्न राज्यों की संस्कृतियों का समावेश एक ही जगह पर किया गया है। इससे उनकी लोक संस्कृति, कला, नवाचार और उनके द्वारा किए गए कार्यों का विवरण तो मिलेगा ही साथ ही पूरे देश को एक सूत्र में बांधने की अवधारणा भी इसके माध्यम से पोषित हो सकेगी।

राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो राजस्थान निर्वाचन विभाग की ओर से हैलो वोटर्स वेब रेडियो को विशेष प्राथमिकता दी गई है। राजस्थान की लोक-संस्कृति, कलाएं, भाषा और संस्कृति की अभिनव पहचान है।

यही वजह है कि हैलो वोटर्स वेब रेडियो के माध्यम से न केवल इसे आगे ले जाने में मदद मिलेगी बल्कि राजस्थान जैसे बड़े भू-भाग के दूरदराज के युवा, ग्रामीण, आम मतदाता अपनी बातों को अपनी बोली में, अपने तरीके से समझ सकेंगे। साथ ही कोई मतदाता न छूटे, की दिशा में उनका जुड़ाव व्यापक रूप से होगा तो मतदान को एक विशेष पहचान मिलेगी।●

मां बाड़ी योजना :

घर में अपनों से शिक्षा पा रहे हैं नौनिहाल

–अनुप्रिया
जनसंपर्क अधिकारी

माँ बाड़ी योजना राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही ऐसी योजना है जिसमें हमारे समाज के अनुसूचित जनजाति वर्ग के उत्थान के लिए प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं। यह योजना स्वच्छ परियोजना के माध्यम से संचालित की जा रही है जिसे विशेष रूप से अनुसूचित क्षेत्र में निवासरत अनुसूचित जनजाति व बारां जिले के सहरिया परिवारों के बालक एवं बालिकाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है।

जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन मां बाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत कार्मिक भी स्थानीय निवासी ही होते हैं। इसका सीधा सा प्रभाव यह पड़ता है कि ये बच्चों की जीवनशैली और समस्याओं से भली-भांति परिचित होते हैं।

ऐसे में इनके लिए इन बच्चों की आवश्यकताओं को समझना तथा शिक्षा आदि के क्षेत्र में इनको आने वाली समस्याओं का निराकरण भी आसानी से किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित होने वाले बच्चों की आयु सीमा 6 से 12 वर्ष निर्धारित की गई है। इस आयुवर्ग के जिन बच्चों को प्राथमिक शिक्षा पाने के लिए अपने घर से दूर जाना पड़ता था अब उन्हें इस योजना के तहत उन्हीं के क्षेत्र, गांव में मां बाड़ी केन्द्रों में बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है।

राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना में प्रत्येक मां बाड़ी केन्द्र पर शिक्षा से वंचित 30 बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा के लिए नामांकित किया जाता है। इनमें से बालिकाओं को वरीयता प्रदान कर उन्हें शिक्षित और सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है।

इन केन्द्रों पर नामांकित बच्चों को सरकार द्वारा मां बाड़ी केन्द्रों में निःशुल्क भोजन, अल्पाहार, ड्रेस और पढ़ने लिखने के लिए जरूरी किताबें उपलब्ध कराई जा रही हैं जिससे इनके ज्ञान और शैक्षिक स्तर में वृद्धि हो रही है और इन्हें बेहतर पोषण भी मिल पा रहा है।

मां बाड़ी केन्द्रों का उद्देश्य जनजाति वर्ग की महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के लिए जागरूक करना भी है। इस योजना के तहत इन केन्द्रों में अध्ययनरत बच्चों की माताओं को भी इन केन्द्रों पर होने वाली गतिविधियों से जोड़कर उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। इन माताओं को राज्य सरकार द्वारा भोजन तैयार करने के लिए उचित मानदेय दिया जा रहा है।

राज्य सरकार को इस योजना में विश्वव्यापी संगठन यूनिसेफ का भी सहयोग मिल रहा है जो कि इन मां बाड़ी केन्द्रों में कार्यरत शिक्षा सहयोगियों को नए पाठ्यक्रम के अनुसार बच्चों को शिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण मुहैया करवा रही है जिससे कि ये शिक्षक छात्रों का बेहतर और नवीन ढंग से ज्ञानवर्धन कर सकें। वर्तमान समय में प्रदेश में कुल 1728 मां बाड़ी केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। इनमें से उदयपुर में 357, डूंगरपुर में 325, बांसवाड़ा में 416, प्रतापगढ़ में 324, आबूरोड में 22, पाली में 59, राजसमंद में 12, पिंडवाड़ा में 34, बारां में 14 और जयपुर में 165 केन्द्र संचालित हैं।

मां बाड़ी शिक्षा सहयोगी बनने के लिए कम से कम 8वीं पास होना आवश्यक है। 51,840 आदिवासी बालक और बालिकाओं को वर्तमान में इस योजना का लाभ मिल रहा है। राज्य में इस योजना के तहत 811 डे केयर सेंटर का भी संचालन किया जा रहा है जिसमें 24,330 बालक एवं बालिकाएं लाभान्वित हो रहे हैं। वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा 250 नए मां बाड़ी केन्द्रों की स्थापना की घोषणा की गई है। विभाग द्वारा इन केन्द्रों को खोलने के लिये स्थान चयन की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है।●

करौली

सब्जियों की पैदावार से जीतमल के जीवन में आयी खुशियां

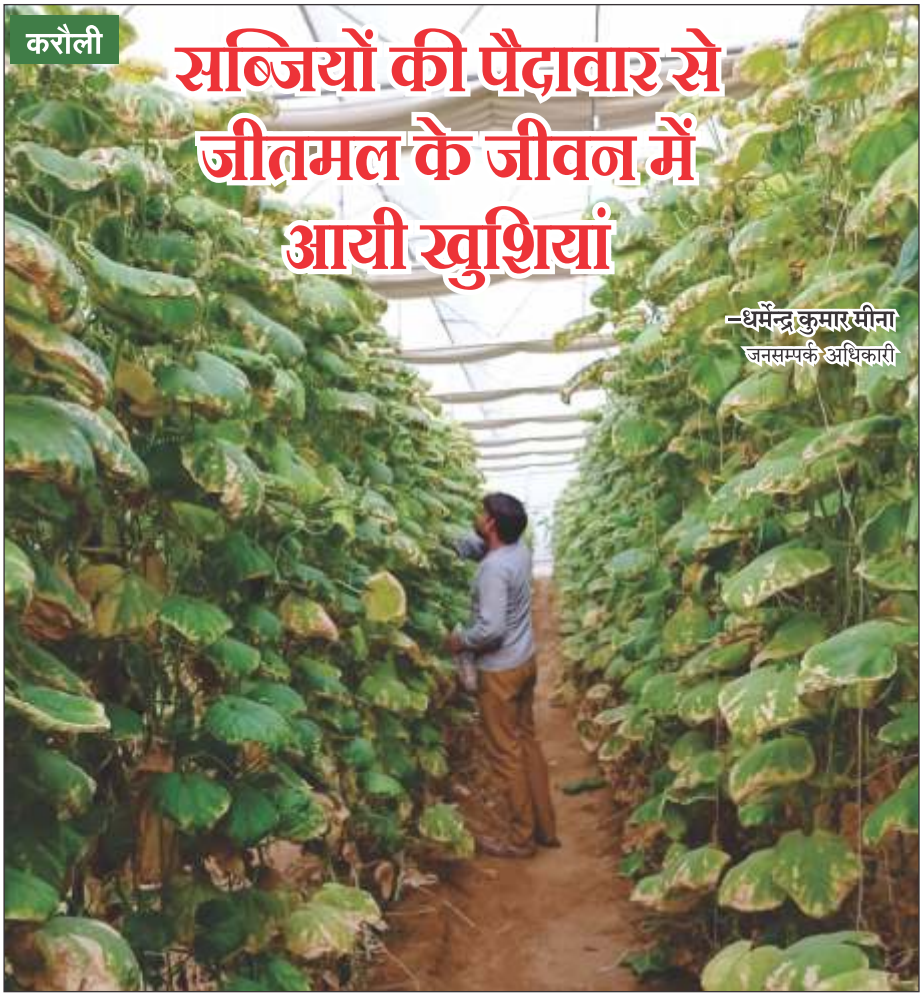

–धर्मेन्द्र कुमार मीना
जनसम्पर्क अधिकारी

करौली जिले की पंचायत समिति श्रीमहावीरजी के कृषक जीतमल सैनी बीएसटीसी और ग्रेजुएशन की उपाधि लेने के पश्चात सरकारी नौकरियों की तैयारी की तलाश में विभिन्न प्रतियोगिताओं की तैयारी कर परीक्षाएं दी लेकिन उसे असफलताओं का ही सामना करना पड़ा, इसी दौरान उनके बड़े भाई का निधन हो गया, जिससे उसका मनोबल टूट गया और घर की जिम्मेदारियां उनके कंधों पर आ गई। उसके पास मौजूद 6-7 बीघा जमीन मे रवि फसलों मे गेहूं, सरसों, चना और खरीफ में बाजरा, तिल, ग्वार आदि फसलें लगाकर 1.5 से 2 लाख रु. कमाने लगा। लेकिन इससे उसके परिवार का जीवन यापन नहीं हो पा रहा था। तभी उनका उद्यान विभाग के अधिकारी से संपर्क हुआ और योजनाओं के बारे मे जानकारी ली। उद्यान विभाग की योजनाओं में उसे ज्ञात हुआ कि सिचांई के लिये ड्रिप फब्बारा बहुत ही फायदेमंद है जिससे पानी और समय दोनों की बचत होती है। लागत कम और मुनाफा अधिक की सोच कर फसलों के साथ सब्जियां बोने लगा और उसे धीरे-धीरे फायदा होने लगा। उद्यान विभाग द्वारा दी गई सलाह और लो टनल, मल्च के साथ सिचांई के लिये ड्रिप फब्बारा के माध्यम से पानी और समय की बचत हुई उसी का परिणाम है कि वह वर्ष मे 5-6 लाख रुपए कमाने लग गया है। वह अब जैविक तरीके से सब्जी का उत्पादन कर रहा है और सब्जियों को उचित मूल्य पर बेच कर लाभ कमा रहा है। सर्दियों में पत्तागोभी, फूलगोभी, पालक, सेंगरी, टमाटर, बैंगन सहित अन्य सब्जियों के साथ चुकन्दर, ग्वार, प्याज, मिर्च, ककड़ी के साथ भिंड़ी, टिंडे भी उगाकर लाभ कमा रहा है। उसका कहना है कि वह पहले एक लाख रुपए भी बडी मुश्किल से कमा पाता था और घर से लागत लगाने के बाद बड़ी मुश्किल से खर्चा चल पाता था। आज वह एक साल में 5 से 6 लाख रुपए तक का लाभ कमा रहा है और अपने परिवार का जीवनयापन अच्छी तरह से कर पा रहा है। उसके जीवन मे उद्यान विभाग की इस योजना के कारण खुशियां लौट आयीं। उसने सभी किसानो से यह अपेक्षा भी की है कि जैविक खेती व कम पानी मे फसल उगाकर अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं।

4 हजार वर्गमीटर ग्रीन हाउस से 70 बीघा के बराबर आय

खेडा जमालपुर के कृषक श्री अनूप कुमार संरक्षित खेती से जुड़ने के बाद 4 हजार वर्गमीटर क्षेत्र में 70 बीघा जितनी आय ले रहे है। किसान श्री अनूप की माने तो आय बढ़ाने का इससे अच्छा जरिया कोई भी नहीं है। पॉली हाउस में खीरे की फसल से सालाना 9 लाख रुपये की आय हो रही है। साथ ही अमरूद की बागवानी के साथ साथ ओपन फील्ड में टमाटर, मिर्च का उत्पादन भी लिया जा रहा है। श्री अनूप सिंह प्रगतिशील किसानों में जिला स्तर पर सम्मानित हो चुके हैं।

तीन साल पहले तक श्री सिंह साधारण किसान थे, लेकिन अब जिले के दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। अब इनसे दूसरे कृषक संरक्षित खेती का ज्ञान हासिल कर रहे हैं। साथ ही आय बढ़ाने में वैज्ञानिक कृषि तकनीक के महत्त्व को समझ रहे हैं।

तीन साल पहले 5 बीघा क्षेत्र में अमरूद का बगीचा स्थापित करने के बाद इस साल 60 हजार रुपये की आय प्राप्त की है। पशुधन से भी वे प्रतिदिन 15 से 20 लीटर दुग्ध का उत्पादन कर आय सृजित कर रहे हैं।

चूरू

फार्म पोंड में बरसाती पानी एकत्र कर उपजाए 20 टन तरबूज

चूरू जिले में खासोली के किसान श्री शिवराम सिंह भाखर ने फार्म पोंड बनाकर किया बरसाती पानी का उपयोग, चार सौ फलदार पौधे, समूचे खासोली गांव और चूरू शहर को ऑर्गेनिक सब्जी खिलाने का सपना

– कुमार अजय
सहायक निदेशक (जनसम्पर्क)

बरसात के समय गांव के जिस पानी के इकट्ठा होकर आने से सारे खेत में खड़ी फसल नष्ट हो जाती थी, फॉर्म पोंड बनाकर खासोली के किसान ने उसी बरसाती पानी को एकत्र कर पिछले सीजन में 20 टन तरबूज का उत्पादन किया। परेशानी का सबब रहा यह बरसाती पानी उनके लिए फायदे का सौदा बन गया।

यह सब संभव हुआ किसान श्री शिवराम सिंह भाखर के अनुभव, दूरदर्शिता भरे प्रयासों एवं कृषि विभाग की फॉर्म पोंड योजना से। सहकारिता विभाग में व्यवस्थापक पद से रिटायर हुए श्री सिंह बताते हैं कि वे मूलत: किसान परिवार से हैं तथा ग्राम सेवा सहकारी समिति के जरिए किसानों के ही बीच रहे। ऐसे में रिटायरमेंट के बाद खेती-किसानी से ही जुड़ने का मन हुआ और उन्होंने ऑर्गेनिक खेती का निर्णय लिया। समस्या यह थी कि गांव के नजदीक खेत होने से गांव के कुछ घरों और गलियों का पानी उनके खेत में इस तरह तेज बहाव से आता था कि सारी फसल नष्ट हो जाती थी। ऐसे में कृषि अधिकारियों ने उन्हें खेत तलाई बनाने की सलाह दी और उस पर मिल रही सब्सिडी के बारे में बताया। इस पर उन्होंने वर्ष 2020-21 में ही खेत तलाई का निर्माण कराया जिस पर विभाग की ओर से 90 हजार रुपए का अनुदान भी मिला। एक सौ फीट लंबी, इतनी ही चौड़ी तथा 15 फीट गहरी खेत तलाई के निर्माण पर करीब सवा तीन लाख रुपए खर्च हुए जिसकी क्षमता तीस लाख लीटर है। इसके बाद उन्होंने ड्रिप इरिगेशन से खेती शुरू की और पहली ही बार में तरबूज की बंपर पैदावार हुई। महज चार बीघा की खेती में उन्होंने करीब 20 टन तरबूज बेचे। इसके अलावा नींबू, माल्टा, किन्नू आदि के 400 पेड़ लगाए जो शत-प्रतिशत जीवित हैं तथा आने वाले कुछ वर्षों में पैदावार देंगे। इस वर्ष भी उन्होंने बैंगन, हरी मिर्च, चंवला, खीरा, तुरई, टिंडा, मतीरा, ग्वार आदि बोए हैं जो आने वाले एक-डेढ़ माह में आय देना शुरू कर देंगे। वे इस खेती में किसी प्रकार का पेस्टीसाइड इस्तेमाल नहीं करते। उनका सपना है कि आने वाले दिनों में पहले अपने पूरे खासोली गांव और फिर चूरू शहर को ऑर्गेनिक सब्जी सप्लाई कर सकें। इसके लिए वे पास ही पड़ी अतिरिक्त जमीन को भी तैयार करवा रहे हैं जिसमें बूंद-बूंद सिंचाई प्रणाली से फल व सब्जियां उपजा सकें। वर्तमान में सब्जियों, फलों में पेस्टीसाइड के उपयोग के कारण वे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं रहती हैं तथा उनके उपभोग से व्यक्ति अनेक बीमारियों का शिकार हो जाता है ऐसे में बेहतर उत्पाद उपजाने के लिहाज से ऑर्गेनिक खेती ही एक मात्र मार्ग है।

खासोली गांव का ट्यूबवेल का पानी सब्जियों की खेती के लिहाज से ज्यादा अच्छा नहीं है। यहां के पानी का पीएच 8.5 तथा ईसी 4.0 है। ऐसे में बरसाती पानी इकट्ठा करने से सब्जियां उगाना संभव हो गया है। इस किसान से प्रेरणा लेकर दूसरे लोग भी फॉर्म पोंड का लाभ उठा सकेंगे। ●

मनरेगा : आज के जीवनयापन से निर्माण ''कल'' का

- **कोरोना की दूसरी लहर के लॉकडाउन के खुलने के बाद जिले के ग्रामीण क्षेत्र में जिन्दगी फिर पटरी पर लौटने लगी है।**
- **कोविड के संकट भरे समय में ग्रामीणों के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना एक बार फिर मजबूत सहारा बनकर उभरी है।**
- **योजना में ऐसे उपयोगी निर्माण हुए जो आने वाली पीढ़ियों के लिए वरदान सिद्ध होंगे।**

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना गांव और ग्रामीणों के लिए एक जीवनदायिनी योजना है लेकिन इसका महत्त्व केवल आज इस योजना के जरिए जीवनयापन करने वाले जरूरतमंद परिवारों की मदद से कहीं अधिक है। कोरोना की दूसरी लहर से बचाव के लिए कुछ समय के लिए नरेगा साइट्स पर काम रुका लेकिन अब यह काम दोबारा शुरू हो चुका है। इस वर्ष इस योजना में हुए कई कार्यों ने न केवल जरूरतमंद ग्रामीणों को आर्थिक सम्बल दिया, पलायन रोका बल्कि गांव, प्रकृति और आने वाली पीढ़ियों के लिए उपयोगी आधारभूत संरचना का निर्माण किया जिनका फायदा सालों-साल मिलता रहेगा।

जमवारामगढ़ पंचायत समिति में जयपुर जिला मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम बोबाड़ी विराटनगर, जमवारामगढ़ और शाहपुरा उपखण्ड की सीमाओं से सटा हैं। बोबाड़ी ग्राम पंचायत में वर्तमान में मनरेगा के अन्तर्गत आईटी सेंटर भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र में पौधारोपण के लिए गड्ढे खुदवाने, स्कूल के खेल मैदान विकास कार्य, श्मशान घाट विकास कार्य, चरागाह भूमि का विकास कार्य, तलाई खुदाई मय

– रजनीश शर्मा
उप निदेशक (जनसम्पर्क)

दीवार व पिचिंग कार्य, श्मशान विकास कार्य, ग्रेवल रोड निर्माण और विद्यालय के खेल मैदान के निर्माण जैसे कार्य करवाया जा रहे हैं।

रोजगार के हर इच्छुक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के अकुशल काम की गारंटी देने वाली यह योजना ''जितना काम, उतना दाम, पूरा काम, पूरा दाम'' के उद्देश्य को पूरा करती है। महिलाओं एवं कमजोर समुदाय को आर्थिक सुदृढ़ करने में मनरेगा की अहम भूमिका है। इस योजना ने कोविड-19 के संकट भरे समय में गरीबों एवं कमजोर समुदाय का सहारा बनकर उन्हें एक नया जीवन प्रदान किया है।

इस योजना में इन मजदूरों को कार्यस्थल पर छाया, पेयजल, आवश्यक दवाइयां एवं क्रेच सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। कोविड के दौरान सेनिटाइजर, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया। मांग पर 15 दिन के अन्दर रोजगार उपलब्ध न कराने पर बेरोजगारी भत्ता और मजदूरी का भुगतान 15 दिवस में नहीं होने पर क्षतिपूर्ति राशि का भी प्रावधान है।

अब नरेगा का ही सहारा

65 वर्षीय कान्ति देवी बाबोड़ी ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत स्कूल के खेल मैदान के कार्य में लगी हुई हैं। कान्ति बताती है कि मनरेगा के कारण हो रही आय से ही उनका घर चल रहा है। घर में बेटे-बहू की आकस्मिक मौत ने उन्हें अन्दर तक तोड़ दिया था। ऐसे में दोनों पोते छोटे होने के कारण उन्हें बहुत सारी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। उनके पति भी अक्सर बीमार रहते हैं तथा एक पोता दिव्यांग है। मनरेगा के कारण उनका चूल्हा जल रहा है और वे अपना जीवनयापन कर पा रहे हैं।

नरेगा के सहारे जीवनयापन

पौधे लगाने के लिए महानरेगा में गड्ढे खोदने के काम में लगी पतासी की भी कुछ ऐसी ही कहानी है। उसका एक बेटा दिव्यांग है और दूसरा बेटा छोटे-मोटे काम करता है। पति की उम्र अधिक होने के कारण वही काम पर आती है और नरेगा योजना के ही सहारे उसका भी घर चल रहा है।

तलाई खुदी तो तीन वर्ष की पेयजल समस्या हुई दूर

ग्राम पंचायत बोबाड़ी के ग्राम जयसिंहपुरा में पिछले 3 वर्षों से गर्मियों में पीने के पानी की विकट समस्या हो रही थी। ग्रामवासियों व पशुधन को पीने का पानी गांव की महिलाओं को दूर से लाना पड़ता था। देहलीधाम, बोबाड़ी (मॉडल तालाब) के निर्माण से ग्रामीणों को इस समस्या से निजात मिली है। तलाई खुदाई मय दीवार एवं पिचिंग कार्य एक माह पहले ही पूर्ण हुआ है। पिछले दिनों आई बारिश से इसमें पानी भी आ गया है। कार्य पूर्ण होने पर गांव में पानी का जल स्तर बढ़ा तथा पशुओं के पीने के पानी की समस्या दूर हुई है। इस तलाई में लम्बे समय से पानी भरा रहने के कारण मछली पालन से रोजगार का नया अवसर मिलने की संभावना भी दिखाई देने लगी है।

बच्चों के शारीरिक विकास के लिये खेल मैदान का निर्माण

पंचायत समिति आंधी की ग्राम पंचायत बिरासना के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में खेल मैदान रनिंग ट्रेक का निर्माण एवं पौधारोपण करवाया गया है। इससे पहले ग्राम बिरासना में बच्चों के रनिंग करने व खेलकूद के लिए कोई स्थान उपलब्ध नहीं था। वर्तमान में मनरेगा द्वारा खेल मैदान का निर्माण होने से विद्यालय में पढ़ने वाले व गांव के अन्य बच्चों को रनिंग करने के लिए ट्रेक तो मिला ही, साथ ही ग्राम में युवाओं द्वारा पुलिस, सेना में जाने के लिए दौड़ एवं शारीरिक दक्षता प्रतियोगिता का अभ्यास करने में यह ट्रेक उपयोगी सिद्ध हो रहा है।

गजराज की गूंज से गुलजार : हाथी गांव

कोरोनाकाल में राज्य सरकार ने दी आर्थिक सहायता

– बनवारी लाल यादव
जनसम्पर्क अधिकारी

गांवों के देश भारत में यूं तो लाखों गांव हैं लेकिन जयपुर का हाथी गांव इनमें सबसे बेमिसाल है। आमेर के कुंडा के पास बसा यह गांव उन हाथियों का ठिकाना है जो देसी-विदेशी सैलानियों को अपनी पीठ पर लादकर ऐतिहासिक आमेर किले की सैर कराते हैं। ये एशिया का दूसरा और भारत का एकमात्र हाथी गांव है। यहां करीब 90 हाथी और उनके महावत रहते हैं। दुनिया के कोने-कोने से जयपुर आने वाले सभी सैलानियों की चाहत होती है कि हाथी पर सवार होकर वो आमेर किले तक सैर करें। 120 बीघा धरती पर फैले इस गांव में जब सजे-धजे हाथियों का काफिला निकलता है तो सैलानी इन हाथियों की पीठ पर सवार होने के लिए मचल उठते हैं। हाथियों की अठखेलियां..सूंड में पानी भरकर मस्ती करते गजराज..और मतवाले महावतों का नज़ारा देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। हाथी मालिकों और महावतों की मानें तो हाथियों के लिए यह गांव बड़ी नियामत हैं।

राज्य सरकार द्वारा बसाए गए इस हाथी गांव की कई ऐसी बातें हैं जो हमारा दिल जीत

लेती हैं। यहां हाथियों और महावतों के लिए अलग-अलग कंपाउंड बने हुए हैं जिसमें हाथी निवास, महावत का कमरा और किचन भी है। यहां हर ब्लॉक में तीन क्वार्टर हैं, हर क्वार्टर में हाथी के लिए एक बड़ा निवास है जहां हाथी आराम कर सकें..और सुस्ताने के साथ नींद भी ले सकें। हाथी के लिए एक किचन जहां महावत उसके लिए खाना तैयार करते हैं और इसी क्वार्टर में महावत के लिए एक खुला हवादार कमरा, जहां महावत आराम से अपने परिवार के साथ रह सके। हाथियों की मस्ती का खयाल रखने के लिए यहां एक खूबसूरत तालाब भी है जिसमें अठखेलियां करते गजराज और भी दिलकश नजर आते हैं। महावत रोज शाम यहां हाथी को नहलाने लाते हैं जिससे वो तरोताजा महसूस कर सकें।

विश्वभर में आमेर ही ऐसी अकेली हेरिटेज साइट है जहां पर हाथी की सवारी होती है। लेकिन कोरोना महामारी के चलते हाथी मालिकों का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है क्योंकि एक हाथी पर करीब तीन हजार रुपए रोज का खर्चा आता है। हाथीपालक परिवारों को राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान लॉकडाउन और पर्यटन गतिविधियों पर प्रतिबंधों के कारण हाथीपालकों की आजीविका प्रभावित होने के क्रम में उनकी आर्थिक मदद का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने निर्देश दिए हैं कि हाथी सवारी में लगे 85 हाथियों के लिये मुख्यमंत्री सहायता कोष के अंतर्गत 'कोविड-19 राहत

कोष' से कुल 57.37 लाख रुपये की आर्थिक मदद हाथी कल्याण संस्थान, जयपुर के माध्यम से दी जाए। यह सहायता राशि 17 अप्रैल से 31 मई, 2021 की अवधि के लिये 1500 रुपये प्रति हाथी प्रतिदिन की दर से देय होगी। गौरतलब है कि 17 अप्रैल से आमेर महल एवं हाथी गांव में हाथी सवारी बंद होने के कारण महावत परिवार विषम आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रहे हैं जिसके चलते यह सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया और इसके लिए स्वीकृति भी जारी कर दी गई है। बीते वर्ष भी कोरोना महामारी के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन तथा अन्य आवागमन प्रतिबंधों के कारण पर्यटन गतिविधियां प्रभावित होने से हाथीपालक परिवारों के समक्ष आर्थिक संकट रहा। मुख्यमंत्री ने तब भी हाथियों के भरण-पोषण एवं उन पर निर्भर परिवारों के सहयोग के लिए मार्च, 2020 से दिसम्बर, 2020 की अवधि के लिए हाथी कल्याण संस्थान, जयपुर को 4.21 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि आवंटित की थी।●

फिट राजस्थान हिट राजस्थान

-प्रवीण प्रकाश चौहान
जनसम्पर्क अधिकारी

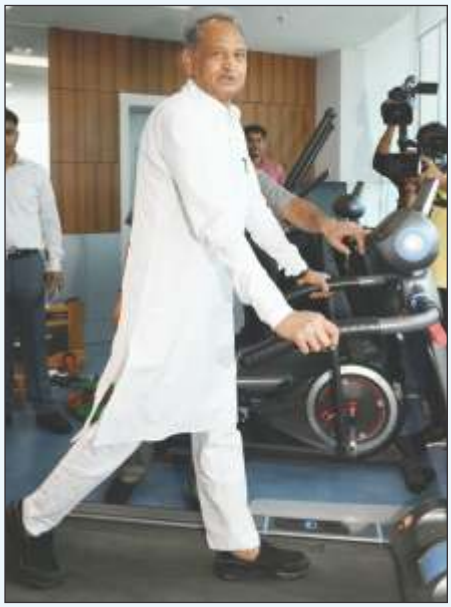

राज्य सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश में खेल वातावरण एवं आधारभूत सुविधाएं विकसित कर रही है। मुख्यमंत्री ने 'फिट राजस्थान हिट राजस्थान' की थीम पर प्रदेश के प्रतिभावान खिलाड़ियों के हित में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं।

अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की बढ़ी इनामी राशि

मुख्यमंत्री ने ओलम्पिक, एशियाई और कॉमनवेल्थ जैसे अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में पदक जीत कर राज्य का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को दी जाने वाली पुरस्कार राशि में तीन से चार गुना तक बढ़ोतरी का ऐलान किया है। ओलम्पिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को दी जाने वाली 75 लाख रुपये की राशि को बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये, रजत पदक जीतने पर दी जाने वाली राशि को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये, कांस्य पदक जीतने वालों को 30 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दी गई है।

इसी प्रकार एशियाई खेलों एवं कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर प्रदेश के खिलाड़ियों को दी जाने वाली राशि को 30 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये, रजत पदक जीतने पर मिलने वाली राशि को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 60 लाख रुपये एवं कांस्य पदक जीतने पर दी जाने वाली राशि 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दी गई है।

मुख्यमंत्री ने 18 अक्टूबर, 2020 को ओलम्पिक, एशियाई और राष्ट्रमंडल जैसे अन्तर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में अपने उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन से देश एवं प्रदेश का नाम रोशन करने वाले राजस्थान के मूल निवासी 13 खिलाड़ियों को इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में 25-25 बीघा भूमि आवंटित करने का महत्त्वपूर्ण फैसला किया था। उन्होंने पदक जीतने वाले 5 खिलाड़ियों को निःशुल्क एवं देश का प्रतिनिधित्व करने वाले 8 खिलाड़ियों को आरक्षित दर पर भूमि आवंटन की घोषणा की।

खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में आरक्षण

राज्य सरकार ने प्रदेश के युवाओं में खेलों के प्रति जागरूकता लाने के लिए राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने की योजना शुरू की है। इसके तहत राज्य के विभिन्न विभागों में राष्ट्रीय स्तर के खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को 2 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए ''सेवा नियम 2013'' में संशोधन किया गया है। संशोधन के तहत अब राज्य के 56 विभागों में खिलाड़ियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। पहले यह आरक्षण राज्य के 52 सरकारी विभागों में ही प्राप्त होता था। राष्ट्रीय स्तर के खेलों में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने की योजना शुरू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है।

राज्य सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में सीधी नियुक्ति दिये जाने हेतु राजस्थान आउट ऑफ टर्न अपॉइन्टमेंट टू स्पोर्ट्स मेडल विनर्स रूल लागू किया है। इस नियम के तहत 29 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। इस फैसले के बाद राज्य में न केवल खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा बल्कि प्रदेश में खेलों के स्तर में भी सुधार होगा। श्रेणी 'क' के अन्तर्गत 11 खिलाड़ियों को राजस्थान पुलिस सेवा, राजस्थान आबकारी सेवा, राजस्थान वन सेवा, राजस्थान शिक्षा विभाग एवं तकनीकी अभियांत्रिकी सेवा में नियुक्ति की घोषणा की गई। इनमें से 6 खिलाड़ियों को उप अधीक्षक पुलिस और 5 खिलाड़ियों को सहायक वन संरक्षक के पद पर, वहीं श्रेणी 'ख' में 11 खिलाड़ियों को पुलिस उप निरीक्षक, एक खिलाड़ी को आबकारी रक्षक, 5 खिलाड़ियों को क्षेत्रीय वन अधिकारी और एक खिलाड़ी को शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक-द्वितीय के पद पर नियुक्ति की घोषणा की गई।

राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलों में राज्य व देश का प्रतिनिधित्व कर चुके राज्य के 153 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी प्रदान करने का फैसला किया है। इसके तहत ग्रेड-ए में 2, ग्रेड-बी में 5 तथा ग्रेड-सी में 146 खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति दी जाएगी। राज्य सरकार ने खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं मे भाग लेने पर मिलने वाले दैनिक भत्ते को दोगुना करने का निर्णय किया है।

राजस्थानी खिलाड़ियों पर रहेगी विशेष नजर

टोक्यो (जापान) में प्रस्तावित ओलम्पिक व पैरा-ओलम्पिक में प्रदेश के खिलाड़ी सुश्री अपूर्वी चंदेला (निशानेबाजी), श्री दिव्यांश सिंह पंवार (निशानेबाजी), श्री अर्जुन लाल जाट (नौकायन), सुश्री भावना जाट (एथलेटिक्स), श्री सुंदर गुर्जर (एथलेटिक्स), श्री देवेन्द्र झांझड़िया (एथलेटिक्स), श्री कृष्णा नागर (बैडमिंटन) एवं सुश्री अवनी लेखरा (निशानेबाजी) देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए चयनित हुए हैं।●

जनजाति का महाकुंभ : बेणेश्वर मेला

जनआस्था धाम पर जुटते हैं लाखों श्रद्धालु
बहुरंगी जनजाति संस्कृति की दिखती है झलक, परंपरागत आयोजनों की रहती है धूम

– छाया चौबीसा
सहायक निदेशक (जनसम्पर्क)

डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा की सीमा रेखा पर अवस्थित 'वागड़ प्रयाग' के नाम से विख्यात तथा सोम–माही–जाखम के मुहाने पर स्थित पवित्र बेणेश्वर धाम पर प्रतिवर्ष माघ माह में लगने वाला वागड़ का प्रसिद्ध 'जनजाति महाकुंभ' बेणेश्वर मेला, लोक संस्कृति के विविध आयामों का दिग्दर्शन कराने वाला एवं बहुरंगी लोक संस्कृतियों के संगम स्थल का साक्षी है।

बहुरंगी जनजाति की दिखती है झलक

अपनी आदिम संस्कृति की विशिष्टताओं के लिए सुविख्यात वागड़ प्रयाग के इस मेले में पारम्परिक परिधानों में सजे और अल्हड़ मस्ती में झूमते–गाते जनजाति वाशिंदों के लोक तरानों से सम्पूर्ण फ़िजा लोक सांस्कृतिक उल्लास के रंगों से सराबोर हो जाती है। लोक संत मावजी महाराज की तपोस्थली पावन धाम बेणे का टापू पर प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इस मेले में राजस्थान, गुजरात और मध्यप्रदेश के अलावा देश–विदेश से आने वाले पर्यटकों तथा अन्य प्रदेशों से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के आस्था का ज्वार सहज ही दृष्टव्य होता है। कई वर्ग किलोमीटर फैले संगम तटों पर विभिन्न क्षेत्रों से उमड़ने वाले जन सैलाब की निरन्तरता देर रात तक देखने को मिलती है।

अल सुबह से शुरू अस्थि विसर्जन का दौर

माघ माह की एकादशी से शुरू होने वाले इस पंद्रह दिवसीय मेले में वैसे तो लोग एक माह पूर्व से ही आना शुरू हो जाते हैं परंतु मुख्य मेला माघ पूर्णिमा के पवित्र दिन होता है। सर्द अल सुबह के हल्के कोहरे और धुंध के बीच हजारों–हजार मेलार्थियों द्वारा अपने दिवंगत परिजनों के मोक्ष कामनार्थ आबूदर्रा स्थित संगम तीर्थ विधि–विधान के साथ त्रिपिण्डीय श्राद्ध आदि उत्तरक्रियाएं पारंपरिक एवं धार्मिक अनुष्ठानों के साथ करते हुए जलाञ्जलि देते हैं। कई हजार लोग अपने पूर्वजों के मोक्ष कामना से उत्तरक्रियाएं पूरी कर उऋण होने का एहसास करते हैं। मेलार्थी नदी के घाटों, संगम तटों तथा शिलाखण्डीय

टापूओं पर सरकण्डे जलाकर देसी भोजन बाटी-चूरमा का भोग लगाकर परिजनों के साथ सामूहिक भोज का आनंद लेते हैं।

देव प्रतिमाओं को नमन् के साथ मेले का लुत्फ

बेणेश्वर धाम के मुख्य मन्दिर राधा-कृष्ण देवालय पर संत मावजी महाराज की जयन्ती माघशुक्ल ग्यारस को महन्त अच्युतानंद द्वारा सप्तरंगी ध्वज चढ़ाने से शुरू होने वाला यह मेला दिन प्रतिदिन उभार पर रहता है। दूर-दूर से आए भक्त, साद सम्प्रदाय के भगत, साधु-संत, महंत के साथ ही पर्यटक मन्दिर परिसरों तथा संगम तटों पर यत्र-तत्र डेरा डाले धार्मिक एवं आध्यात्मिक आनन्द में गोते लगाते रहते हैं। मेलार्थी अपने परिजनों के साथ सामूहिक स्नान एवं भोज के बाद बेणेश्वर शिवालय, राधा-कृष्ण मन्दिर, वाल्मीकि मन्दिर, ब्रह्मा मन्दिर, हनुमान मंदिर आदि देवालयों में जाकर देव-दर्शन, पूजा-अर्चना आदि धार्मिक क्रियाकलापों को सम्पन्न करते हैं। मेला बाजार में वागड़ अंचल के लघु उद्योगों एवं कुटीर उद्योगों की जीवन्त झांकी दिखाई देती है। मेला स्थल पर स्थानीय पारम्परिक एवं कलात्मक वस्तुओं के साथ ही अन्य सामान की लगी दुकानों पर जमकर खरीददारी कर मेले का लुत्फ उठाया जाता है वहीं रंगझूलों में बैठकर हवा में तैरने का आनन्द भी लेते हैं।

पालकी यात्रा व शाही स्नान मुख्य आकर्षण

मेले का मुख्य आकर्षण निष्कलंक भगवान एवं महन्त की पालकी यात्रा एवं संगम पर महंत का शाही स्नान है। मावजी महाराज की जन्मस्थली साबला के हरि मन्दिर से गाजे-बाजे और ढोल-नगाड़ों के साथ निष्कलंक भगवान एवं महंत अच्युतानंद की पालकी यात्राएं निकलती है। सैकड़ों धर्मध्वजाओं, भजन-कीर्तन, गाजे-बाजे एवं रासलीला के मनोहारी दृश्यों से भरपूर इस पालकी यात्रा में भक्तगण आनंद लेते है। रास्ते भर पालकी यात्रा का ग्रामीणों द्वारा भावभीना स्वागत किया जाता है। इस दौरान समूचा मेला स्थल संत मावजी की जय-जयकार से गूंज उठता है। पालकियां राधाकृष्ण मंदिर पहुंचती हैं जहां महंत द्वारा देव दर्शन किये जाते हैं। इसके बाद पुन: हजारों भक्त पालकियों को लेकर जलसंगम तीर्थ 'आबूदर्रा' की ओर बढ़ते हैं जहां महन्त जल तीर्थों का आह्वाहन करते हैं और मावजी महाराज सहित बेणेश्वर के आद्य महन्तों का स्मरण करते हुए पारंपरिक अनुष्ठानों के साथ स्नान किया जाता है।

परम्परागत आयोजनों की धूम

बहुप्रसिद्ध एवं क्षेत्र की पहचान बन चुके 'गैर' नृत्य प्रतियोगिताओं में वागड़ के अलावा आसपास के जिलों एवं अन्य राज्यों से आए लोगों का उमड़ता हुजूम, एक साथ लोक वाद्य यंत्रों पर गूंजती थापे और गैर नृत्य पर एक साथ उठते कदम ताल पूरी फिज़ा को माघ माह में भी फ़ाल्गुनी होने का अहसास कराते हैं। स्थानीय खेल की परंपरागत प्रतियोगिताओं में उमड़ती अथाह जनमेदीनी जहां प्रतिभागियों का हौसला अफजाई करती है वहीं अपने दल के सदस्यों के जीतने पर 'हा-हूं-हुर्रे' की जोरदार ध्वनियों से खुशियां भी मनाई जाती हैं।

सांस्कृतिक संध्या में दिखती है संस्कृति

पवित्र तीर्थ स्थल पर पूर्णिमा की धवल चांदनी में जलसंगम में बिखरती रश्मियों के बीच लोक कलाकारों की एक से बढ़कर एक दी जाने वाली शानदार प्रस्तुतियों में संस्कृति का उल्लास समाहित होता है। जिला प्रशासन एवं पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में तीन दिवसीय रात्रिकालीन सांस्कृतिक संध्या के तहत देश के विभिन्न भागों से आए राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के ख्यातनाम कलाकारों द्वारा मनोहारी प्रस्तुतियों से हर शाम एक यादगार शाम बन जाती है ।

भजनों से मिलती है आध्यात्मिक ऊंचाई

मेले में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग एवं खेल विभाग के तत्वावधान में विविध सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं खेलकूद प्रतियोगिताओं के तहत भजन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है। भक्तों एवं संतों के भजनों से वातावरण भक्ति से सराबोर हो कर आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छू लेता है।

बहती है साहित्य की भी रसधारा

बेणेश्वर मेले में साहित्य की भी रसधारा बहती है जिसमें वागड़ी साहित्य कलाकारों द्वारा स्थानीय बोली वागड़ी में संदेश देने वाली साहित्य रचनाओं को प्रस्तुत किया जाता है।●

प्रतिक्रियाएं

सुजस का पर्यावरण विशेषांक प्राप्त हुआ। आई.एफ.एस. श्रीमती श्रुति शर्मा का आलेख बिन संरक्षण सब सून पढ़ा। उन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत ही सटीक सुझाव दिए हैं। विशेषांक इस बार बहुत ही रोचक और पठनीय था। मेरा सुझाव यह है कि सुजस का हर अंक संग्रहणीय हो। इसके लिए जन उपयोगी सामग्री का समावेश हो तो ज्यादा अच्छा होगा।

दिनेश माहेश्वरी, वरिष्ठ पत्रकार, कोटा

राजस्थान सुजस का यह अंक अच्छा लगा। सुजस अंक नई साज-सज्जा के साथ सामने आया। देखने में भी रोचक लग रहा है। आज के अंक में वरिष्ठ पत्रकारों के लेख हैं। श्री संजीव श्रीवास्तव का लेख देखकर बहुत अच्छा लगा। सुजस का यह परिवर्तित रूप वास्तव में देखने लायक है। जिलों के लघु समाचार, चित्र समाचार और पाठकों की टिप्पणियों को भी स्थान दिया है। संपादक डॉ. लोकेश चन्द्र शर्मा एवं उनकी टीम को बधाई और शुभकामनाएं!

अजय नागर, वरिष्ठ पत्रकार, जयपुर

मेरे नाम से पहली बार घर पहुंची ''राजस्थान सुजस'' ने 1960 के दशक में पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग से निकलने वाली ''राजस्थान विकास'' की यादें ताजा कर दी। राजस्थान सुजस ने पूरे राजस्थान में अपनी अलग पहचान बनाई है। सार्थक प्रयास के लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

-एडवोकेट मोहम्मद मुश्ताक जोइया
पूर्व सरपंच एवं पूर्व अध्यक्ष,
सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार, हनुमानगढ़

सुजस का नया अंक पहली बार मेरे डाक पते पर मिला। संग्रहणीय अंक, हमारे जिले की शानदार उपस्थिति। सूचना व जनसम्पर्क विभाग को भी बधाई कि सुजस के सभी अंकों को कड़ी मेहनत, ठेट गांव ढाणी तक जाकर तथ्यात्मक रिपोर्टिंग होती है। हमारे राज्य की अनेकों प्रतिभाओं व नवाचारों का मंच है सुजस। मेरे घर तक सुजस पहुंचाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री को विशेष धन्यवाद। एक सुझाव भी कि इसमें कुछ खेती बाड़ी के लेख राजस्थानी भाषा में हो।

-विनोद स्वामी,
साहित्यकार, परलीका, नोहर, हनुमानगढ़

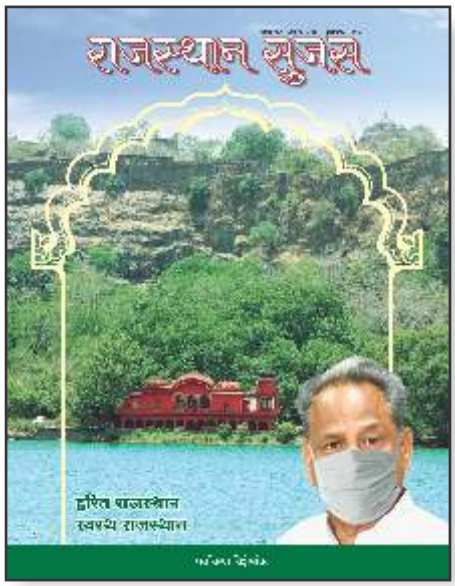

सुजस का जून माह का अंक प्राप्त हुआ। आकर्षक सज्जा, नये कलेवर और विषय विविधता, अनुभवी पत्रकारों और जनसंपर्क अधिकारियों के आलेख इस पत्रिका को रोचक और नया स्वरूप दे रहे हैं। संपादक और पूरी टीम बधाई की पात्र है।

महेश चंद्र शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, जयपुर

सुजस के कलेवर एवं सामग्री में बहुत मेहनत की है। कठोर श्रम का प्रमाण भी सामने मिल रहा है। टंकण एवं मुद्रण की त्रुटियां इस पत्रिका में आम बात हुआ करती थीं लेकिन अब इसकी प्रूफ रीडिंग और प्रोडक्शन को बहुत साधा और सुधारा गया है। सम्पादक और उनकी पूरी टीम को बहुत-बहुत बधाई।

डॉ. डी.एन. पाण्डे, आई.एफ.एस.

राजस्थान सुजस ग्लॉसी पेपर में प्रकाशित बहुत ही सुंदर पत्रिका है। जहां तक मेरी जानकारी है शायद ही किसी अन्य राज्य में सरकार की ओर से प्रदेश की जनता को सूचित करने का ऐसा आकर्षक प्रयास किया जा रहा हो। सुजस का जून, 2021 का अंक बहुत ही ज्ञानवर्धक है। विशेष रूप से अंक में प्रकाशित शुभ्रा शर्मा का पर्यावरण से जुड़े 'राजस्थान के राज्य प्रतीक' आलेख। लेख आकर्षक और ज्ञानवर्धक है। शुभ्रा को बधाई। पत्रिका में चार चाँद लग जाएंगे यदि इसे थोड़ा और रोचक बनाने की पहल की जाए। मनोहारी प्रयास के लिए संपादक और उनकी टीम को बधाई।

राजेन्द्र कुमार राज, वरिष्ठ पत्रकार

सुजस का जुलाई अंक डाक से प्राप्त हुआ। श्री सुरेश बिश्नोई जिला जनसंपर्क अधिकारी हनुमानगढ़ ने फिर से यह मौका दिया। सुजस परिवार का किन शब्दों में आभार प्रकट करूं? इस नवीन अंक में वैसे तो सारी ही सामग्री संग्रहणीय और मन को भाने वाली है लेकिन हनुमानगढ़ के बारे में जानकारी देखकर और अच्छा लगा। घग्घर के सिंचित खेतों के चित्र से तो आंखें हटाए से भी नहीं हट रही थी। इस पत्रिका ने अपने प्रथम अंक से लेकर आज तक जो रुतबा कायम किया है वह बहुत कम पत्रिकाएं कायम कर पाती हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों से लेकर जिज्ञासु पाठकों तक के लिए यह संग्रहणीय है। मुझे यह जानकर सुखद आश्चर्य और खुशी हुई कि अब सुजस पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्यों, जिला परिषद सदस्यों के साथ-साथ अन्य सभी जनप्रतिनिधियों, सरकारी एवं निजी विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, साहित्यकारों, पत्रकारों, सहित जिले के प्रबुद्ध लोगों को डाक द्वारा उनके पते पर भिजवाई गयी है और आगे भी लगातार भिजवाई जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत और सूचना एवं जनसंपर्क निदेशक श्री पुरुषोत्तम शर्मा की सोच, जज्बे और प्रबंधन को सलाम। एक बेहतरीन अंक के लिए संपादक और उनकी पूरी टीम को साधुवाद।

-डॉ. भरत ओला
साहित्य अकादमी नई दिल्ली से पुरस्कृत साहित्यकार,
नोहर, हनुमानगढ़

राजस्थान सुजस 'पर्यावरण विशेषांक' इस बार मुझे डाक द्वारा घर बैठे ही प्राप्त हुआ। माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आर्ट पेपर पर ख़ूबसूरत और प्रेरणाप्रद व ज्ञानवर्धक सामग्री के लिए विभाग और संपादक मंडल को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।

-दीनदयाल शर्मा, बाल साहित्यकार
हनुमानगढ़

Got the sujas magazine by Government of Rajasthan on my address, nice initiative by DIPR, lot of informative topics covered also have got adequate space in the edition.

- Gurpindra Singh (K.P.)
Director, Desert Raiders club,
Hanumangarh

अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

#राजस्थान_सतर्क_है

सावधान
कोरोना के नए रूप डेल्टा प्लस का भारत में प्रवेश

कोरोना का ख़तरनाक डेल्टा प्लस वेरिएंट बीकानेर-राजस्थान में प्रवेश कर चुका है।

- कोरोना का डेल्टा वेरिएंट 85 देशों में फैल चुका है, और अब डेल्टा प्लस वेरिएंट भी फैलने लगा है।
- ये वेरिएंट ज़्यादा तेज़ी से फैलते हैं, फेफड़ों को ज़्यादा जल्दी संक्रमित करते हैं और इनमें मृत्यु दर भी अधिक है।
- वैक्सीनेशन के बाद इंग्लैंड खुलने लगा था पर एक बार फिर मामले बढ़ने लगे हैं।
- इज़राइल में सभी पाबंदियाँ हटा दी गई थीं लेकिन इस नए वेरिएंट के कारण फिर से मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है।
- प्रख्यात अमेरिकी विशेषज्ञ डॉ. फाओची ने कोरोना के नए वेरिएंट को सबसे बड़ा ख़तरा बताया है।

राजस्थान सतर्क है

- कोरोना की दूसरी लहर के दौरान पूरे देश में दवाइयों, अस्पताल में बैड्स व ऑक्सीजन की भारी किल्लत हुई और लोगों को भारी तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। लेकिन आप सबके सहयोग से राजस्थान ने इनके बेहतर प्रबंधन का प्रयास किया।
- हम 2.36 करोड़ प्रदेशवासियों को वैक्सीन की कम से कम एक डोज़ लगा चुके हैं।
- राज्य में वैक्सीन वेस्टेज 0% से भी कम है।
- हमारी रोज़ 15 लाख वैक्सीन लगाने की तैयारी है और हम केंद्र सरकार से हमें पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन देने के लिए लगातार संपर्क में हैं।

कोविड-19 के बदलते वेरिएंट पर प्रभावी निगरानी रखने के लिए एक अभिनव पहल– जयपुर में SMS मेडिकल कॉलेज में **जीनोम सीक्वेंसिंग** सुविधा स्थापित

मास्क ज़रूरी है

पूरे विश्व में विशेषज्ञ इस बात पर एकमत हैं कि वैक्सीन और मास्क ही कोरोना से बचा सकते हैं। अतः जीवन रक्षा के लिए वैक्सीन लगने से पहले और वैक्सीन की दोनों डोज़ लगने के बाद भी आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखने के लिए मास्क बेहद ज़रूरी है।

मास्क पहनने में लापरवाही बेहद घातक है।

राजस्थान मास्क की अनिवार्यता का कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य है

राजस्थान के **'नो मास्क, नो एंट्री'** जागरूकता अभियान की देश-विदेश में सराहना हुई।

कोरोना की तीसरी लहर से आप सबको सुरक्षित रखने के लिए राजस्थान सरकार सजगता से तैयारी कर रही है। चिंता न करें, किंतु सतर्क अवश्य रहें।

1. घर से बाहर निकलें तो हमेशा मास्क पहनें	**2.** आपस में दो गज़ की दूरी बनाए रखें	**3.** अपने हाथ साबुन से धोते रहें या सैनेटाइज़ करें

कोरोना या सरकारी सेवाओं से जुड़ी किसी समस्या के लिए 181 पर फ़ोन करें

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान

राजस्थान सरकार

Postal Regd. No. Jaipur City/413/2020-22
Registered with Registrar of Newspapers of India under R. No. 56175/1991

धरोहर

मेहरानगढ़ किला

जोधपुर

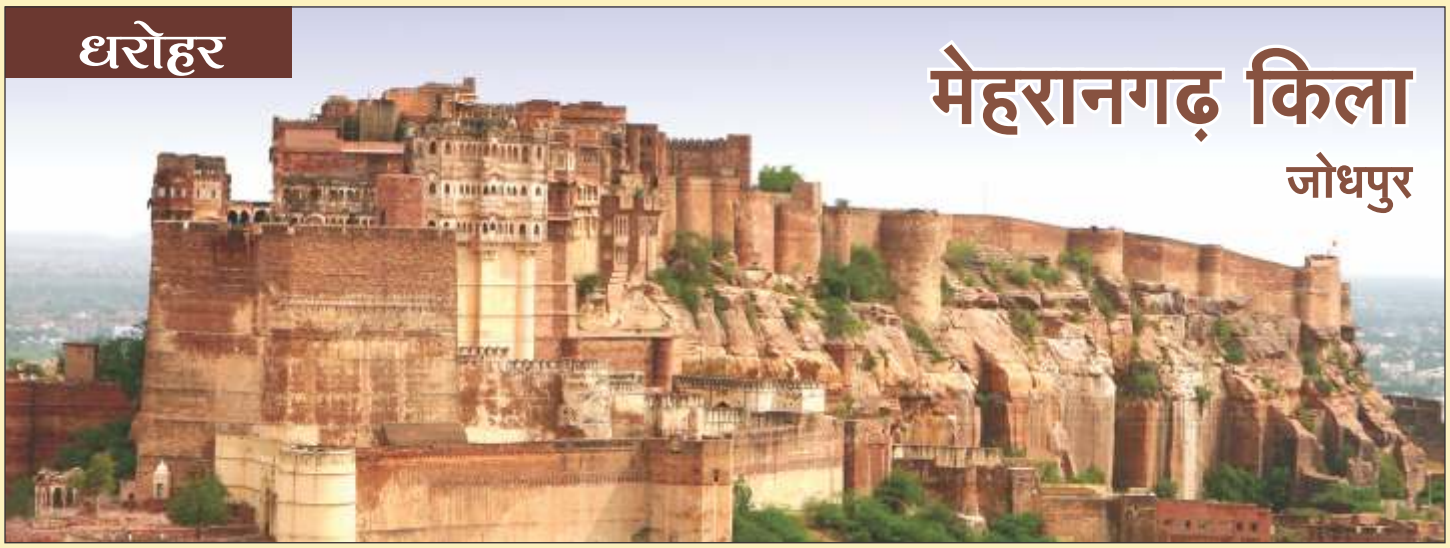

जोधपुर का मेहरानगढ़ का किला भारत के प्राचीनतम किलों में से एक है। जोधपुर के 15वें शासक राव जोधा ने 1459 ई. में चट्टानी पहाड़ी पर इसकी नींव रखी तथा महाराज जसवन्त सिंह (1638–1678) ने इस किले का निर्माण कार्य पूरा करवाया।

15वीं शताब्दी में निर्मित इस ऐतिहासिक किले में आठ द्वार और अनगिनत बुर्जे हैं। यह दस किलोमीटर लम्बी दीवार से घिरा हुआ है।

दुर्ग के दो मुख्य द्वार हैं – लोहापोल व जसपोल। इसके अलावा दुर्ग में फतहपोल, ध्रुवपोल, सूरजपोल, भैरोंपोल आदि अन्य द्वार भी हैं। किले के भीतर कई भव्य महल हैं, इनमें शीशमहल, सिलेखाना, दौलतखाना आदि महलों की स्थापत्य कला अद्‌भुत है।

– श्याम सिंह देवड़ा
वरिष्ठ फोटो पत्रकार

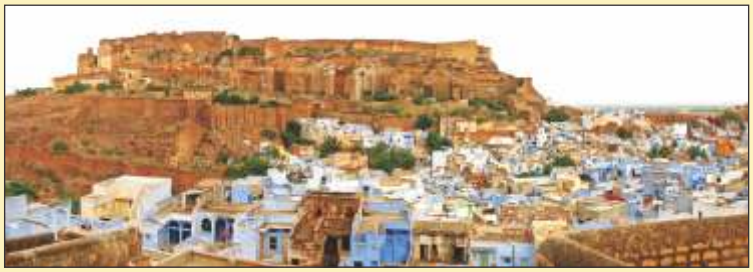

#DIPRRajasthan

प्रकाशक व मुद्रक – सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशक, पुरुषोत्तम शर्मा द्वारा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के लिए, शासन सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) से प्रकाशित • सम्पादक– डॉ. लोकेश चन्द्र शर्मा • मै. पॉपुलर प्रिन्टर्स, एम. डी. रोड़, जयपुर से मुद्रित • राजस्थान सुजस –पृष्ठ 60, लागत मूल्य–29.22 रुपये • वितरण–निःशुल्क • 2,10,000 प्रतियां